संक्षिप्त खबरें

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद। चार साल तक शादी का झांसा देकर एक युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने लक्ष्य शर्मा उर्फ निक्की को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शादी की बात कहने पर युवती के साथ मारपीट भी की। पुलिस के अनुसार, लखनऊ की रहने वाली युवती की मुलाकात चार साल पहले ओला पार्टी ऐप के जरिए मोदीनगर के सीकरी कलां निवासी लक्ष्य शर्मा से हुई थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और युवक ने शादी का वादा कर युवती से संबंध बनाए। बताया जा रहा है कि दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। हालांकि, जब युवती ने शादी की बात कही, तो आरोपी ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और शादी नहीं कर सकता। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने युवती के साथ मारपीट की। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि युवती की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी लक्ष्य शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला फिलहाल जांच के अधीन है।

यमुना सिटी में ट्रैक्टर बनाने वाली इकाई लगेगी

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने की इकाई लगेगी। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) ने न्यू होलेंड कंपनी को 100 एकड़ भूमि के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी कर दिया। यहां टैक्टर के इंजन समेत अन्य उपकरण तैयार होंगे। यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरके सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के पास निवेश के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। सोमवार को ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी न्यू होलैंड ने भी क्षेत्र में अपनी इकाई लगाने के लिए 100 एकड़ भूमि की मांग की। कंपनी क्षेत्र में 5000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। कंपनी को सेक्टर-8डी में भूमि देने पर सहमति बन गई है, जिसके बाद प्रस्ताव को इन्वेस्ट यूपी भेजा गया है, यहां से अनुमति मिलने के बाद कंपनी को जमीन आवंटित कर दी जाएगी। इससे पहले एस्कोर्ट कबौटा कंपनी को भी सेक्टर-10 में जमीन देने के लिए सहमति बन चुकी है। कंपनी को 200 एकड़ भूमि दी जाएगी। यह कंपनी क्षेत्र में टैक्टर के इंजन समेत अन्य उपकरण तैयार करेगी। कंपनी दो चरणों में करीब छह हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। अबतक क्षेत्र में ट्रैक्टर और इससे जुड़े उपकरण करने वाले दो कंपनियां आगे आ चुकी हैं। न्यू होलैंड का ग्रेटर नोएडा में भी एक प्लांट है।

तीन नशे के सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की इकोटेक-3 थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 4 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह गिरफ्तारी दिनांक 9 नवंबर 2025 को स्थानीय खुफिया तंत्र और बीट पुलिसिंग की सहायता से की गई। पुलिस का कहना है कि यह अभियान नशा तस्करी व नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान चिराग चौधरी उर्फ तनु, आकाश शर्मा और हरिओम शर्मा के रूप में हुई है। तीनों आरोपी नॉलेज पार्क-5 क्षेत्र में सक्रिय थे और उसी इलाके से इन्हें दबोचा गया। प्राथमिक जांच में पता चला है कि ये लोग बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से मादक पदार्थों की सप्लाई में शामिल थे। अभियुक्तों में पहले का नाम चिराग चौधरी उर्फ तनु है, जो ग्राम जलालपुर करीरा थाना शिकारपुर, बुलंदशहर का निवासी बताया जा रहा है। दूसरा अभियुक्त आकाश शर्मा भी जलालपुर करीरा का ही रहने वाला है, जबकि तीसरा अभियुक्त हरिओम शर्मा ग्राम निमचाना थाना अगौता, बुलंदशहर का निवासी है।

होटल के बाहर कार पार्किंग के विवाद में मारपीट

नोएडा। छिजारसी गांव में होटल के बाहर खड़ी कार हटाने के लिए कहने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। आरोपी पक्ष ने कार हटाने के लिए कहने पर होटल मालिक के भाई और स्टाफ से मारपीट की। आरोपी होटल की डीवीआर भी ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अलीगढ़ आमीपुर गांव निवासी जयकेश ने पुलिस को बताया कि छिजारसी गांव में उनका फोर्टिस इन के नाम से होटल है। उनके भाई रोदास और सचिन होटल की देखभाल करते हैं। रविवार रात करीब आठ बजे गांव के रवि गौतम के साथी कपिल और सुमित कार से आए। कार को होटल के बाहर खड़ा कर दिया। स्टाफ ने हटाने के लिए कहा तो आरोपियों ने अभद्रता की। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने अपने साथी मुन्नू को बुला लिया। तीनों ने मिलकर रोदास, सचिन और स्टाफ से मारपीट की। आरोपी होटल की डीवीआर को भी उठाकर ले गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने उन्हें एससी-एसटी ऐक्ट के केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले में शिकायत की पुलिस से की। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर कपिल, सुमित और मुन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक 3 कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुबह की सैर पर निकली महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुलेसरा निवासी दीपचन्द ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 अक्तूबर की सुबह करीब चार बजे वह अपनी पत्नी शीतल के साथ रोज की तरह टहलने निकले थे। हिंडन नदी का पुल पार करते ही एक अज्ञात वाहन ने शीतल को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाकर घायल को अस्पताल भिजवाया। यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केस दर्ज कराया है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

आईडिया टू मार्केट प्रतियोगिता आयोजित

नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को प्राचार्य डॉ. दिनेश चंद के संरक्षण में आईडिया टू मार्केट विषय पर स्टार्टअप प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम का निर्देशन लेफ्टिनेंट डॉ. सूक्ष्म रानी अनेजा एवं डॉ. प्रतिभा यादव ने किया। प्रतियोगिता में छात्रों ने नवाचार पूर्ण व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में समरीन ने प्रथम, नेहा शाक्या ने द्वितीय और शैली अग्निहोत्री ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रही।

तकनीकी विकास व रोजगार पर व्याख्यान

नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सोमवार को कंप्यूटर विज्ञान विभाग व कैरियर काउंसलिंग सेल द्वारा तकनीकी विकास एवं रोजगार विषय पर विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शिशुपाल सिंह व डॉ. गरिमा यादव ने किया। लोकभारती फाउंडेशन ग्रुप से आए विशेषज्ञों मुकेश मंडल और पूनम शर्मा ने विद्यार्थियों को नई तकनीक, कौशल विकास व रोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन दिया।

पांच और मरीजों में डेंगू की पुष्टि

नोएडा। जिले में सोमवार को डेंगू के 5 मरीज मिले हैं। विभाग की ओर से इन मरीजों के घर व आसपास के क्षेत्र में एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। मरीजों से संपर्क करके उनके स्वास्थ्य के बारे में भी पता किया जा रहा है। अब कुल मरीजों का आंकड़ा 615 तक पहुंच गया है। मलेरिया अधिकारी श्रुति कीर्ति वर्मा ने बताया कि डेंगू के सभी मरीज ठीक हैं। अधिकांश मरीज ठीक हैं। एक दो मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं।

डाक घर में सर्वर की समस्या से जूझे लोग

गाजियाबाद। मुख्य प्रधान डाकघर में सोमवार को एक बार फिर सर्वर ठप होने की समस्या से लोगों को जूझना पड़ा। डाकघर के खुलने के कुछ समय बाद से ही सर्वर डाउन हो गया, जिससे घंटों इंतजार के बाद भी लोगों के काम नहीं हो सके। नवयुग मार्केट स्थित मुख्य प्रधान डाकघर में बड़ी संख्या में लोग काम कराने के लिए पहुंचते हैं। यहां स्पीड पोस्ट, पार्सल भेजने से लेकर अन्य कार्यों से आते हैं। सोमवार को डाकघर खुलने के कुछ देर बाद से ही सर्वर डाउन हो गया। दोपहर तक यही स्थिति बनी रही।

मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे लोगों का पिकअप पुल से गिरा, तीन की मौत

- 18 लोग घायल जिनमें से दो की हालत नाजुक

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जित कर लौट रहे लोगों का पिकअप वाहन एक पुल की रेलिंग से टकरा गया, जिससे वाहन में बैठक छह लोग उछलकर 20 फुट नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरे। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए।

सहायक पुलिस आयुक्त ट्विंकल जैन ने बताया कि सेक्टर 113 थाने की पुलिस को रविवार की शाम को सूचना मिली कि हिंडन पुल और एफएनजी एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक पुल पर पिकअप वाहन रेलिंग से टकरा गया है और कई लोग पिकअप वाहन के नीचे दबे हैं।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है और 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई हैं। ये लोग हिंडन नदी में मूर्ति विसर्जित कर पिकअप वाहन से घर लौट रहे थे।

जैन ने बताया कि पिकअप वाहन में सवार सभी लोग मूलरूप से पश्चिम बंगाल के निवासी हैं और वर्तमान समय में नोएडा के सफार्बाद गांव में रहते हैं। वे रविवार को हिंडन नदी में काली माता की मूर्ति को विसर्जन करने गए थे।

उन्होंने बताया कि लौटते वक्त बिसरख पुल पार करके पिकअप वाहन एफएनजी एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे वाहन से टक्कर से बचने की कोशिश में पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गया और पलट गया। पुलिस ने घायलों को बिसरख, नोएडा व आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन लोगों दुर्योधन (52), वासुदेव (45) और रंजीत (55) की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों में से दो की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है।

सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मौके से वाहन हटवाया गया। उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक मृतकों के परिजनों ने इस मामले में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

पेयजल संकटः तीन दिन से पानी के तरस रहे लोग

- बोतल बंद पानी खरीद करना पड़ रहा गुजारा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शालीमार गार्डन स्थित डबल टंकी पार्क में खड़ी पानी की टंकी की पाइपलाइन बीते तीन दिन से क्षतिग्रस्त है। इसके चलते करीब 30 हजार लोग पेयजल के लिए तरस रहे है।

वहीं अर्थला, राजेंद्र नगर, डिफेंस कॉलोनी समेत अन्य इलाकों में दूषित जल आपूर्ति व कम दबाव से आपूर्ति की समस्या लगातार बनी हुई। इसके चलते लोगों को बोतल बंद पानी खरीद गुजारा करना पड़ता है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र के मोहन नगर जोन में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जल निगम ने 2019 में करीब 82 करोड़ की योजना बनाई थी।

इस योजना के तहत मोहन नगर जोन में कई जगह ऑवरहैड वाटर टैंक बनाए गये थे। लेकिन कई स्थानों पर बने टैंक से आपूर्ति आज तक भी शुरू नहीं हो सकी। इसके चलते आज भी लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।

> स्थानीय लोगों का कहना है कि डबल टंकी पार्क में स्थित टंकी की मैंन पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है। इसके चलते तीन दिन से पानी खरीदना पड़ रहा है। शालीमार गार्डन निवासी जुगल किशोर ने बताया कि तीन दिन से इलाकें में पानी की आपूर्ति बाधित है। किस वजह से बाधित है, इसकी सूचना भी जलकल विभाग ने नहीं दि। सोमवार को पता करने गये, तो देखा गया की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है। उन्होंने बताया कि जलकल विभाग को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। जिससे निवासी वैकल्पिक व्यवस्था बना सके।

शालीमार गार्डन में शुक्रवार को जर्जर टैंक का मलबा हटाने के दौरान पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। इसके चलते बीते तीन दिन से लोगों को पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ रहा है। तीन दिन से लगातार पानी खरीदने के वजह से लोगों का आर्थिक बजट बीगड़ गया है।

सर्राफा दुकान में चोरी करने वाला कर्मचारी गिरफ्तार, 2 लाख बरामद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा शॉपिंग प्लाजा स्थित एक सर्राफा दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना से संबंधित 2 लाख नगद भी बरामद किए हैं।

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि थाना इंदिरापुरम क्षेत्र के शिप्रा शॉपिंग प्लाजा स्थित वर्मा ज्वैलर्स के मालिक अभिषेक वर्मा ने 3 नवंबर को थाना इंदिरापुरम में तहरीर दी थी कि उनकी दुकान पर कार्यरत कर्मचारी रितिक वर्मा पुत्र माधव सिंह वर्मा दुकान से 2 सोने के कड़े और 1 ब्रेसलेट लेकर फरार हो गया है। इस तहरीर के आधार पर थाना इंदिरापुरम पर आरोपी रितिक वर्मा के खिलाफ धारा 316(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। 9 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम ने आरोपी रितिक वर्मा को सेक्टर-62 अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 2 लाख की नगदी बरामद की, जो चोरी गए सोने के गहनों को बेचने से प्राप्त हुई थी।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पिता की मैनपुरी में सुनार की दुकान है और उसे भी ज्वैलरी का काम आता है। नौकरी की तलाश में उसने अपना मोबाइल नंबर ₹जॉब है₹ ऐप पर डाला था। इसी माध्यम से उसे अभिषेक वर्मा की दुकान पर नौकरी मिली।

डीएम ने की जनसुनवाई, भू-माफिया पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में नियमित जनसुनवाई कर जनता की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का पूरा और सही समाधान किया जाए। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा।

जनसुनवाई में नगर निगम, पुलिस, जीडीए, विद्युत, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन शिकायतों का निरीक्षण संभव है, उन्हें तुरंत जाकर देखा जाए और निपटान के बाद शिकायतकर्ता से फीडबैक लिया जाए।

इस दौरान डासना गांव की चकमार्ग/चकरोड और सरकारी नाली की जमीन (खसरा 1382, 1383) पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली। जिलाधिकारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उन्होंने कहा कि भू-माफिया, भ्रष्टाचारी और धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी प्रकार की रिहायत नहीं दी जाएगी। जनसुनवाई में एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

चुनाव की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदान केंद्रों की आलेख्य सूची सार्वजनिक

गाजियाबाद। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार मांदड़ ने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान स्थलों की आलेख्य सूची जारी कर दी है। सूची 10 नवंबर से एक सप्ताह के लिए सार्वजनिक की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर किसी को सूची में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो वह 16 नवंबर तक लिखित रूप में जिलाधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी/तहसीलदार कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है और सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने में सहयोग करें और समय पर अपनी आपत्ति या सुझाव दें।

हापुड़ चुंगी पर ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

यातायात माह 2025 के तहत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को हापुड़ चुंगी चौराहे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात सचिदानंद बर्नवाल के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों वाहन चालकों के चालान काटे गए। 1 से 30 नवंबर तक गाजियाबाद में मनाए जा रहे 'यातायात माह' के तहत ट्रैफिक पुलिस लगातार सड़कों पर अभियान चला रही है। सोमवार को इस विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने स्कॉर्पियो, बाइक और स्कूटी समेत कई वाहनों की जांच की। इस दौरान न केवल आम जनता बल्कि पुलिसकर्मियों को भी ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया गया।

एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि गाजियाबाद पुलिस ने पिछले 10 दिनों में करीब 30 हजार से अधिक चालान जारी किए हैं। उन्होंने कहा, यातायात माह 2025 का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं को रोकना है। हम हेलमेट न पहनने, ओवरस्पीडिंग, गलत पार्किंग, सिग्नल जंपिंग और अन्य उल्लंघनों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने ने बताया कि सोमवार के अभियान में सैकड़ों वाहनों की जांच की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। कई वाहन चालकों से मौके पर जुमार्ना वसूला गया।

गौरतलब बात यह रही कि एडीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद बर्नवाल का दो दिन पहले ही शासन द्वारा लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया है। उन्हें एसएसएफ लखनऊ मुख्यालय में एडिशनल पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है। इसके बावजूद उन्होंने गाजियाबाद में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए यह अंतिम बड़ा अभियान चलाया। स्थानीय नागरिकों ने इस सघन चेकिंग अभियान की सराहना की, हालांकि कुछ लोगों ने भारी चालानों को लेकर नाराजगी भी जताई।

एबीवीपी के अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं ने लिया प्रशिक्षण

गाजियाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गाजियाबाद महानगर का अभ्यास वर्ग आठ और नौ नवंबर को नेहरू नगर के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। वर्ग का उद्घाटन प्रांत अध्यक्ष डॉ. घनश्याम वत्स, महानगर अध्यक्ष डॉ. राकेश राणा, महानगर मंत्री रिशांक भारद्वाज एवं विभाग संगठन मंत्री सिद्धार्थ स्वामी ने किया। अभ्यास वर्ग में गाजियाबाद महानगर के 125 कार्यकर्ताओं ने आठ सत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त किया। महानगर मंत्री रिशांक भारद्वाज ने बताया कि वर्ग में विद्यार्थी परिषद की कार्यपद्धति, सैद्धांतिक भूमिका, परिसर कार्य, प्रवास, बैठक, आयाम, कार्य गतिविधि जैसे विषयों पर विभिन्न सत्रों में प्रमुख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

पूर्व मंत्री डीपी यादव समेत नौ पर जमीन कब्जाने का मुकदमा दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डी.पी. यादव, उनकी पत्नी और बेटे समेत नौ लोगों के खिलाफ नोएडा के सलारपुर गांव में जमीन कब्जाने और धमकी देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। संपत्ति मालिक अशोक वाडिया की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद सेक्टर-126 थाने में रविवार को यह मामला दर्ज हुआ। वाडिया ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री डी. पी. यादव और उनके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के अनुसार, सलारपुर गांव में 14,000 वर्ग मीटर की जमीन 1989 में गोरखपुर के पवन जिंदल के स्वामित्व में थी। जिंदल ने उस समय अपना हिस्सा अशोक वाडिया को बेच दिया था, जबकि वाडिया ने बाद में अन्य सह-स्वामियों से भी शेष हिस्सा खरीद लिया। 2001 से यह जमीन उनके नाम पर दर्ज है।अशोक वाडिया का आरोप है कि अगस्त 2025 में पवन जिंदल ने पूर्व मंत्री डी. पी. यादव, सुरेश गोलय, देवेश यादव, रामफल शर्मा, उमलेश यादव, कुनाल यादव, रविंद्र सिंह, अभय उपाध्याय और कुछ अन्य के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया और विक्रय पत्र को आरोपियों के पक्ष में दिखाया ।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यमुना प्रसाद ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी संपत्ति विवाद को लेकर गोरखपुर निवासी पवन जिंदल ने 29 अक्टूबर को सेक्टर-49 थाने में वाडिया बंधुओं समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर 48 हजार रुपये ठगे, रिपोर्ट दर्ज

लोनी। लोनी थाना क्षेत्र की आशियाना सिटी कॉलोनी निवासी व्यक्ति से ठगों ने मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर 48 हजार रुपये ठग लिये। ठगों द्वारा दोबारा रुपये मांगे जाने पर व्यक्ति को अपने साथ हुई ठगी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। आशियाना सिटी कॉलोनी निवासी मोहसिन के फोन पर 28 सितंबर को अज्ञात नंबर से कॉल आई। उन्होंने बताया कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को लखनऊ के थाने में तैनात पुलिसकर्मी बताते हुए कहा कि उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई है। अचानक आई कॉल से वह भयभीत हो गये। जिस पर व्यक्ति ने मुकदमा खत्म कराने की बात करते हुए 48 हजार रुपये मांगे। उन्होंने व्यक्ति द्वारा भेजे गये बारकोड पर रुपये ट्रांसफर कर दिये। रुपये मिलने के बाद व्यक्ति ने दोबारा कॉल कर और धनराशि की मांग की।

ऑपरेशन क्लीनः मालवाहन निस्तारण पर आलोक प्रियदर्शी ने की बैठक

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

सोमवार को पुलिस लाइन्स स्थित परमजीत हॉल में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं यातायात कमिश्नरेट, आलोक प्रियदर्शी ने माल वाहनों के निस्तारण से संबंधित प्रचलित ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत बैठक आयोजित की।

इस बैठक में सभी थानों पर नियुक्त हेड मोहर्रिर मालखाना को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने मालवाहन निस्तारण प्रक्रिया को सुचारू और प्रभावी बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की।

कार्यक्रम में नोडल अपर पुलिस उपायुक्त और सभी जोन के नोडल सहायक पुलिस आयुक्त भी उपस्थित रहे। पुलिस अधिकारियों ने इस अभियान के महत्व और जनता को बेहतर सेवाएं देने में इसके योगदान पर जोर दिया।

आलोक प्रियदर्शी ने कहा कि ऑपरेशन क्लीन के तहत मालवाहन निस्तारण को और अधिक पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए थानों में नियमित निगरानी और समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा।

वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया रिफ्लेक्टिव टेप अभियान

गाजियाबाद। यातायात माह-2025 के तहत गाजियाबाद यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया। सोमवार को पुलिस उपायुक्त-यातायात के निदेर्शानुसार सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम जोन ने ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान कुल 180 वाणिज्यिक वाहनों पर निःशुल्क रिफ्लेक्टिव टेप लगवाई गई। ट्रक चालकों और पदाधिकारियों को रिफ्लेक्टिव टेप के महत्व और इसके फायदों के बारे में जागरूक किया गया। गोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम जियाउद्दीन अहमद, यातायात निरीक्षक अशेष कुमार, अजय कुमार, कुलदीप सिंह और अन्य यातायात अधिकारी उपस्थित रहे।

यातायात पुलिस के अनुसार, रिफ्लेक्टिव टेप लगाने से रात में वाहनों की दृश्यता बढ़ती है, जिससे सड़क पर दुर्घटनाओं का खतरा कम होता है। यह खड़े या खराब वाहनों की पहचान आसानी से करने में मदद करता है और कोहरा, धुंध, धूल, बारिश या कम दृश्यता वाली परिस्थितियों में भी वाहन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा, रिफ्लेक्टिव टेप से वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई स्पष्ट रहती है, जिससे सड़क पर सुरक्षा बढ़ती है और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होता है।

कॉप-30
गंभीर चुनौतियां

जब पर्यावरण की बात आती है, तो बहुत हो गया, ग्रह उबाल पर है, और जो एक बार मान लिया गया था वह अब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध नहीं है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जो खाना हम खाते हैं वह हमारे सबसे बुरे सपने में बदल रहा है। बढ़ते तापमान और प्रदूषित वातावरण का असर सभी पर पड़ रहा है, विश्व के नेताओं को छोड़कर, जो अब भी सोचते हैं कि पर्यावरण उनकी प्राथमिकता नहीं हो सकता। उनकी अदूरदर्शी दृष्टि ने हमें आगे बढ़ाया है और वे इनकार में ही रहते हैं।

बेलेम, ब्राजील में कॉप 30 नेताओं के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, एक महत्वपूर्ण क्षण होना चाहिए था - दुनिया के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने से पहले कार्य करने की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने के लिए एक विराम। लेकिन वह नहीं होने के लिए था। बल्कि इसकी शुरूआत डांट-फटकार से हुई, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं को अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता के लिए चेतावनी दी। गुटेरेस ने अपने भाषण में कहा, बहुत से नेता अपने निहित स्वार्थों के बंधन में बंधे हुए हैं। उनकी चेतावनी स्पष्ट थीः देश जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी पर हर साल लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं, वही ईंधन जो ग्रह को जला रहे हैं।

वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ग्रह अब 2030 के आसपास 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग सीमा को पार करने के लिए लगभग निश्चित है। फिर भी, उत्सर्जन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार देश - संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और भारत ,शिखर सम्मेलन से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थे।

केवल यूरोपीय संघ ने एक शीर्ष नेता भेजा। उनकी अनुपस्थिति ने सभा पर एक लंबी छाया डाली, जो वैश्विक एकता के परेशान करने वाले क्षरण को उजागर करती है जब सहयोग की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जैसे ही विश्व नेताओं ने अपनी झपकी ली, स्वदेशी समुदायों ने कार्यक्रम स्थल पर जंगलों और नदियों की सुरक्षा के लिए मार्च किया और गीत गाए।

कॉप30 के मेजबान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने देश को एक पुल और एक प्रकाशस्तंभ दोनों के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, अमेजॅन और अन्य महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के उद्देश्य से $125 बिलियन का फंड ₹ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी लॉन्च किया है।

शुरुआती प्रतिज्ञां जर्मनी, चीन, नॉर्वे और इंडोनेशिया से आई हैं, हालांकि पारंपरिक जलवायु सहयोगी यूनाइटेड किंगडम ने योगदान देने से इनकार कर दिया है। लूला की पहल शिखर सम्मेलन की क्षमता का प्रतीक हैः बहुपक्षवाद का एक नया मॉडल, जो वैश्विक दक्षिण के बीच सहयोग में निहित है और नीचे से ऊपर तक निर्मित है, जो शक्तिशाली देशों द्वारा निर्धारित नहीं है।

तीस वर्षों के जलवायु शिखर सम्मेलन के बाद - रियो से क्योटो तक, पेरिस से बेलेम तक - उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, जीवाश्म ईंधन का विस्तार बेरोकटोक जारी है, और जलवायु वित्त प्रतिबद्धताएं काफी हद तक पूरी नहीं हुई हैं। पर्यावरण पर वैश्विक कार्रवाई गायब है क्योंकि राष्ट्र अपने तथाकथित राष्ट्रीय हितों को पर्यावरण से ऊपर रखते हैं, जिससे यह अत्यधिक खतरे में पड़ गया है। विडम्बना कठोर है, नए तेल क्षेत्रों को लाइसेंस देते समय राष्ट्र ₹शुद्ध शून्य₹ का वादा करते हैं, वे विनाश का वित्तपोषण करते हुए एकजुटता की प्रतिज्ञा करते हैं।

कॉप 30 एक चेतावनी है, लेकिन हर कोई जागने से इनकार करता है। वे तर्क की पुकार से बच रहे हैं। जब वे जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अस्तित्व ही एकमात्र एजेंडा बन सकता है।

वह राजनेता जो संकट के समय मजबूती से खड़ा रहा

एक ऐसे भूले हुए प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि, जिन्होंने उथल-पुथल के बीच भारत को स्थिर किया, आर्थिक सुधारों की नींव रखी, और राजनीति से परे ईमानदारी और सेवा का जीवन जिया और उथल-पुथल के बीच एक राष्ट्र का नेतृत्व किया।

एच एन शर्मा

जब मुश्किल समय आता है, तो किस्मत नेतृत्व उन्हें सौंपती है जो शांत हिम्मत के साथ हालात संभाल सकते हैं - और अपनी असली ताकत दिखाते हैं। आज से 35 साल पहले, 10 नवंबर 1990 को, जब चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वह बहुत बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का समय था। उन्होंने ऐसे समय में देश की बागडोर संभाली जब देश कई संकटों से घिरा हुआ था। इनमें मंडल कमीशन के आरक्षण का बवाल, इराक द्वारा कुवैत पर हमले के बाद खाड़ी संकट के आर्थिक झटके, विदेशी मुद्रा भंडार में खतरनाक कमी, और राम मंदिर विवाद को लेकर बढ़ते तनाव शामिल थे।

चंद्रशेखर सरकार, भले ही कम समय के लिए थी, लेकिन उसने एक घायल देश पर मरहम का काम किया - दशकों के वित्तीय कुप्रबंधन से जूझ रही अर्थव्यवस्था के लिए यह एक तेज़ लेकिन ज़रूरी कदम था। कुछ अहम महीनों के लिए, उनकी सरकार ने स्थिरता बहाल करने का काम किया और चुपचाप उस चीज़ की नींव रखी जो बाद में भारत के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सुधारों में बदल गई।

लेकिन, सरकार को भी समय और राजनीतिक स्थिरता की ज़रूरत थी। इसके बजाय, राजीव गांधी द्वारा कांग्रेस का समर्थन अचानक वापस लेना ऐसा था जैसे पट्टी को बहुत जल्दी हटा देना, जिससे सरकार को देश की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक आपातकाल से निपटने का मौका नहीं मिला।

चंद्रशेखर जी की सरकार पर राजीव गांधी की जासूसी करने के आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उनमें कोई सच्चाई नहीं थी। ज़्यादा संभावना यह है कि राजीव गांधी, चंद्रशेखर के राम मंदिर विवाद को सुलझाने के लिए किए गए मुक्त और गोपनीय प्रयासों से परेशान थे, जो राष्ट्रीय सुलह की दिशा में एक बड़ी सफलता थी। जब गांधी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और आखिरकार चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। लेकिन यह चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने सबसे पहले वे कदम उठाए जिन्होंने भारत को आर्थिक पतन से बचाया और उसे उबारने के लिए मंच तैयार किया - यह एक ऐसी कहानी है जो अक्सर लुटियंस के गलियारों में फुसफुसाई जाती है लेकिन छिपाकर रखी जाती है, क्योंकि वह अपनी बड़ाई करने वालों में से नहीं थे। उन्हें श्रेय न मिलने का कारण शायद राजनीतिक पक्षपात और एक ऐसा नैरेटिव है जिसने 1989 की हार के बाद राजीव गांधी की छवि को सुधारने के लिए उनके संकट प्रबंधन को कम करके आंका। आर्थिक सुधारों की टाइमलाइन को देखते हुए, यह विश्वास करना मुश्किल है कि नरसिम्हा राव सरकार ने पद संभालने के सिर्फ 33 दिनों के भीतर इतने बड़े बदलावों की कल्पना की और उन्हें लागू किया होगा, जबकि पहले से ही कोई तैयारी न की गई हो - प्रभावी रूप से भारत को एक बंद अर्थव्यवस्था से एक खुली अर्थव्यवस्था में बदलने लगा।

एक पक्के समाजवादी होने के नाते, वह अच्छी तरह समझते थे कि 1990-91 के संकट के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है। उनकी सरकार के कदम का अर्थ नवउदारवाद की ओर मुड़ना नहीं था, बल्कि हालात के हिसाब से सोच-समझकर उठाया गया कदम था। पत्रकार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने चंद्रशेखरः द लास्ट आइकॉन में इस बलिदान को राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए वैचारिक आत्महत्या बताया। वह अक्सर कहते थे, मैंने मरीज़ को बचाने के लिए ज़हर पिया।

विचारधारा से ऊपर देश को प्राथमिकता देते हुए, उन्होंने भारत की भलाई के लिए अपने निजी सिद्धांतों का बलिदान दिया, इन सुधारों को विश्वास में असली बदलाव के बजाय इमरजेंसी सर्जरी के तौर पर देखा। उस समय जब प्रधानमंत्री कड़े कदम उठा रहे थे, विपक्ष ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश में दावा किया कि उन्होंने भारत का सोना बेच दिया है।

असल में, भारत सरकार ने शॉर्ट-टर्म फंड के लिए गारंटी के तौर पर बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 46.91 टन सोना गिरवी रखा था। यह एक निर्णायक कदम था जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुरक्षित किया और ढांचागत सुधारों के लिए समय दिया।

उनका उदय समाजवादी आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित था। बलिया के इब्राहिमपट्टी में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे, ग्रामीण अभाव और असमानता के शुरुआती अनुभवों ने जीवन भर के लिए एक वैचारिक संकल्प को जन्म दिया। शुरू में अकादमिक क्षेत्र की ओर आकर्षित होकर, उन्होंने राजनीति विज्ञान में पीएच.डी. के लिए दाखिला लिया था, लेकिन आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें रिसर्च छोड़कर पूरी तरह से सार्वजनिक सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए मना लिया। करिश्माई लेकिन नाटकीय राम मनोहर लोहिया के बजाय सिद्धांतवादी और बौद्धिक रूप से कड़े नरेंद्र देव के साथ जुड़ने का उनका चुनाव, दिखावे के बजाय असलियत को तरजीह देने की उनकी स्थायी पसंद को दर्शाता है।

उनकी विद्रोही भावना इमरजेंसी (1975-77) के दौरान सबसे ज़्यादा साफ़ दिखी। कांग्रेस महासचिव का पद संभालने के बावजूद उन्होंने इंदिरा गांधी के सत्तावाद का खुलेआम विरोध किया। सैद्धांतिक असहमति के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, जिससे एक आदर्श यंग तुर्क के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मज़बूत हुई - असहमति के एक ऐसे कट्टर समर्थक जो समझते थे कि सत्ता को चुनौती देना बेवफ़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची सेवा है। बाद में उन्होंने मशहूर होकर घोषणा की, ₹हम नेता के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ हैं जो नेताओं को अचूक बनाता है।₹

आज के भारत में, जहाँ युवाओं के लिए राजनीति में आना बहुत मुश्किल हो गया है, उनकी यह यात्रा प्रेरणा और सीख दोनों का काम करती है। वह उन उभरते नेताओं के लिए एक मिसाल हैं जो ईमानदारी के साथ असहमति जताने की हिम्मत रखते हैं, और उन अनुभवी राजनेताओं के लिए भी जो नैतिक विश्वास के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं।

उनकी हिम्मत सिर्फ़ पार्टी राजनीति तक ही सीमित नहीं थी; यह संसद में सबसे ज़्यादा साफ़ दिखाई देती थी। साथी और नागरिक, सब उन्हें सुनने के लिए रुक जाते थे, यह जानते हुए कि उनके शब्दों में साफ़गोई, विश्वास और एक अटल नैतिक दिशा थी। वह निडर होकर सच बोलते थे, सत्ता और लापरवाही दोनों को चुनौती देते थे। मुझे एक घटना साफ़ याद है जब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा देने के बाद किसी ने मज़ाक में उनके छोटे से कार्यकाल पर टिप्पणी की थी। उन्होंने अपने खास अंदाज़ में जवाब दियाः ''लोग माउंट एवरेस्ट पर रहने नहीं जाते, झंडा गाड़ने जाते हैं, जो मैं करके आ गया!''

अपने संपूर्ण सार्वजनिक जीवन में, वह लोगों से बहुत गहराई से जुड़े रहे - यह रिश्ता 1983 की उनकी भारत यात्रा में सबसे साफ़ तौर पर दिखा। छह महीनों में, उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक लगभग 4,260 किलोमीटर पैदल यात्रा की, प्रचार या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि भारत की असल ज़िंदगी को समझने के लिए, गाँव-गाँव, इंसान-इंसान से मिलकर।

और आज के नेताओं के उलट जो अपने लोगों के बीच जाने से पहले आराम और सुरक्षा पक्की करते हैं, उनकी पदयात्रा पूरी तरह से आम गाँव वालों पर निर्भर थी; उन्होंने और उनके साथियों ने गाँव वालों ने जो कुछ भी दिया - एक सादा खाना, आराम करने की जगह - उसे खुशी से स्वीकार किया, और इस यात्रा को देश के साथ एक ज़िंदा बातचीत में बदल दिया।

अपने लंबे और शानदार सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास और युवा सशक्तीकरण के लिए कई संस्थान स्थापित किए - देवस्थली विद्यापीठ, जय प्रकाश नारायण ट्रस्ट, भारत यात्रा केंद्र (भोंडसी, दिल्ली, मुंबई और अन्य जगहों पर केंद्रों के साथ), युवा भारत ट्रस्ट, सेंटर फॉर एप्लाइड पॉलिटिक्स, और इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। उन्होंने लगातार इस बात पर ज़ोर दिया कि इन ट्रस्टों को राजनीतिक धन से नहीं, बल्कि सार्वजनिक योगदान से फंड मिलता है, और ये हमेशा राष्ट्र की सेवा में रहने चाहिए।

इस विश्वास से प्रेरित होकर कि ये संपत्तियाँ व्यक्तियों के बजाय लोगों की सेवा के लिए हैं, उन्होंने 2000 के दशक की शुरुआत में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर अपनी संपत्ति को पारदर्शी सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में राष्ट्र को समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। दुख की बात है कि जब उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 2007 में उनका निधन हो गया, तो यह इरादा अधूरा रह गया। जब देश अपने सबसे सिद्धांतवादी नेताओं में से एक के निधन पर शोक मना रहा था, तो उनके कुछ करीबी लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और उन मुश्किल समय का फायदा उठाकर उन संपत्तियों पर कब्ज़ा करने की साज़िश रचनी शुरू कर दी, जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक भलाई के लिए सोचा था।

यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि इन लोगों ने कथित तौर पर ट्रस्ट के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ की - मिनट्स, डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर किया, और यहाँ तक कि स्व. प्रधानमंत्री, कुछ सांसदो और दूसरे न्यासियों के दस्तखत भी जाली बनाए। खासकर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की कथित जालसाजी, कानूनी और नैतिक दोनों तरह की वैधता को कमज़ोर करती है।

अधिकारियों की वर्षों की प्रशासनिक लापरवाही ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे न्यास की कई संपत्तियां लंबे समय से मुकदमों में फंसी हुई हैं। कुछ समर्पित लोगों को छोड़कर, आज बहुत कम लोग ऐसे लगते हैं जो सच में उनके आदर्शों और उनके बनाए संस्थानों को बचाने में दिलचस्पी रखते हैं। फिर भी, 45 से ज़्यादा सालों तक उनके करीबी होने के नाते, मैं इन ट्रस्टों को प्राइवेट कब्ज़े से बचाने और उनकी स्थायी विरासत - लोगों और देश के प्रति अटूट सेवा - को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ।

आज भी, उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि राजनीति, अपने सबसे अच्छे रूप में, शक्ति या संपत्ति के बारे में नहीं है, बल्कि सेवा के बारे में है - निस्वार्थ, दृढ़ और अटूट। वह कभी भी जाति या समुदाय की बांटने वाली राजनीति करने वालों में से नहीं थे, और शायद इसी वजह से वह ऐसा वोट बैंक नहीं बना पाए जो असलियत से ज़्यादा दिखावे को महत्व देता हो। हाल के सालों में, भारत रत्न जैसे सम्मान कभी-कभी राजनीतिक हिसाब-किताब को दिखाते हैं, जैसा कि कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह के मामलों में देखा गया है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस व्यक्ति ने भारत को सबसे मुश्किल राजनीतिक और आर्थिक बदलावों में से एक से रास्ता दिखाया, उसे न तो ठीक से याद किया गया और न ही उसकी सहनशक्ति और ईमानदारी के लिए उचित श्रेय दिया गया। जैसे-जैसे देश 2027 में उनकी 100वीं जयंती के करीब आ रहा है, भारत सरकार के लिए देश के प्रति उनकी जीवन भर की सेवा के लिए उन्हें भारत रत्न देना सर्वथा उचित होगा।

ग्रीन फाइनेंसः भारत की घरेलू प्रगति

भारत अपने जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। देश घरेलू वित्तपोषण को बढ़ावा देने, बाजार के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देकर हरित वित्त में अंतर को कम करने और ग्लोबल साउथ का समर्थन करने का प्रयास कर रहा है।

वैभव प्रताप सिंह
लेखक, एक संगठन के कार्यकारी निदेशक हैं।

जैसे जैसे दुनिया जलवायु संकट का सामना कर रही है, वित्त का मुद्दा तेजी से प्रमुख होता जा रहा है। पिछले दशक में, विषयगत वित्त, या विशिष्ट लक्ष्यों के लिए जुटाई गई पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें हरित वित्त एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा है। जलवायु वित्त, हरित वित्त का एक उपसमूह, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत शमन और अनुकूलन परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि हरित वित्त, 1970 के दशक में शुरू हुई सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश की एक प्राकृतिक प्रगति, पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी पहल का समर्थन करती है और इसका दायरा व्यापक है। विश्व स्तर पर, हरित निवेश के लिए वित्तीय प्रवाह बढ़ गया है। क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव के अनुसार, ग्रीन, सोशल, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड (जीएसएस+) बॉन्ड जारी करना 2024 के अंत तक 5.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया, पहली बार वार्षिक प्रवाह 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया। फिर भी, यह पूंजी विकसित बाजारों में केंद्रित है। विकासशील देशों में सीमा पार प्रवाह सीमित है, जो अक्सर व्यापक आर्थिक जोखिमों और भू-राजनीतिक प्राथमिकताओं से प्रभावित होता है।

अजरबैजान में कॉप29 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर आया, जहां वैश्विक जलवायु वित्त प्रतिबद्धता (मूल रूप से 2020 तक, लेकिन 2025 तक संशोधित) को मूल यूएसडी100 बिलियन वार्षिक लक्ष्य से संशोधित करके 2030 तक 300 बिलियन यूएसडी कर दिया गया था। फिर भी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अनुमान से पता चलता है कि दुनिया को 2030 तक सालाना 6.3 से 6.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, अकेले उभरते बाजारों और विकासशील देशों (चीन को छोड़कर) को इसकी आवश्यकता होगी। लगभग 3.1 से 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। विकासशील देशों के लिए चुनौती न केवल मात्रा में बल्कि वित्त की संरचना में भी है। ओईसीडी डेटा से पता चलता है कि 2022 में, विकासशील देशों के लिए प्रतिबद्ध सार्वजनिक निधि में 92 बिलियन अमरीकी डालर का, 69 प्रतिशत ऋण के रूप में, 28 प्रतिशत अनुदान के रूप में, और केवल 2 प्रतिशत इक्विटी के रूप में आया। इन प्रवाहों की वर्तमान ऋण-भारी प्रकृति ऊर्जा संक्रमण परियोजनाओं की लागत को बढ़ाती है, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा पहल, जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। विकासशील देशों में प्रतिस्पर्धी घरेलू मांगें विकसित देशों से अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता को उजागर करती हैं, जिससे संक्रमण और अधिक जटिल हो जाता है।

उपरोक्त आंकड़ों की समझ के माध्यम से, विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय विकास बैंकों ने कॉप29 में 2030 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए जलवायु वित्त में सालाना 120 बिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने के सामूहिक लक्ष्य की घोषणा की, जिसमें अनुकूलन परियोजनाओं के लिए 42 बिलियन अमरीकी डालर शामिल हैं, जो निजी क्षेत्र के जुटाव से अपेक्षित 65 बिलियन अमरीकी डालर से पूरक है। इन वैश्विक गतिशीलता के बीच, भारत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का प्रदर्शन कर रहा है। अपने नेट-शून्य दृष्टिकोण और जलवायु लचीलापन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, भारत को 2070 तक अनुमानित 10-20 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, मुख्य रूप से विकार्बनीकरणकारी बिजली, परिवहन और उद्योग के लिए, अनुकूलन लागत संभावित रूप से 2030 तक 57 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच जाएगी।

अकेले 2022 में, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और दक्षता परियोजनाओं के लिए घरेलू स्तर पर लगभग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए। भारत ने पहली बार जनवरी 2023 में सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किया, जिससे ऊर्जा-कुशल इलेक्ट्रिक इंजन जैसी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 8,000 करोड़ रुपये (लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) जुटाए गए, जो स्थायी वित्तपोषण के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूंजी जुटाने के अलावा, भारत बाजार के बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है जो हरित संक्रमण का समर्थन करता है। जलवायु-संरेखित गतिविधियों को वर्गीकृत करने के लिए एक मसौदा जलवायु वर्गीकरण जारी किया गया है, जिससे घरेलू हरित निवेशक आधार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 2026 तक प्रत्याशित एक घरेलू कार्बन बाजार, क्षेत्रीय डीकाबोर्नाइजेशन मार्गों की रूपरेखा तैयार करने में मदद करेगा, जबकि बैंकों के लिए जलवायु प्रकटीकरण और सेबी और आरबीआई के हरित बांड दिशानिर्देशों सहित नियामक ढांचे का उद्देश्य निवेशकों के विश्वास को मजबूत करना है।

विश्व स्तर पर, भारत ने समान वित्तीय प्रवाह की वकालत करने, बहुपक्षीय विकास बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्रणालियों में सुधारों पर दबाव डालने के लिए जी77+, ब्रिक्स और जी 20 में अपनी भूमिका का लाभ उठाया है।

हालाँकि, भारत के संक्रमण पथ में बहुत सारी चुनौतियां हैं। वित्त संबंधी कुछ चुनौतियों में अपेक्षाकृत उथला बांड बाजार शामिल है। ये चुनौतियां, बिजली वितरण कंपनियों की खराब वित्तीय स्थिति जैसे कार्यान्वयन मुद्दों के साथ मिलकर, देश में नई परियोजनाओं को अपनाने को सीमित कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय स्थिति पर बाधाएं और उपराष्ट्रीय संस्थाओं की साख जलवायु परिवर्तन के अलावा अन्य प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।

इन मुद्दों के समाधान के लिए सेक्टर-विशिष्ट नीति और वित्तीय सहायता पैकेज के साथ सभी क्षेत्रों में चरणबद्ध राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय नेट-शून्य रणनीति की आवश्यकता है। उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए व्यावसायिक मामले में सुधार, विशेष रूप से औद्योगिक डीकाबोर्नाइजेशन में, विदेशी जलवायु वित्त की व्यापक भागीदारी की अनुमति देगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से बांड-वित्तपोषित परिपक्व परियोजनाओं में पूंजी का पुनर्चक्रण घरेलू वित्तीय प्रवाह को और मजबूत कर सकता है।

भारत अपने जलवायु परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है। देश घरेलू वित्तपोषण को बढ़ावा देने, बाजार के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह को बढ़ावा देकर हरित वित्त में अंतर को कम करने और ग्लोबल साउथ का समर्थन करने का प्रयास कर रहा है। ये उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि भारत का नेट-शून्य संक्रमण प्राप्त करने योग्य और टिकाऊ दोनों है।

आप की बात

ट्रंप का बयान, खतरे का संकेत

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह बयान कि उन्होंने अपने युद्ध विभाग को अन्य देशों के समान स्तर के परमाणु परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं, विश्व समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ट्रंप ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के आरोप लगाए, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। हालांकि चीन, रूस और पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया, किंतु पाकिस्तान के परमाणु इतिहास को देखते हुए उसके दावों पर भरोसा करना कठिन है। 1996 में पारित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अनुसार, किसी भी देश को सैन्य या नागरिक उद्देश्य से परमाणु परीक्षण करने की अनुमति नहीं है। परंतु विडंबना यह है कि अमेरिका, जो इस संधि का प्रमुख प्रायोजक रहा है, ने आज तक इसे अनुमोदित नहीं किया है। ट्रंप का यह रवैया न केवल संधि की भावना के विपरीत है, बल्कि विश्व शांति की दिशा में वर्षों से किए जा रहे प्रयासों को कमजोर करता है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 1998 के बाद से परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लगा रखी है, परंतु उसका अतीत इस पर संदेह उत्पन्न करता है। परमाणु तकनीक को ईरान, लीबिया और उत्तर कोरिया जैसे देशों को बेचना यह दर्शाता है कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की कई बार अवहेलना की है।

– **विभुक्ति बुपक्या**, विधि छात्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय

सड़क और आकाशीय दुर्घटनाएं

देश में सड़क दुर्घटनाएं (नदुरबार ५६ बच्चों को ले जा रही स्कूल बस गिरी दो बच्चों के दर्दनाक मृत्यु हो गई, दो गंभीर हैं व शेष सभी घायल हो गए) तेजी से बढ़ रही हैं. वाहनों और सड़कों के रखरखाव पर ध्यान देना अतिआवश्यक है. ठीक इसी तरह वायुयानों में भी तकनीकी खराबियों की शिकायतें बढ़ती जा रही है. इनके भी दुरस्तीकरण पर ध्यान देना जरुरी है. सड़कों का विकास हो या रेल सुविधाओं में बढ़ौतरी की योजनाएं अथवा एयरपोर्ट्स के विकास की परियोजनाएं। नया अवश्य करते रहें किन्तु अब उससे भी ज्यादा जरुरी हो गया है जो चल रहा है उसके दुरूस्तीकरण/रखरखाव पर ध्यान देना. फिर चाहे मामले हवाई यात्रा से सम्बंधित हों या रेल यात्रा से अथवा रोड ट्रैवल्स से सम्बंधित. देश के तीनों मंत्रालयों को फिर चाहे तकनीकी सुधार हो या मानवीय (स्टाफ) परिचालन सम्बंधित समस्या अथवा रेल/सड़क/एयरपोर्ट की मरम्मत/रखरखाव के मामले सब पर उन्हें सख्त होने की जरुरत है. क्योंकि नवनिर्माण की जितनी ज्यादा जरुरत है उससे अधिक सुरक्षात्मक उपायों को करने की आवश्यकता है. ताकि यात्रियों की यात्राएं सुरक्षित व सुलभ हो सके और उनका विश्वास डगमगाए नहीं. क्योंकि जिनके परिजन शिकार होते हैं उनपर जो गुजरती है उसका दुखभरा एहसास वो ही भुगतता है. सरकार को चाहिए वो पहले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र ही जरुरी व सख्त कदम उठाये।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

तीसरी कक्षा से एआई शिक्षा

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और दूरदर्शी कदम उठाया जा रहा है। एनसीईआरटी की विशेष टीम सीबीएसई के सहयोग से तीसरी कक्षा से ही एआई की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह पहल न केवल समय की मांग है, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन भी है। वर्तमान समय में जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि, रक्षामें प्रवेश कर चुकी है, तब बच्चों को इसकी समझ प्रारंभिक स्तर से देना भविष्य निर्माण की ठोस नींव रखेगा। यदि तीसरी कक्षा से ही एआई की पढ़ाई शुरू की जाती है, तो बच्चों में विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान की क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। इससे वे केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके निमार्ता बनेंगे। एनसीईआरटी की यह पहल स्वागतयोग्य है क्योंकि यह बच्चों को बचपन से ही डिजिटल साक्षरता और तकनीकी समझ प्रदान करेगी। साथ ही, यह आवश्यक है कि नौवीं कक्षा से ही छात्रों को अपने विषय चयन की स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वे अपने रुचि क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकें। वर्तमान में लगभग तीन से चार वर्ष का समय सामान्य विषयों में व्यतीत हो जाता है। यदि यही प्रक्रिया नौवीं कक्षा से आरंभ की जाए, तो छात्र ग्रेजुएशन तक आते-आते अपने चुने हुए क्षेत्र में गहराई तक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इससे उनकी ऊर्जा और समय दोनों का सही उपयोग होगा।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

सेक्स वर्करों को सम्मान मिले

समाज की रचना तभी सशक्त होती है जब उसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान और अधिकार मिले। लेकिन दुख की बात है कि आज भी सेक्स वर्कर, जो समाज का हिस्सा हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। वे भी इंसान हैं, उनके अपने सपने, भावनाएं और जरूरतें हैं, फिर भी समाज उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा का पात्र बना देता है। सेक्स वर्कर कोई अपराधी नहीं हैं। कई बार परिस्थितियां, गरीबी या मजबूरी उन्हें इस पेशे में धकेल देती हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सम्मानजनक जीवन और सुरक्षा का अधिकार है। भारत के संविधान ने सबको समानता का हक दिया है, तो फिर सेक्स वर्कर इससे वंचित क्यों रहें? जरूरत है सोच बदलने की। समाज को समझना होगा कि पेशा किसी की इंसानियत को नहीं बदलता। सरकार को भी उनके पुनर्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा और बच्चों की शिक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। पुलिस और प्रशासन का रवैया भी मानवीय होना चाहिए, ताकि वे भयमुक्त होकर अपने अधिकारों की बात कर सकें। सेक्स वर्कर को सम्मान देना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे समाज की नैतिकता की पहचान है। जब हम किसी पेशे को नीचा नहीं दिखायेंगे तभी सच्चे अर्थों में समानता और मानवता स्थापित हो पायेगी।

– **संदीप कुमार**, मधुपुर, झारखंड

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।

खबर कोना

सीबीआइ ने 2.4 लाख रुपए रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली, 10 नवंबर (भाषा)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने दिल्ली पुलिस के एक सहायक उप-निरीक्षक को एक संपति की सत्यापन रपट देने के लिए कथित तौर पर 2.4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। ज्योति नगर पुलिस थाने में तैनात एएसआइ पाटिल कुमार ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में लंबित एक मामले में एक संपति के बारे में अनुकूल सत्यापन रपट जमा करने के लिए शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। कुमार ने कथित तौर पर धमकी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी गई, तो वह शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रपट पेश कर देंगे।

वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग उठाई

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

एच-फाइल्स में उजागर हुई वोट चोरी के खिलाफ एनएसयूआइ ने प्रदर्शन कर चुनाव आयोग और भाजपा से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा में भाजपा के पक्ष में मतदाता सूची में 25 लाख फर्जी नाम शामिल किए थे। उन्होंने दावा किया कि गांधी ने उन्हें खोज निकाला है और हर आठ में से एक वोट फर्जी था। एनएसयूआइ ने सोमवार को चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और हरियाणा की मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोपों पर चुनाव आयोग और भाजपा से जवाबदेही की।

हत्या के आरोप में तीन नाबालिग समेत पांच पकड़े

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

भलस्वा डेयरी थाना क्षेत्र में आठ नवंबर (शनिवार) को तीन नाबालिग समेत पांच आरोपियों ने एक युवक की पीट-पीट कर और चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। मृतक की पहचान करण के तौर पर की गई थी। मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल तीन नाबालिग समेत पांचों आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों की पहचान भलस्वा डेयरी निवासी मोहम्मद समीर और सुलेमान के तौर पर की गई है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने सोमवार को बताया कि अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक युवक को खून से लथपथ अवस्था में लाया गया था, जिसे चिकित्सकों ने पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली-आसपास की खबरें 5

प्रदूषण से बेहाल लोग दूसरे दिन भी सड़कों पर उतरे, कहा

सरकार के पास न कोई योजना है, न ही कोई दिशा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

राजधानी दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सोमवार को दूसरी बार बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। रविवार को जहां इंडिया गेट पर लोग जुटे थे, वहीं सोमवार को सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर युवाओं और नागरिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने 'स्वच्छ वायु हमारा मूलभूत अधिकार है' और 'हमें सांस लेने दो' जैसे नारे लगाते हुए दिल्ली सरकार पर प्रदूषण नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाया।

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेसी युवा और एनएसयूआइ के छात्र शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब पूरी दिल्ली धुंध की चादर में घिरी हुई है और हवा सांस लेने लायक नहीं बची, तब सरकार के पास न कोई ठोस रणनीति है और न ही कोई दिशा। युवाओं ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण के आंकड़ों से हेराफेरी कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 800 से भी ऊपर पहुंच चुका है, जो विश्व के सबसे गंभीर स्तरों में गिना जाता है।

मुख्यमंत्री आवास के पास सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को अवरोधक लगाकर रोक लिया, जिसके बाद वहां तनाव की स्थिति बन गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात है। राजधानी गैस चैंबर में बदल चुकी है और हमारी पीढ़ी राजनीतिक नाकामी की कीमत चुका रही है। मुख्यमंत्री के पास न दृष्टि है, न आपातकालीन योजना और न जवाबदेही। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे, और सरकार चुप है।

नई दिल्ली के शालीमार बाग में पानी का छिड़काव करती धुंध रोधी मशीन।

तापमान 2 से 5 डिग्री नीचे गिरने के आसार

दिल्ली में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, आने वाले चार से पांच दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। सोमवार को राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 27.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.9 डिग्री कम 10.4 डिग्री दर्ज किया गया।

आया नगर निगरानी केंद्र पर न्यूनतम तापमान सबसे कम 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पालम में अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 25 डिग्री दर्ज किया गया। हवाओं की रफ्तार सुबह 5-10 किलोमीटर प्रतिघंटा रही जो दोपहर में बढ़कर 15 किलोमीटर तक पहुंच गई।

धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, 'बेहद खराब' श्रेणी में हवा

राजधानी दिल्ली एक बार फिर जहरीली हवा की गिरफ्त में है। सोमवार को सुबह से ही शहर के कई इलाकों में घनी धुंध छाई रही, जिससे दृश्यता घट गई और वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 370 दर्ज किया गया। कई इलाकों में यह स्तर 'गंभीर' श्रेणी को भी पार कर गया। सीपीसीबी के 'समीर' एप के आंकड़ों के अनुसार बवाना में एक्यूआइ 411, वजीरपुर में 400, बुराड़ी और चांदनी चौक में 391, जबकि आनंद विहार में 379 और मुंडका में 376 दर्ज किया गया। जानकारों का कहना है कि हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि संवेदनशील लोगों को सांस लेने, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी शिकायतें हो रही हैं।

एमसीडी ने वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए बनाई योजना

राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए नगर निगम (एमसीडी) ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। निगम की ओर से बताया गया कि धूल और वाहन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए एंटी-स्माग गन और मैकेनिकल स्वीपर मशीनें शहर के विभिन्न इलाकों में तैनात की गई हैं। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। एमसीडी आगामी सदन बैठक में पार्किंग शुल्क को दोगुना करने का प्रस्ताव पेश करने जा रहा है, ताकि निजी वाहनों के उपयोग को हतोत्साहित किया जा सके और प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सके। अधिकारी के अनुसार यह प्रस्ताव सदन की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। निगम का कहना है कि वह दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

रोड शो

दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले एक रोड शो के दौरान उम्मीदवार के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता।

निगम उपचुनाव : बारह वार्डों में 133 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। अंतिम दिन तक कुल 133 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अधिकारियों के मुताबिक, नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय की गई है। इन सीटों पर मतदान 30 नवंबर को होगा।

जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक 15 नामांकन नारायणा वार्ड से दाखिल किए गए हैं, जबकि मुंडका, द्वारका और दक्षिणपुरी वार्डों में सबसे कम सिर्फ छह-छह उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। बाकी वार्डों में भी नामांकन को लेकर पूरे दिन गहमागहमी का माहौल रहा।

उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन के अंतिम दिन अपने-अपने वार्ड से पर्चा भरा और जीत का विश्वास जताया। नारायणा वार्ड से 'आप' प्रत्याशी राजन अरोड़ा पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने नामांकन से पहले मंदिर जाकर आशीर्वाद लिया। अरोड़ा ने कहा कि अगर ईश्वर ने चाहा तो हम यह चुनाव जीतेंगे।

जंतर-मंतर पर शख्स ने गोली मारकर की खुदकुशी

मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला था 40 वर्षीय लोकेंद्र, जुलाई से दिल्ली में रह रहा था

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 10 नवंबर।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार को एक व्यक्ति ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने वाले व्यक्ति की पहचान मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले 40 साल के लोकेंद्र के रूप में हुई। वह जुलाई से ही राष्ट्रीय राजधानी में था और अपनी बहन के लिए अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग कर रहा था। वह इससे पहले भी इस संबंध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर चुका था।

लोकेंद्र के बहनोई मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी पद पर काम करते थे। 2019 में लोकेंद्र के बहनोई का निधन हो गया। मृतक चाहता था कि सरकार उसकी बहन को अनुकंपा के आधार पर विभाग में नौकरी दे। जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि उन्हें सोमवार सुबह करीब सूचना मिली कि लोकेंद्र नामक व्यक्ति ने जंतर-मंतर पर खुद को गोली मार ली। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और घटनास्थल का मुआयना कराया गया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर मामले की जांच शुरू की गई। उधर परिजनों ने बताया कि वह रविवार शाम दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकला।

JINDAL STAINLESS

CIN: L26922HR1980PLC010901
Regd. Office: O.P.Jindal Marg, Hisar-125 005 (Haryana)
Ph. No. (01662) 222471-83, Fax No. (01662) 220499, Email Id. for Investors: investorcare@jindalstainless.com, Website: www.jindalstainless.com

EXTRACTS OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2025

(₹ in crores except per share data)

Sr. No.	Particulars	For the quarter ended			For the half year ended		For the year ended
		30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	31 March 2025
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Total income from operations	10,892.78	10,207.14	9,776.83	21,099.92	19,206.59	39,312.21
2	EBITDA *	1,387.85	1,309.80	1,186.49	2,697.65	2,398.21	4,666.63
3	Net profit for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	1,061.01	969.05	834.27	2,030.06	1,720.21	3,346.02
4	Net profit for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	1,078.42	969.05	834.27	2,047.47	1,720.21	3,338.96
5	Net profit for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	807.92	714.66	609.42	1,522.58	1,255.49	2,499.72
6	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	815.91	713.57	606.63	1,529.48	1,253.79	2,537.18
7	Paid up equity share capital (face value of ₹2/- each)	164.74	164.73	164.69	164.74	164.69	164.73
8	Other equity	17,914.54	17,249.22	15,296.87	17,914.54	15,296.87	16,523.21
9	Securities premium account	4,120.52	4,120.10	4,102.26	4,120.52	4,102.26	4,119.73
10	Net worth	18,079.28	17,413.95	15,461.56	18,079.28	15,461.56	16,687.94
11	Paid up debt capital #	99.00	99.00	474.00	99.00	474.00	286.50
12	Outstanding redeemable preference shares	-	-	-	-	-	-
13	Debt equity ratio	0.37	0.35	0.41	0.37	0.41	0.38
14	Earning per share (EPS) (face value of ₹2/- each) a) Basic b) Diluted (EPS for the period not annualised)	9.80 9.78	8.67 8.66	7.42 7.41	18.47 18.44	15.29 15.28	30.42 30.41
15	Capital redemption reserve	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
16	Debenture redemption reserve #	-	-	-	-	-	-
17	Debt service coverage ratio	4.92	2.94	4.39	3.71	4.80	3.26
18	Interest service coverage ratio	10.49	9.57	7.78	10.02	8.28	8.11

* EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation & amortization and other income
# Listed debenture

Notes

The above is an extract of the detailed format of quarterly/half yearly/yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015) ['SEBI (LODR)']. The full format of the standalone and consolidated quarterly/half yearly/yearly financial results along with other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (LODR) are available on the Company's website: (www.jindalstainless.com) and on the websites of Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Ltd. (www.nseindia.com). The same can be access by scanning the QR Code provided below.

Standalone financial information of the Company, pursuant to regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) :

(₹ in crores)

Particulars	For the Quarter ended			For the half year ended		For the year ended
	30 September 2025	30 June 2025	30 September 2024	30 September 2025	30 September 2024	31 March 2025
	Unaudited			Unaudited		Audited
Total income from operations	10,880.89	10,340.51	9,745.65	21,221.40	19,330.55	40,181.68
EBITDA *	1,059.82	1,047.79	1,006.92	2,107.61	2,011.32	3,905.20
Profit before tax (before exceptional items)	866.91	862.78	792.82	1,729.69	1,581.08	3,367.63
Profit before tax (after exceptional items)	866.91	862.78	792.82	1,729.69	1,581.08	3,519.18
Profit after tax	643.89	641.64	589.29	1,285.53	1,167.61	2,711.19

Place: New Delhi
Date: 10 November 2025

By Order of the Board of Directors
For Jindal Stainless Limited

Tarun Kumar Khulbe
Chief Executive officer, Chief Financial Officer
and Whole Time Director

GREENPANEL
— MDF KA DOOSRA NAAM —

Greenpanel Industries Limited

पंजीकृत कार्यालय: डीएलएफ डाउनटाउन, ब्लॉक 3, प्रथम तल, डीएलएफ फेज 3, सेक्टर 25ए, गुरुग्राम - 122002 | फोन: +91 124 4784600
CIN : L20100HR2017PLC127303
E-mail: investor.relations@greenpanel.com, Website: www.greenpanel.com

30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक अवधि के लिए असंपरीक्षित वित्तीय परिणाम

ऑडिट समिति की सिफारिशों के आधार पर, ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ("कम्पनी") के निदेशक मंडल ने अपनी बैठक, जो 10 नवंबर, 2025 को आयोजित हुई, में 30 सितंबर, 2025 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक अवधि के असंपरीक्षित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित किया। इन परिणामों की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों, मेसर्स एस. एस. कोठारी मेहता एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के अनुसार की गई है।

उपरोक्त वित्तीय परिणाम, साथ ही वैधानिक लेखा परीक्षकों की सीमित समीक्षा रिपोर्ट, https://www.greenpanel.com/financial-results/ पर उपलब्ध हैं और नीचे दिए गए क्विक रिस्पॉन्स कोड को स्कैन करके भी देखे जा सकते हैं।

Scan the QR Code to view the results on the website of the company

Scan the QR Code to view the results on the website of the BSE

Scan the QR Code to view the results on the website of the NSE

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते ग्रीनपैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
शोभन मित्तल
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईएन: 00347517
स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 10 नवंबर, 2025

यदि उपरोक्त प्रकटीकरण के संबंध में कोई प्रश्न हों, तो कृपया हमसे संपर्क करें:
investor.relations@greenpanel.com
फोन: +91 -124 478 4600

MDF I Pre-Laminated MDF I Wooden Flooring I Plywood

कल्पमेधा

इससे फर्क नहीं पड़ता कि किन्हीं वजहों से आप गिर गए।
मायने यह रखता है कि क्या आप उठते हैं!
–विंस लोंबार्डी

आतंक का चेहरा

आतंकवाद वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए साजिशों के नए-नए जाल बुनते हैं, जिन्हें भेद पाने में सुरक्षा एजंसियों को भी कड़ी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है। सुरक्षा एजंसियों को इसी तरह के एक अंतरराज्यीय आतंकी संजाल का भंडाफोड़ करने में सफलता मिली है, जिसमें आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस साजिश की भयावहता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आरोपियों के ठिकानों से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं। यानी वे किसी बड़े खौफनाक हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस का दावा है कि आतंकियों का यह तंत्र पाकिस्तान की धरती से संचालित होने वाले जैश-ए-मोहम्मद और आइएसआइएस से संबंधित अंसार गजवातुल-हिंद से जुड़ा हुआ था, जो जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय था। सवाल है कि इस गिरोह से जुड़े लोग इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ और हथियार जमा करने में कैसे कामयाब हो गए? सुरक्षा और खुफिया एजंसियों को इनकी गतिविधियों की भनक पहले क्यों नहीं लग पाई?

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस तथा केंद्रीय एजंसियों के साथ विशेष अभियान चलाकर इस आतंकी तंत्र का पर्दाफाश किया है। खास बात यह है कि इस गिरोह के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें एक विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक और एक चिकित्सक भी शामिल हैं। साफ है कि आतंकी संगठन पढ़े-लिखे लोगों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, ताकि किसी हिंसक वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में से एक के दिल्ली से सटे फरीदाबाद स्थित किराए के मकान से 360 किलोग्राम ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील पदार्थ का मिलना कई सवाल खड़े करता है। एनसीआर में जगह-जगह पुलिस की ओर से सुरक्षा नाके लगाए गए हैं, इसके बावजूद विस्फोटक पदार्थ की इतनी बड़ी खेप आखिर वहां कैसे पहुंचाई गई? क्या खुफिया और सुरक्षा एजंसियों की जांच का व्यवस्थागत तंत्र इतना कमजोर है कि वह वास्तविक समय पर आपराधिक गतिविधियों को पकड़ पाने में सक्षम नहीं है?

गिरफ्तार किए गए आठ लोगों में से सात कश्मीर के हैं, जबकि एक उत्तर प्रदेश का निवासी है। सुरक्षा अधिकारियों का दावा है कि जांच में दो आरोपियों के मोबाइल फोन में पाकिस्तान के कई नंबर पाए गए हैं। जाहिर है कि वे पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में थे। यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि गिरफ्तार सभी आरोपी स्थानीय हैं, मगर उनके पास चीनी स्टार पिस्तौल, एके-56 एवं एके क्रिंकाव राइफल जैसे हथियार और इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ कहां से आए? प्रारंभिक जांच में यह बात भी सामने आई है कि धन का लेन देन करने और साजो-सामान की व्यवस्था के लिए यह गिरोह गुप्त माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा था। सामाजिक और धर्मार्थ कार्यों की आड़ में पेशेवर तथा शैक्षणिक तंत्र के जरिए धन जुटाया जाता था। मगर ऐसा कैसे संभव हुआ कि खुफिया और सुरक्षा एजंसियों को इसकी पहले कोई भनक नहीं लग पाई। जाहिर है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कहीं न खामियां व्याप्त हैं, जिन्हें दुरुस्त किए जाने की जरूरत है।

हादसों की जड़ें

लगभग सभी बड़े हादसों और उनमें लोगों के हताहत होने की घटना के बाद राहत तथा मुआवजे के लिए सरकार की ओर से औपचारिक कदम उठाए जाते हैं। सबका ध्यान आमतौर पर इस बात पर टिका रहता है कि किस वाहन के चालक की गलती थी या कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं थी। मगर कई बार हादसों की वजहें ऐसे पहलू में भी छिपी होती हैं, जिन पर ध्यान देना लोग जरूरी नहीं समझते और न ही उसे अहम बिंदु माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ वैसे ही कारणों को चिह्नित करने की जरूरी पहल की है। अदालत ने सोमवार को राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए सड़क हादसे के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से दो हफ्तों के भीतर दुर्घटना के कारणों पर विस्तृत जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इसमें संबंधित महकमों को फलोदी से गुजरने वाले राजमार्ग पर ढाबों की संख्या के साथ-साथ राजमार्ग की स्थिति और वहां सड़क रखरखाव के लिए ठेकेदार द्वारा अपनाए गए मानदंडों के बारे में भी बताना होगा।

गौरतलब है कि उस हादसे में सड़क किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे यात्रियों से भरा टेम्पो ट्रेवलर टकरा गया था, जिसमें दस महिलाओं और चार बच्चों सहित पंद्रह की जान चली गई थी। दरअसल, लंबी दूरी की यात्रा के लिए निर्बाध सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और रखरखाव के लिए उच्चतम मानदंडों को बनाए रखना जरूरी नहीं समझा जाता। जबकि हर कुछ दूरी पर टोल संग्रह केंद्रों पर वाहन चालकों से शुल्क वसूलने में कोई रियायत नहीं बरती जाती। दूसरी ओर, ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, जिनमें किसी ढाबे के पास सड़क किनारे खड़े बड़े वाहन पर सही समय पर नजर न पड़ने की वजह से पीछे से कोई अन्य वाहन आकर टकरा जाता है और नाहक ही लोगों की जान चली जाती है। सवाल है कि जब तेज रफ्तार और निर्बाध सफर के लिए सड़कें बनाने का दावा किया जा रहा है, तो उसे हर लिहाज से सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फलोदी में हुए हादसे का स्वतः संज्ञान लेकर दरअसल हादसों के वास्तविक कारणों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की है।

समाज में वैचारिक क्रांति की दरकार

वर्तमान में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्मगुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है।

जगमोहन सिंह राजपूत

लोकतंत्र में चुनाव जब केवल सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने तक सीमित हो जाएं, तब देश के प्रबुद्ध वर्ग का कर्तव्य और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है। भाषण चाहे राजनीति से जुड़ा हो या फिर किसी अन्य विषय से, उसमें समस्या और समाधान दोनों हों, तभी वह सार्थक कहलाता है। स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में 11 सितंबर 1893 को अपने ऐतिहासिक भाषण में अमेरिका के लोगों को 'बहनों एवं भाइयों' कहकर संबोधित किया, तो वहां मौजूद भीड़ इन शब्दों को सुनकर आह्लादित हो उठी। वे सनातन धर्म के प्रतिनिधि थे, जिसमें हर पंथ ससम्मान और समकक्ष स्वीकार्य था। ऐसा कोई बंधन नहीं था कि अमुक पूजा पद्धति को ही अपनाएं, या किसी एक धार्मिक पुस्तक को पूरी तरह स्वीकार करें। यह सभ्यता और सनातन ज्ञान परंपरा हर प्रकार की जकड़न से मुक्त थी। आप पूजा करें या न करें, ईश्वर को मानें या न मानें, जब तक आप समाज की मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं, आप हिंदू हैं। ऐसा कोई बंधन नही था कि आपका आस्तिक होना आवश्यक है!

स्वामी विवेकानंद ने सनातन संस्कृति की विश्व-व्यापकता को जिस ढंग से प्रस्तुत किया, वह अद्वितीय था। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि जब अब्राहमी धर्म के लोग यहां आए, तो भारत के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने धर्म के अनुसार परंपराओं एवं मान्यताओं को आगे बढ़ाने का हर एक अवसर दिया। पारसी मत को मानने वालों का यहां आना इसलिए ज्यादा महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वे यहां आकर पूरी तरह घुलमिल गए। आज उनकी संख्या कम होने के बावजूद उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाता है। देश के निर्माण में उन्होंने जो योगदान दिया है, वह किसी अन्य धर्म से कम नहीं है। भारत में इस समय सभी बड़े पंथों के अनुयायी रहते हैं और उन सभी ने यहां की सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

इस समय देश में सांप्रदायिक माहौल को लेकर विचार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है की यदि आजादी के बाद यानी भारत विभाजन के पश्चात के समय पर दृष्टि डाली जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में धार्मिक ढांचे और सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर समस्याएं और चिंता बनी हुई हैं। इनका समाधान निकालना केवल सरकार का नहीं, बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। इसमें धर्मगुरुओं तथा बौद्धिक वर्ग की भूमिका अहम हो सकती है। इस कर्तव्य को पहचानना और उसे अंगीकार कर समाधान में लगना हर भारतीय का उत्तरदायित्व है। इस कार्य को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

यह सवाल भी अहम है कि क्यों सामुदायिक मनमुटाव का लाभ उठाने के लिए अनेक राजनीतिक दल अपने-अपने ढंग से अग्रसर हो गए हैं। वे दलगत हित और चुनाव जीतने जैसे सामान्य लक्ष्य को राष्ट्रहित के ऊपर प्राथमिकता देने में नहीं हिचक रहे हैं। इस क्रम में समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसी भी सामान्य नागरिक को यह लगता है कि जिस जाति प्रथा को समाप्त करने में महात्मा गांधी और बाबा साहब आंबेडकर जैसे अनेक मनीषियों ने जीवन लगा दिया,

उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाले आज पूरे प्राणप्रण से जाति प्रथा के आधार पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रहित पर इसका दीर्घकालिक और नकारात्मक असर पड़ता है, इसलिए सांप्रदायिक और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी की भागीदारी आवश्यक

> **कुछ रूढ़िवादी विचार समय के साथ इतने सशक्त हो जाते हैं कि उनसे पार पाने में सदियां लग जाती हैं। लंबे संघर्ष के पश्चात भारत के संविधान में जाति प्रथा और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, फिर भी यह सब समाप्त नहीं हुआ है। देश के युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि छोटे-छोटे राजनीतिक लक्ष्य सामने रखकर दलगत लाभ लेने के लिए समाज को सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित करने वालों से सावधान रहें। देश की भावी पीढ़ी को खुद को इस सबसे बचाना होगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करना होगा।**

है। समाज में एक आंतरिक वैचारिक क्रांति लानी ही होगी और ऐसा तभी संभव होगा, जब हर तरुण, युवा और बुद्धिजीवी इस विचार में रच-बस जाएं कि देश तभी समृद्ध होगा, जब यहां अटूट भाईचारा और पंथिक सद्भाव सारे विश्व को दिखाई देगा! देश तभी सुरक्षित होगा, जब अपने अनुभव से सीख कर हर भारतवासी यह अंतर्मन से स्वीकार करेगा कि देशहित सर्वोपरि है और बाकी सब कुछ इसके बाद ही आता है। इसके लिए बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक तैयारी आवश्यक है।

यह सब कैसे संभव होगा, इसकी सीख स्वामी विवेकानंद हमें बहुत पहले यह कह कर दे गए थे कि बड़े काम में बहुत समय तक लगातार और महान प्रयत्न की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे कार्य में कुछ लोग विफल भी हो जाएं, तो भी उसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। संसार का यह नियम है कि अनेक लोग नीचे गिरते हैं और उनमें से कुछ फिर उठ खड़े हो जाते हैं। कितने ही दुख आते हैं, कितनी ही भयंकर कठिनाइयां सामने उपस्थित होती हैं। स्वार्थ और अन्य बुराइयों का मानव-हृदय में घोर संघर्ष होता है और तभी आध्यात्मिकता की अग्नि से इन सबका विनाश होने लगता है। इस जगत में भलाई का मार्ग सबसे दुर्गम एवं पथरीला है। कितने लोग सफलता प्राप्त करते हैं और कितने विफल हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हजारों ठोकरें खाने के बाद चरित्र का निर्माण होता है।

कुछ रूढ़िवादी विचार समय के साथ इतने सशक्त हो जाते हैं कि उनसे पार पाने में सदियां लग जाती हैं। लंबे संघर्ष के बाद भारत के संविधान में जाति प्रथा और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, फिर भी यह सब समाप्त नहीं हुआ है। देश के युवाओं को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि छोटे-छोटे राजनीतिक लक्ष्य सामने रखकर दलगत लाभ लेने के लिए समाज को सांप्रदायिक और जातिवाद के आधार पर विभाजित करने वालों से सावधान रहें। देश की भावी पीढ़ी को खुद को इस सबसे बचाना होगा और सामाजिक सद्भाव बढ़ाने की चुनौती को स्वीकार करना होगा। इस संसार में प्रकृति ने जो सृजन किए हैं, उसमें विविधता की सुंदरता को समझने के लिए वह सदा प्रेरित करती है। पंथिक विविधता को भी उसमें निहित सुंदरता को ध्यान में रखकर समझना होगा। ऐसा कौन-सा धर्म या पंथ है, जो सत्य, शांति, अहिंसा, प्रेम और सदाचार की बात नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता है? जरूरत है तो इन तत्त्वों को अपने जीवन में आत्मसात करने और उनके अनुरूप आचरण की।

स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन को रास्ता दिखाया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि पूजाघर में जाना तब प्राथमिकता में नहीं है, अगर उसी समय किसी अकिंचन व्यक्ति को आपकी सेवा की आवश्यकता हो। दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा से कम नहीं है। उन्होंने यह सीख भी दी थी कि यदि आप मानते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर विद्यमान है, तो फिर हमारे पास दूसरे की सहायता करने का अधिकार रह ही नहीं जाता है, हम केवल सेवा ही कर सकते हैं।

जहां तक समस्याओं के समाधान के कौशल की बात है तो शिक्षण संस्थाओं से इसकी शुरुआत की जा सकती है। राष्ट्र और मानव प्रेम की भावनाओं के साथ यदि व्यक्तित्व विकास होगा, तो निश्चित रूप से देश में सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता के साथ-साथ सेवा भावना बढ़ेगी। इसी से भविष्य में देश की प्रगति और विकास को गति मिलेगी तथा भारत विश्व में अपना अपेक्षित स्थान प्राप्त कर सकेगा।

दुनिया मेरे आगे

वैरागी गान

राजेंद्र मोहन शर्मा

यह एक गहन आंतरिक शांति का क्षण है, जहां चेतना अपने चिर-परिचित बाहरी शोरगुल से पूरी तरह विमुख हो चुकी है। वह अनवरत कोलाहल, वह संसार की अंतहीन रार और द्वेष, अब केवल एक दूरस्थ, महत्त्वहीन प्रतिध्वनि मात्र है। इस बोध ने अब जड़ें जमा ली हैं कि संघर्ष और खींचतान पूरी तरह से निरर्थक हैं। जीवन की यह अवधि कितनी छोटी, कितनी अनिश्चित है! जब अगले ही क्षण का कोई आश्वासन नहीं है, और यह भौतिक काया, जो मात्र पंचतत्त्वों का अस्थायी जमावड़ा है, किसी भी पल मिट्टी में मिल जाने को तैयार है, तो फिर किस बात का स्वामित्व और कैसी होड़? इस नश्वर देह के विसर्जन की आतुरता ही अब एकमात्र अटल सत्य बनकर उभरती है।

दृष्टि का यह नवीन स्वरूप सामान्य नहीं है। यह वह गहन अंतर्दृष्टि है जो हर कण और हर गति में मृत्यु की अनिवार्यता का दर्शन कराती है। यह निराशा नहीं, बल्कि परम यथार्थ का स्वीकरण है। यह दुनिया कोई स्थिर ठिकाना नहीं, बल्कि एक तीव्र गति से ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ पिंड है। इस अनंत यात्रा में, जीवन का चक्र लाखों वर्षों से निरंतर चल रहा है- आगमन और प्रस्थान की यह शृंखला अनवरत है। हम इस विराट क्रम में मात्र एक क्षणिक उपस्थिति हैं। यह महाकाल का विशाल फलक, वर्तमान के छोटे-छोटे संकटों को पूरी तरह से विस्मृत कर देता है। अब किस बात पर व्यथित होना, किस क्षणभंगुर उपलब्धि पर अहंकार करना? यह विशालता ही मन को समस्त विकारों से मुक्त कर देती है।

> **एक दिन वह परम स्पष्टता आएगी, जब जीवन की सारी भागदौड़, सारे संघर्ष, सारी उपलब्धियां- सब कुछ एक छोटे-से बालक के खेल जैसा प्रतीत होगा। जब यह अंतिम बोध पूर्ण हो जाएगा, तब यह जबरन ठहरना समाप्त हो जाएगा। फिर न तो किसी चीज की चाहत रहेगी और न ही किसी बंधन का भय। केवल शुद्ध सत्ता का अनुभव शेष रह जाएगा।**

साक्षी भाव का यह अनवरत अभ्यास एक दिन चेतना को उस उच्च, तटस्थ बिंदु पर स्थापित करता है, जहां से संसार एक सुनियोजित, पर क्षणिक, नाटक की तरह दिखाई देता है। यहां सुख और दुख का एक शाश्वत संगीत बजता है, जीवन अपने पूरे उल्लास और विषाद के साथ प्रवाहित होता है। मगर देखने वाला अब इस प्रवाह में डूबता नहीं, वह केवल एक उदासीन द्रष्टा बनकर खड़ा रहता है। वासनाएं और इच्छाएं, जो कभी अस्तित्व का आधार थीं, अब ज्ञान के अथाह सागर में विसर्जित हो चुकी हैं। उनके अवशेष तक शेष नहीं हैं, केवल एक नितांत खालीपन है जो स्वयं में पूर्णता है। यह परम शांति की स्थिति है, जहां 'चाहिए' का भाव 'है' के बोध में रूपांतरित हो जाता है।

फिर भी, एक अद्भुत और विरोधाभासी अवरोध है- इस अनुभव की पराकाष्ठा के बावजूद, इस भौतिक आयाम में जबरदस्ती ठहरने का एक आत्म-निर्णय। आत्मा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। वह फल पक चुका है जो वृक्ष से विलग होना चाहता है, लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे रोके हुए है। यह ठहरना अंतिम परीक्षा है, खुद को परखने की। यह सुनिश्चित करने की कि क्या बंधन का एक भी धागा शेष है! क्या इस जगत के आकर्षणों के प्रति कोई सूक्ष्म आसक्ति अभी भी भीतर सुलग रही है?

मानवीय अस्तित्व की वे गहनतम अभिलाषाएं, जो हमें भौतिक सुरक्षा, इंद्रिय सुख, सामाजिक स्वीकृति, पद और परिवार का कवच देती हैं, क्या उनमें कहीं कोई रंच मात्र लगाव बचा है? जब व्यक्ति ने अनुभव की हर ऊंचाई को छुआ हो, भोग के हर चरम शिखर पर जाकर स्वयं को परखा हो, तब यह आंतरिक निरीक्षण और भी आवश्यक हो जाता है। हर कर्म, हर अनुभव एक गहन आत्म-विश्लेषण का विषय बन गया है। उसने भोगा, पर भोगते हुए भी एक निर्लिप्त चेतना को निरंतर जीवित रखा। उस चेतना ने भोग की हर सीमा का मूल्यांकन किया। उसने मापा कि इस आनंद की वास्तविक कीमत क्या है, इस सुख के साथ जुड़े हुए दुख के आयाम क्या हैं, और इस क्षणभंगुरता की अंतिम सीमाएं कहां तक हैं।

यह रुकना वास्तव में उस आखिरी गांठ को खोलने जैसा है। यह जानते हुए कि संसार का यह आकर्षण एक दिन स्वयं ही टूट जाएगा, इस क्षणिक फांस को सहर्ष भोगना ही अंतिम लीला है। यह बोध कि भोग के माध्यम से ही त्याग की पूर्णता प्राप्त होती है, व्यक्ति को इस खेल का आनंद लेने की अनुमति देता है। वह निरंतर जागृत रहता है, निरंतर देखता रहता है, और अपने अनुभवों की गहराई में गोता लगाता है। चाहे वह प्रेम की मधुरता हो या जीवन का कठोर संघर्ष, हर अनुभव का विश्लेषण करते रहना ही अब एकमात्र अनिवार्य कर्म है। यह विश्लेषण ही वह ज्ञान है जो आखिर मुक्ति की ओर ले जाता है। यह अंतर्दृष्टि ही जीवन के सारे जटिल और गंभीर पहलुओं को सहज बना देगी।

एक दिन वह परम स्पष्टता आएगी, जब जीवन की सारी भागदौड़, सारे संघर्ष, सारी उपलब्धियां- सब कुछ एक छोटे-से बालक के खेल जैसा प्रतीत होगा। जब यह अंतिम बोध पूर्ण हो जाएगा, तब यह जबरन ठहरना समाप्त हो जाएगा। फिर न तो किसी चीज की चाहत रहेगी और न ही किसी बंधन का भय। केवल शुद्ध सत्ता का अनुभव शेष रह जाएगा। यह आत्म-बोध ही वह परम गंतव्य है, जहां पहुंचकर द्रष्टा और दृश्य का भेद मिट जाता है, और संपूर्ण अस्तित्व एक लय में समाहित हो जाता है। यह है उस अनादि यात्रा की अंतिम कड़ी, जो भौतिकता से परे ले जाती है।

यह वह महाप्रस्थान है, जो किसी शोरगुल या घोषणा के बिना होता है। यह भीतर का गान है, जो केवल द्रष्टा को सुनाई देता है। यह उस विरक्ति की धुन है जो परम सत्य के समक्ष बज उठी है।

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

कैंसर का जोखिम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, कैंसर अभी भी मानव जीवन के लिए सबसे घातक चुनौतियों में से एक है। वर्ष 2022 में विश्वभर में लगभग दो करोड़ नए मामले सामने आए और 97 लाख लोगों की मृत्यु हुई। वैश्विक स्तर पर कैंसर की घटनाओं की दर वर्ष 1990 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 220.6 थी, जो 2023 में घट कर 205.1 पर आ गई और अनुमान है कि 2025 तक यह 192.9 तक पहुंच जाएगी। यह संकेत है कि दुनिया के कई हिस्सों में रोकथाम, प्रारंभिक जांच और उपचार-सुविधाओं ने असर दिखाया है। वैश्विक संकेतक सुधार दर्शा रहे हैं, लेकिन भारत में कैंसर के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। 'लांसेट की ग्लोबल बर्डन आफ डिजीज' रपट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में लगभग 15 लाख नए मामले सामने आए। वर्ष 1990 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर कैंसर की घटनाएं 84.8 थीं, जो 2023 में बढ़ कर 107.2 हो गईं। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक कैंसर-मामलों और मृत्यु-संख्या में तेजी से वृद्धि देखी जाएगी। हर आठ भारतीयों में से एक के जीवनकाल में कैंसर होने की संभावना इस खतरे की व्यापकता को रेखांकित करती है।

– मोहम्मद जुबैर, मुखर्जीनगर, दिल्ली

आपदा और चुनौती

सुनामी जैसी आपदाएं अपने विनाशकारी प्रभाव और अचानक आने वाली तीव्रता के कारण वैश्विक चिंता का विषय रही हैं। दुनियाभर में प्रति वर्ष नवंबर में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक तैयारी और आपदा प्रबंधन की कुशल रणनीति द्वारा नुकसान को रोकना है। सुनामी की गति इतनी तेज होती है कि प्रतिक्रिया का समय अत्यंत कम मिलता है। इसलिए समय पूर्व चेतावनी, तटीय आबादी को प्रशिक्षित करना, बचाव मार्गों का निर्माण और स्थानीय प्रशासन की तत्परता बेहद आवश्यक है। जापान जैसे देशों ने आपदा प्रबंधन को अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल कर यह साबित किया है कि तैयारी जितनी मजबूत होगी, हानि उतनी कम होगी। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय सहित महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए एहतियाती उपाय बेहद जरूरी है।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

राजनीति में अपराध

अपराधियों और राजनीतिज्ञों को एक दूसरे की सरपरस्ती अब कोई रहस्य एवं रोमांच का विषय नहीं है, जितना लोग-बाग इसे बनाते हैं। दरअसल, यह राजनीतिकों में घोर प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। अगर इसमें बलिदान, त्याग और सेवा का भाव निहित होता, तब शायद पार्टियों को उम्मीदवार तय करने में भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता और न ही राजनीति के अपराधीकरण से आगे बढ़ कर मामला अपराध के राजनीतिकरण तक जाता। इस तरह के अपराध पनपने देने के लिए राजनीति जिम्मेदार है। कुछ सीमा तक इसकी जड़ें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामाजिक बुनावट में भी समाई हैं। सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है? विकास और व्यवसाय का सुगम मार्ग हो। कानून के प्रति सम्मान का भाव हर आम-खास, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिसकर्मियों, राजनीतिक वर्ग और व्यवसायियों आदि में हो, न कि मजबूरी में इसका पालन करें। हालांकि यह तब होगा जब कानूनी जटिलताएं कम होंगीं।

– मुकेश कुमार मनन, पटना

जागरूकता के संकेत

इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मतदान में कई कीर्तिमान बने। इस पर पूरे देश की नजर थी। विदेशों में भी इस चुनाव को लेकर चर्चा होती रही। चुनाव पूर्व जिस तरह दल दूसरे दलों पर जुबानी हमले कर रहे थे, उससे यही लग रहा था कि चुनाव के दौरान हिंसा होगी। मगर सख्त इंतजामों के कारण प्रथम चरण का मतदान शांति से निपट गया। वहीं मतदान फीसद में अद्भुत वृद्धि देखी गई। कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार मतदान 64.66 फीसद तक चला गया। साल 2020 में पहले चरण में 56.1 फीसद मतदान हुआ, लेकिन उस समय पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे जबकि इस बार 121 सीट पर चुनाव हुए हैं। करीब सभी मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई। इस बार बिहार में सत्ता हथियाने के लिए कई नई राजनीतिक दलों का जन्म हुआ।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

संपादकीय जागरण
मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 : मार्गशीर्ष कृष्ण - 7 वि. 2082
हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है

आतंक की आहट

पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों से आतंकियों के कई गुटों का जो भंडाफोड़ हुआ, वह चिंतित करने वाला ही है। यह गंभीर चिंता की बात है कि पढ़े-लिखे और यहां तक कि डाक्टर डिग्री धारक भी आतंक के रास्ते पर चल रहे हैं। इसी के साथ यह संतोष की बात भी है कि वे पुलिस और खुफिया एजेंसियों की निगाह में आ जा रहे हैं। इसके बाद भी यह कल्पना सिहरन पैदा करती है कि यदि खतरनाक इरादों से लैस इन आतंकियों को समय रहते पकड़ा न जाता तो वे किसी बड़ी तबाही का कारण बन सकते थे। इसका एक संकेत गत दिवस दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में जोरदार धमाके से मिलता है। कई लोगों को हताहत करने वाले इस धमाके की प्रकृति और उसकी तीव्रता किसी आतंकी करतूत की ओर ही इशारा कर रही है। इसी कारण इस घटना की जांच में आतंक निरोधक एजेंसियां भी जुट गई हैं। इस दहशत पैदा करने वाली घटना के ठीक पहले गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने जिन तीन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, उनमें एक हैदराबाद का डाक्टर है। उसके दो साथी उत्तर प्रदेश के हैं। उनके पास से तीन पिस्टल और कारतूस के साथ घातक जहर राइसिन बनाने वाली सामग्री मिली है। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के अलावा जम्मू-कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने तीन डाक्टरों समेत सात ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फरीदाबाद में करीब तीन हजार किलो विस्फोटक जमा कर रखा था। इनमें एक महिला डाक्टर भी है। शेष में मौलवी और छात्र हैं। इनके पास से राइफल, पिस्टल, टाइमर आदि भी मिले हैं। साफ है कि अब यह धारणा सही नहीं रही कि अशिक्षित और गरीब मुस्लिम युवा ही आतंक की ओर उन्मुख होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों का देश और दुनिया का अनुभव यही बताता है कि अब पढ़े-लिखे मुस्लिम युवा आतंकी बनना अधिक पसंद कर रहे हैं। वे केवल आइएस, अलकायदा, जैश और लश्कर जैसे खूंखार आतंकी संगठनों से ही नहीं जुड़ रहे हैं, बल्कि खुद के आतंकी गुट बनाने का भी दुस्साहस कर रहे हैं। इसकी अनदेखी न की जाए कि बीते दिनों कर्नाटक की जेल में बंद एक आतंकी मोबाइल से फंड जुटाते मिला तो ग्रेटर नोएडा में एक अन्य मजहबी उन्माद भड़काने वाली किताबों का प्रकाशन करते हुए। यह सही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि मजहब की आड़ लेकर भी आतंक के रास्ते पर चला जा रहा है। एक के बाद एक कई आतंकी गुटों के भंडाफोड़ के बीच दिल्ली की घटना केवल यही नहीं बताती कि सुरक्षा एजेंसियों को और अधिक सतर्क रहना होगा, बल्कि इसकी भी मांग करती है कि मुस्लिम समाज का राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्तर पर नेतृत्व करने वाले यह देखें कि किन कारणों से उनके युवा आतंक की राह पर चल रहे हैं?

सतर्कता जरूरी

दिल्ली में लाल किले के पास विस्फोट में नौ लोगों की मौत और 21 अन्य के घायल होने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विस्फोट के कारणों को लेकर अभी पुलिस के स्तर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह धमाका जिस तरह से हुआ है और इसका असर जितना बड़ा है, उससे इसके आतंकी धमाका होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर एनएसजी और एनआइए टीम को बुलाने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने इस धमाके की सभी दृष्टिकोण से जांच किए जाने की बात कही है।

> यदि पुलिस हाई अलर्ट पर थी और आतंकी नापाक हरकत को अंजाम देने में सफल हुए, तो यह दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है

दिल्ली के साथ लगते फरीदाबाद में विगत दो दिनों में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी के पास से 2900 किग्रा अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। जिस दिन सुबह इस बरामदगी को लेकर फरीदाबाद पुलिस प्रेस वार्ता करती है, उसी दिन शाम को दिल्ली में धमाका हो जाता है। इस बरामदगी के साथ ही दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पुलिस को हाई अलर्ट पर हो जाना चाहिए था। यदि पुलिस साथ लगते शहर में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी के बाद भी हाई अलर्ट पर नहीं थी, तो यह निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है। यदि पुलिस हाई अलर्ट पर थी और उसके बाद भी आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने में सफल हो गए, तो यह दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर और भी बड़ा सवाल है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकारें पर्याप्त गंभीरता का परिचय दे रही हैं?

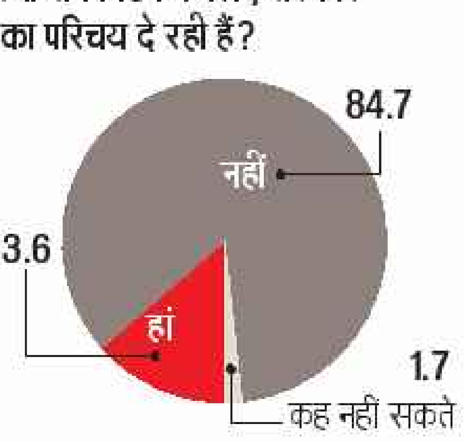

आज का सवाल

क्या शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य किया जाना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

भूटान को चीनी चंगुल से बचाने की चुनौती

श्रीराम चौलिया

तिब्बत में चीन के अतिक्रमण और नेपाल में चीन के विस्तार को देखते हुए भारत के लिए भूटान को चीनी महत्वाकांक्षाओं से बचाकर रखना अनिवार्य है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिन के लिए भूटान के दौरे पर हैं। भूटान क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी है, परंतु इसका सामरिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह चीनी कब्जे वाले तिब्बत और भारत के बीच ऊंचे हिमालयों में स्थित महत्वपूर्ण मध्यवर्ती देश है। गत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी का वहां चार बार जाना और इसी तरह भूटान के प्रधानमंत्रियों और राजाओं का लगातार भारत में आगमन का क्रम दर्शाता है कि इस संवेदनशील रिश्ते को उचित ही सर्वोच्च राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है। भूटान अगर कमजोर और बेसहारा बन जाए तो विस्तारवादी चीन न केवल उसे निगल जाएगा, बल्कि भारत की सीमा पर एक और मोर्चा खोल देगा। 1950 के दशक में तिब्बत में चीन के अतिक्रमण और वर्तमान में नेपाल में चीन के विस्तार को देखते हुए भारत के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भूटान को चीनी महत्वाकांक्षाओं से बचाकर रखे। एक अद्वितीय हिमालयी बौद्ध राष्ट्र को आक्रामक महाशक्ति चीन के जबरन कब्जे से बचाना कोई किताबी या सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है। 'सीलाइट' नामक अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान के अनुसार हाल के वर्षों में चीन ने भूटान की पारंपरिक सीमाओं के भीतर कम से कम 22 कृत्रिम गांव बसाए हैं, जो इस छोटे से देश के लगभग दो प्रतिशत भूभाग पर कब्जा हैं। इन चीनी बस्तियों में सड़कें, सैन्य चौकियां और प्रशासनिक केंद्र भी शामिल हैं, जिससे जमीनी स्तर पर ऐसे नए तथ्य अंकित कर दिए गए हैं, जिन्हें नकारना मुश्किल है।

भूटान के साथ सीमा वार्ताओं के अंतर्गत चीन ने नए दावे भी पेश किए हैं, ताकि भूटान की संप्रभुता धीरे-धीरे घिस जाए और चीनी सेना भारत की सीमाओं को घेर ले। 2017 में डोकलाम में अवैध सड़क निर्माण का प्रयास चीन की दीर्घकालिक योजनाओं का नमूना था। इसी खतरे को रोकने के लिए भारतीय सेना ने 73 दिन तक चीनी फौज से आमना-सामना किया था। अंततः चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था।

भूटान के अस्तित्व के लिए चीन के बढ़ते खतरे के चलते भारत भूटानी सेना के लिए रक्षा उपकरणों के साथ प्रशिक्षण की सुविधाएं बढ़ा रहा है। 2007 में संशोधित भारत-भूटान स्थायी मैत्री संधि के अनुसार दोनों देश "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों" का मुकाबला करेंगे। चीन द्वारा भूटान में घुसपैठ करने और उसे अपने अधीन लाने के मंसूबों के कारण प्रतिरक्षा भारत-भूटान संबंधों का प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। चूंकि भूटान को भारतीय सैन्य सहायता संवेदनशील मामला है, इसलिए उसके बारे में सार्वजनिक रूप से घोषणाएं नहीं होती हैं। इस सबके बाद भी मोदी सरकार भूटान के उत्तर और पूर्व में मंडरा रहे खतरे से अवगत है और उसे जरूरी संसाधन उपलब्ध करा रही है।

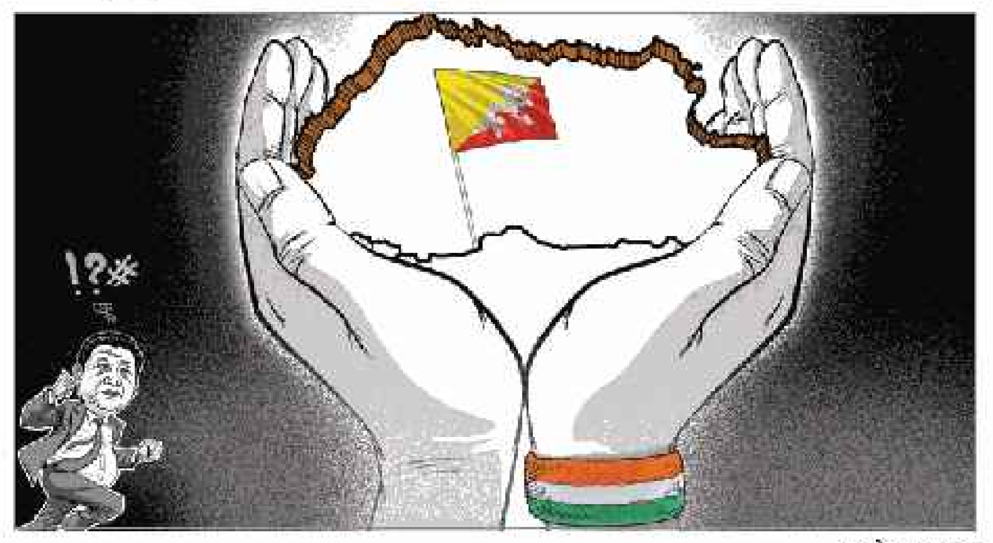

अवधेश राजपूत

भूटान को अपने प्रभाव में लाने के इरादे से चीन उसे आर्थिक प्रलोभन भी दे रहा है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसियों में भूटान एकमात्र देश है, जो चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे में भूटान की आर्थिक प्रगति, ढांचागत सुधार और आधुनिकीकरण के प्रति भारत का विशेष उत्तरदायित्व है। भूटान की अपनी चौथी यात्रा में मोदी भारत की मदद से बने पुनतसंगचु जलविद्युत परियोजना का अनावरण करेंगे, जिससे भारत को भूटान से बिजली का निर्यात और भूटान में भारतीय कंपनियों का निवेश बढ़ेगा। भारत अपने उत्तर-पूर्वी राज्य असम के कोकराझार से भूटान के प्रतिष्ठित 'न्यू गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी' तक 58 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का भी निर्माण कर रहा है, जिससे आपसी कारोबार और पर्यटन का विकास होगा।

अंतरिक्ष उपग्रहों से लेकर वित्तीय प्रौद्योगिकी तक भारत उभरते क्षेत्रों में भूटान की मदद कर रहा है, ताकि उसके विभिन्न राजनीतिक समूह और सामाजिक वर्ग भारत के साथ मित्रता के ठोस लाभ को महसूस कर सकें। वर्षों से भूटान भारतीय सहायता का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। 2025-26 के भारतीय बजट में उसके लिए 2,150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। मोदी की भूटान यात्रा दुनिया को याद दिलाएगी कि भारत दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए प्रमुख साझीदार बनने के लिए तत्पर है और इस मामले में चीन से प्रतिस्पर्धा करने से नहीं कतराएगा।

विकास और प्रतिरक्षा के अलावा भारत ने संस्कृति और आध्यात्मिकता को अपनी भूटान नीति का तीसरा स्तंभ बनाया है। भूटान की इस यात्रा के दौरान मोदी एक मठ में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा करेंगे, जिन्हें उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से वहां भेजा गया है। इसके अलावा भारत की ओर से बौद्ध आध्यात्मिक नेता और भूटानी राष्ट्र के संस्थापक झाबद्रुंग नामग्याल की प्रतिमा भी भूटान को प्रदर्शन के लिए दी गई है।

भूटान की आठ लाख से भी कम आबादी अत्यंत धर्मपरायण है और अपनी अद्वितीय बौद्ध विरासत के संरक्षण के प्रति सचेत है। एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में उभरकर भारत भूटान के लोगों का दिल और दिमाग जीत रहा है। बिना कहे ही सब समझते हैं कि जहां नास्तिक चीन ने अधिकृत तिब्बत में बौद्ध धर्म के विरुद्ध सांस्कृतिक नरसंहार किया, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक भारत ने सदियों पुरानी आध्यात्मिक कुंजी को संरक्षित किया। इसीलिए मोदी अपनी इस भूटान यात्रा में एक विशेष 'वैश्विक शांति प्रार्थना' समारोह में भी भाग ले रहे हैं, जो दोनों देशों की सरकारें साझा तौर पर आयोजित कर रही हैं। भारत की रणनीति इन सभी आयामों पर ध्यान देने की है, ताकि भूटानी समाज में कोई भारत विरोधी गुट न सक्रिय होने पाए। यह संयोग नहीं कि भूटान भारत का सबसे स्थिर दक्षिण एशियाई पड़ोसी है। संगठित भारत-विरोधी तत्वों की अनुपस्थिति के फलस्वरूप भूटान में सामाजिक समरसता में खलल नहीं पड़ा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की तरह भूटान में भी चीन घुसपैठ करके भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। भविष्य में चीनी कारस्तानियों से निपटने के लिए भारत को भूटानी विशिष्ट वर्ग के साथ-साथ आम लोगों से भी घनिष्ठ संबंध बनाने होंगे। मोदी बार-बार भूटान जाते रहे तो दोनों देशों की मित्रता यूं ही सुदृढ़ होती रहेगी।

(लेखक जिंदल स्कूल आफ इंटरनेशनल अफेयर्स में प्रोफेसर और डीन हैं)
response@jagran.com

बैंकों से बेहतर है सहकारी नेटवर्क

अनुरोध ललित जैन

जब निजी बैंक पीछे हट रहे हों और सार्वजनिक बैंक थक चुके हों तो समाधान सहकारिता ढांचे में है

बढ़ई, कुम्हार, सुनार और दर्जी आदि 18 पारंपरिक पेशे से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक नई उम्मीद लेकर आई थी। इसके तहत इन्हें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक औजार और बिना जमानत के छोटा ऋण देने का प्रविधान है, ताकि वे आज की तकनीकी दुनिया में फिर से खड़े हो सकें। सितंबर 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू हुई इस योजना का लक्ष्य देश के ग्रामीण जीवन से संबंधित पारंपरिक पेशे थे। दो साल बाद कागज पर तो आंकड़े उत्साहजनक दिखते हैं, क्योंकि इस योजना के तहत तीन करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हुए हैं, पर सच्चाई कुछ और है। अब तक सिर्फ 4.65 लाख कारीगरों को 4,000 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 2,200 करोड़ रुपये ही वास्तव में वितरित हुए और मात्र 224 करोड़ रुपये की वापसी हुई है। पंजीकरण और वास्तविक कर्ज वितरण के बीच यह फासला सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि संरचनात्मक कमी दर्शाता है। यह बताता है कि भारत में आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं का सबसे बड़ा रोड़ा बैंकिंग व्यवस्था ही है।

निजी बैंक सरकार का विरोध नहीं कर रहे, बस नियमों का चतुराई से पालन कर रहे हैं। आरबीआइ ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वे अपनी कुल ऋण पुस्तिका का 40 प्रतिशत कृषि, लघु उद्योग क्षेत्र के साथ कमजोर वर्गों को दें। निजी बैंक प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य को पूरा करने के बजाय प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र खरीद लेते हैं। ये प्रमाणपत्र वे उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से खरीद सकते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य से अधिक ऋण वितरित किया हो। कुछ बैंक अपने दायित्व को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के माध्यम से पूरा करने का दावा करते हैं। कागज पर वे नियम पूरा करते हैं, लेकिन हकीकत में विश्वकर्मा ऋण देने के मामले में निजी बैंकों का रिकार्ड निराशाजनक है। पीएम जन धन योजना में भी निजी बैंकों की हिस्सेदारी मुश्किल से तीन प्रतिशत है। निजी बैंकों का तर्क है कि दो लाख रुपये का एक छोटे कारीगर को दिया गया ऋण उतने ही कागजी काम और लागत मांगता है, जितना 20 लाख का कार लोन, पर मुनाफा बहुत कम। कारीगरों के पास न जमानत होती है, न डिजिटल ऋण इतिहास, जिससे जोखिम बढ़ जाता है। सरकारी गारंटी भी केवल आंशिक नुकसान कवर करती है। ऐसे में शेयरधारकों से संचालित संस्थानों के लिए यह काम आकर्षक नहीं है। इसके उलट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लगभग पूरा बोझ उठाते हैं-चाहे जन धन, मुद्रा या विश्वकर्मा जैसी योजनाएं हों, लेकिन सीमित स्टाफ और सख्त नियामक बोझ के कारण उनकी क्षमता सीमित है। जब कर्ज अटकता है तो जनता के सामने दोष बैंक या सरकार, दोनों को झेलना पड़ता है।

सहकारिता कुंभ का शुभारंभ करते अमित शाह • एएनआइ

जब निजी बैंक पीछे हट रहे हों और सार्वजनिक बैंक थक चुके हों, तो समाधान सहकारिता ढांचे में है। यह भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद वित्तीय व्यवस्था है। सहकारी ऋण समितियां और जिला सहकारी बैंक 'सामाजिक गारंटी' पर काम करते हैं, जहां हर सदस्य की गारंटी दूसरा सदस्य देता है। यह सामुदायिक भरोसा उन कारीगरों के लिए अधिक उपयोगी है, जिनके पास औपचारिक रिकार्ड नहीं है। इन संस्थाओं में डिफाल्ट दर औसतन दो प्रतिशत के आसपास रहती है, जो अधिकांश सूक्ष्म ऋणों से बेहतर है। कई राज्यों में सहकारी संस्थाएं डेरी, हैंडलूम और ग्रामीण उद्यमों में गहराई से जुड़ी हैं। उन्हें स्थानीय व्यापार और मौसमी आय का अनुभव है। एक कुम्हार या बढ़ई भले फिनटेक न समझे, सहकारी संस्था को समझता है। यदि विश्वकर्मा योजना को इन सहकारी नेटवर्क से जोड़ा जाए तो यह योजना वास्तव में जन-संचालित बन सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश के बुनकर समाज या गुजरात की डेरी सहकारिताओं में हुआ है।

सरकार को चाहिए कि सहकारी और जिला केंद्रीय बैंकों को निर्धारित बैंकों की तुलना में बेहतर ऋण गारंटी दे, क्योंकि इनका सामाजिक आधार अधिक गहरा है। नाबार्ड या सिडबी के माध्यम से कारीगर ऋणों के लिए पुनर्वित्त सुविधा खोली जा सकती है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का डिजिटलीकरण 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। इन्हें भी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। जो सहकारिताएं ऋण वितरण और वसूली में अच्छा प्रदर्शन करें, उन्हें ब्याज सब्सिडी या प्रशासनिक सहायता दी जा सकती है। सरकार एनईएफटी/आरटीजीएस शुल्क, केवाईसी सत्यापन और क्रेडिट ब्यूरो फीस जैसी छोटी, पर बार-बार आने वाली लागतें भी सहकारिताओं के लिए माफ कर सकती है। एक विशेष कोष बनाकर उन सहकारिताओं के प्रशासनिक खर्च का कुछ हिस्सा वापस किया जा सकता है, जो वित्तीय समावेशन के लक्ष्य पूरे करती हैं। यह सच है कि कई सहकारी संस्थाएं पूंजी की कमी, कमजोर प्रबंधन या डिजिटलीकरण की कमी से जूझ रही हैं, पर इन्हें सुधारा जा सकता है। पारदर्शी आडिट, पदाधिकारियों का रोटेशन एवं सरकार से कार्यशील पूंजी सहयोग जैसी पहलें भरोसा बहाल कर सकती हैं। प्रशिक्षण शिविर सहकारिता प्रबंधन में ईमानदारी और दक्षता बढ़ाएंगे। असली वित्तीय समावेश तभी होगा हम जब उन संस्थाओं को मजबूत करें, जो अपने लोगों को जानती हैं, क्योंकि क्रेडिट केवल पूंजी नहीं, भरोसा भी है।

(लेखक आल इंडिया कांग्रेस माइनारिटी सेल के उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

संतुलन

आज हर व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर भाग रहा है-कभी सफलता, कभी मान-सम्मान और कभी उस भविष्य की ओर, जिसे वह अपने प्रियजनों के लिए सुरक्षित बनाना चाहता है। यह दौड़ मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि प्रयास, संघर्ष और परिश्रम ही प्रगति के मूल आधार हैं, लेकिन समस्या तब जन्म लेती है जब दौड़ जीवन का साधन न रहकर स्वयं जीवन का उद्देश्य बन जाती है। सफलता के पीछे भागते-भागते हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का असली मूल्य गति में नहीं, संतुलन में है। तेज दौड़ आपको आगे पहुंचा तो सकती है, पर यह तभी सार्थक है जब आपके भीतर शांति भी हो।

हर जीत के पीछे किसी के त्याग की कहानी होती है। जैसे कि माता-पिता अपनी जगह अपने बच्चों के सपनों को प्राथमिकता देते हैं। यह संवेदना अगली पीढ़ी के मन में बनी रहे, यही असली विरासत है। दौड़ आवश्यक है, परंतु संयम के साथ। समाज, तकनीक और दुनिया के बदलते रूप को देखते हुए यह भी उतना ही सच है कि इस दौड़ को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि किस दिशा में दौड़ें। उद्देश्यहीन गति अंततः थकान देती है, जबकि सार्थक गति जीवन को ऊर्जा देती है। जीवन की हर दौड़ में जीत मिले जरूरी नहीं, लेकिन गिरने के बाद फिर उठना अधिक महत्वपूर्ण है। परिश्रम सफलता की कुंजी है, पर विवेक वह हाथ है, जो इस कुंजी को सही ताले में लगाता है। मानवता आज जिन वैश्विक संघर्षों और शक्तिसंघर्षों की दौड़ में उलझी है, वह चेतावनी है कि अनियंत्रित महत्वाकांक्षा कैसे विनाश ला सकती है। अतः व्यक्तिगत और सामूहिक स्तरों पर संयम, संतुलन और संवेदनशीलता आवश्यक हैं। दौड़ें, पर अपने भीतर शांति बचाए रखकर। आगे बढ़ें, पर अपने मनुष्य होने की कोमलता को खोए बिना, क्योंकि अंततः जीवन गति नहीं, गति और विश्रांति का संतुलन है।

छाया श्रीवास्तव

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

खुले संवाद का समर्थक संघ

संपादकीय 'संघ प्रमुख का आमंत्रण' पढ़ा। यह तथ्य है कि संघ लंबे समय से गलत और नकारात्मक धारणाओं का शिकार रहा है। उसके बारे में बनी कई सतही अवधारणाएं उन लोगों द्वारा गढ़ी गई हैं, जिन्होंने कभी संघ को निकट से समझने का प्रयास ही नहीं किया। यदि ऐसे लोग संघ प्रमुख के निमंत्रण को सकारात्मक रूप में लें और संघ को भीतर से देखने की कोशिश करें, तो संभव है कि उसके प्रति उनकी कई मिथ्या धारणाएं दूर हो जाएं। संघ द्वारा सभी को संवाद के लिए आमंत्रित करना स्वयं इस बात का संकेत है कि उसके कार्यों में पारदर्शिता है और छिपाने जैसा कुछ नहीं। संघ का स्पष्ट मंतव्य है कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यापक सांस्कृतिक अर्थ में 'हिंदू' है। इसका प्रमाण यह है कि संघ आपदा राहत, सामाजिक कल्याण और सेवा कार्यों में सक्रिय रहता है तथा यह सेवा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रदान की जाती है। हिंदू समाज लंबे समय से अलग-अलग संप्रदायों और संस्कृतियों में विभाजित रहा है। इसके अनुयायियों में धार्मिक स्वाभिमान और गौरवबोध की कमी भी देखी गई है, जिसके कारण मतांतरण और अन्य दुष्चक्रों में वृद्धि हुई है। अतः समाज की एकजुटता और जागरूकता के प्रयास राष्ट्रहित में अत्यंत आवश्यक हैं। जहां अन्य पंथ और संप्रदाय अपने हितों के प्रति संगठित और सजग रहते हैं, वहीं हिंदू समाज अक्सर इसके विपरीत दिखाई देता है। यही कारण है कि एकजुटता और जागरूकता के अभाव में देश को सदियों तक पराधीनता और संघर्ष झेलना पड़ा।

विमलेश फगारिया, बदनावर, मध्य प्रदेश

फिर न छिड़े परमाणु हथियारों की होड़

शिवाकांत शर्मा ने 'फिर से न छिड़े परमाणु हथियारों की होड़' आलेख में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हथियारों की होड़ फिर शुरू करने को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यह बयान कि उन्होंने अपने युद्ध विभाग को अन्य देशों के समान स्तर के परमाणु परीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं, विश्व समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ट्रंप ने रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान पर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने के आरोप लगाए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। हालांकि चीन, रूस और पाकिस्तान ने इन आरोपों का खंडन किया है, किंतु पाकिस्तान के परमाणु इतिहास को देखते हुए उस पर भरोसा करना कठिन है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने 1998 के बाद से परीक्षणों पर रोक लगा रखी है, परंतु उसका अतीत इस पर संदेह उत्पन्न करता है। परमाणु तकनीक को दूसरे देशों को बेचकर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय नियमों की कई बार अवहेलना की है। इधर भारत ने 'पहले प्रयोग न करने' की नीति अपनाई है। दरअसल, ट्रंप जैसे नेताओं के लिए परमाणु नीति केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि हथियार उद्योग के लिए व्यापारिक अवसर है। हथियारों का कारोबार कुछ देशों की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। यही कारण है कि वैश्विक शक्तियां खुले रूप से भले ही शांति की बात करते हैं, परंतु गुप्त रूप से नए-नए विध्वंसक हथियारों के निर्माण में लगी हैं।

विभूति बुपक्या, दिल्ली

आतंकी साजिश नाकाम

देश में आतंकवाद की निरंतर बढ़ती चुनौती के बीच गुजरात एटीएस द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण कार्रवाई ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। एटीएस ने गांधीनगर से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनका देशव्यापी आतंकी हमले की साजिश से संबंध पाया गया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में एक डाक्टर भी शामिल है, जो हैदराबाद का निवासी बताया गया। अभियुक्तों के कब्जे से विदेश निर्मित कई पिस्टल, जिंदा कारतूस व अरंडी (कैस्टर) का तेल बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच से यही पता चला कि इस तेल का इस्तेमाल अत्यंत विषैले पदार्थ को बनाने में किया जाना था, जिसे देश में बड़े पैमाने पर जनहानि के लिए दुरुपयोग किया जा सकता था। आरोपितों ने बताया कि हथियार आपूर्ति करने के लिए पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन का उपयोग किया गया था। आरोपियों द्वारा दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद समेत अन्य संवेदनशील जगहों की रेकी करने की बात सामने आई है। गिरफ्तार डाक्टर का नाम अहमद मोइनुद्दीन सैयद बताया गया है, जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई चीन से किया था और साजिश में प्रमुख भूमिका निभा रहा था। अन्य दो के संबंध उत्तर प्रदेश से हैं, जिसकी पूरी जांच होनी बाकी है। जांच में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन व अन्य अंतरराष्ट्रीय तंत्रों का नाम भी जुड़ा है। इस तरह की साजिश को समय रहते पर्दाफाश करना देश के सुरक्षा एवं खुफिया तंत्र के लिए एक अहम सफलता है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

पोस्ट

कोलकाता की गुलशन कालोनी अचानक बस गई और यहां लगभग दो लाख लोग रहते हैं, लेकिन बीएलओ केवल 20,000 मतदाताओं का ही पता लगा पाए। बाकी लोग कौन हैं?

पद्मजा जोशी@PadmajaJoshi

एक डाक्टर खतरनाक केमिकल राइसिन के साथ पकड़ा गया। दो डाक्टर एके-47 के साथ पकड़े गए। एक आइटी इंजीनियर आइईडी मैनुअल्स के साथ पकड़ा गया। जो कोई कहता है कि आतंकवाद गरीबी या अशिक्षा से आता है, वह भ्रम फैला रहा है।

अमित शांडिल्य@Schandillia

कभी सोचा नहीं था कि डाक्टर आतंकी भी बन सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए, कम है।

ऋचा द्विवेदी@RicchaDwivedi

आतंकवादियों और उनके मददगारों का नार्को, पालीग्राफ, ब्रेनमैपिंग टेस्ट करने, 100 प्रतिशत संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और एक वर्ष में फांसी देने के लिए कानून कब बनेगा?

अश्विनी उपाध्याय@AshwiniUpadhyay

जनपथ

निर्णायक दिन आज है जाय करो मतदान,
बटन दबाओगे सही तो होगा कल्याण।
तो होगा कल्याण तनिक सा भी यदि चूके,
होगा जंगल राज मिलेंगे पग-पग धोखे।
पूरा बुद्धि - विवेक लगाकर चुनिए नायक,
लोकतंत्र का पर्व सदा होता निर्णायक।

\- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 116

****

बंगाल समेत अन्य 12 राज्यों में नहीं दिखेगा एसआइआर पर बिहार जैसा विरोध : रावत

साक्षात्कार

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसका तीखा विरोध हो रहा है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई गई है। लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष के हमलों को झेल चुके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का मानना है कि एसआइआर के खिलाफ बिहार जैसा विरोध बंगाल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में नहीं देखने को मिलेगा। बिहार से सीख लेते हुए चुनाव आयोग ने इस बार फार्म के साथ दस्तावेज देने की बाध्यता खत्म कर दी है। उन्होंने कहा कि एसआइआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग को है लेकिन वोट चोरी जैसे मुद्दे पर चुनाव आयोग को ज्याद संवेदशीलता और पारदर्शिता से काम करना चाहिए। पूर्व **सीईसी रावत** से दैनिक जागरण के विशेष संवाददाता **अरविंद पांडेय** ने एसआइआर के मुद्दे पर विस्तार से बात की। पेश से बातचीत के प्रमुख अंश---

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ● आइएएनएस

- चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप राजनीतिक, ऐसे आरोप पहले कभी नहीं लगाए गए
- इस बार चुनाव आयोग ने बीएलए को कुछ ज्यादा ही अधिकार दे दिए

●कांग्रेस ने मतदाता सूची में गड़बड़ी को बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्या पहले भी यह मुद्दा बना था?

-2018 में यह मुद्दा काफी उठा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद में ऐसे मुद्दे उठे थे। इस तरह की शिकायतों के बाद आयोग ने डुप्लीकेट, एक जैसे चेहरों वाले मतदाताओं की पहचान के लिए दो साफ्टवेयर खरीदे। इससे बड़ी संख्या में एक जैसे मिलते-जुलते नाम व चेहरे वाले मतदाता निकाले गए। अकेले मध्य प्रदेश में इसके जरिए 60 लाख डुप्लीकेट मतदाता पकड़े गए थे।

●आपके समय में राजनीतिक दलों ने ईवीएम को मुद्दा बनाया था और अब मतदाता सूची को। पूरा विवाद आयोग पर दबाव बनाने का हथकंडा है?

-ऐसा नहीं है। असलियत यह है कि राजनीतिक दलों के पास किसी आरोप की जांच के लिए कोई साधन है। उन्हें तो अपने कार्यकर्ताओं की बात पर भरोसा करना होता है। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन चुनावी मशीनरी की ये मजबूरी नहीं है। किसी भी मुद्दे पर जांच के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी को जांच में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें भरोसा रहे कि जांच सही हुई है। ईवीएम के मामले में ऐसा ही किया गया था। आम आदमी पार्टी ने उस समय आरोप लगाया था। आयोग ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया और कहा कि हमारे सुरक्षाकर्मियों के साथ चलें, जहां भी संदेह हो, हम वहां से उन ईवीएम को उठाकर लाएंगे। कोई राजनीतिक दल आगे नहीं आया।

●कांग्रेस मशीन रिडेबल मतदाता सूची मांग रही है और आयोग उसे दे नहीं रहा है। क्या फैसला सही है?

-रिडेबल मतदाता सूची सुरक्षा कारणों से किसी को नहीं दी जा सकती है। आयोग को शिकायत पर अपने पास मौजूद मशीन रिडेबल से तुरंत जांच कर शिकायत करने वाले को सही तथ्य बताना चाहिए।

●एसआइआर पहले भी हुए हैं लेकिन पहली बार ऐसा विरोध हो रहा है। क्यों?

-आजादी के बाद 2003 तक सात या आठ बार एसआइआर हो चुके हैं। लेकिन कभी एसआइआर को लेकर विवाद नहीं हुआ। पहले कभी नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं मांगा गया। सिर्फ गणना फार्म सभी को भरना था। बाद में संदेह होने पर नागरिकता के दस्तावेज मांगे जाते थे। इस बार नागरिकता का मुद्दा नागरिकों पर डाल दिया गया। यह विवाद और विरोध की बड़ी वजह बना।

●राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या चुनाव आयोग वोट चोरी करा सकता है?

-ये चीज राजनीतिक है। आयोग पर वोट चोरी के आरोप पहले कभी नहीं लगाए गए। आयोग की सदैव नीति रही कि कोई भी राजनीतिक दल या मतदाता शिकायत करता था तो एक मिनट की देरी किए बगैर तुरंत जांच कराता था। इसमें शिकायतकर्ता और सभी राजनीतिक दलों को शामिल किया जाता था। अगले ही दिन बता दिया जाता था कि असलियत क्या है। इससे किसी को हल्ला करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जांच के लिए शपथ पत्र देने को कहा गया। जब सभी क्षेत्र में डी-क्रिमनलाइजेशन की बात की जा रही है, तब आयोग का यह रवैया सही नहीं है। शपथ पत्र मांगना क्रिमनलाइजेशन जैसी चीज ही है। यदि एक भी गलती हुई तो छह महीने की सजा होगी।

●क्या बिहार जितने नाम पहले भी कभी मतदाता सूची से हटाए गए थे?

पुनरीक्षण में इससे ज्यादा नाम हटते रहे हैं। 2023 में मतदाता सूची के शुद्धिकरण को लेकर देशभर में एक बड़ा अभियान चलाया गया था। इसमें मतदाता सूची में होने वाली नेचुरल बढ़ोत्तरी की जगह मतदाताओं की संख्या करीब छह प्रतिशत तक कम हो गई थी।

●मतदाता सूची जमीनी स्तर पर बीएलओ तैयार करते हैं। इनकी नियुक्ति को लेकर कोई मानक है? इनके प्रशिक्षण पर कितना जोर दिया जाता है और गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई होती है?

-ये स्थानीय और उसी क्षेत्र के रहने वाले होने चाहिए। सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। साथ ही उस क्षेत्र, मोहल्ले की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिनका निवास कहीं और है और ड्यूटी कहीं और है तो उन्हें इसमें नहीं लगाया जाता है। इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। बीएलओ कोई गड़बड़ी करता है तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा जाता है।

●एसआइआर के दौरान बीएलए का नाम भी चर्चा में है। चुनावी प्रक्रिया में इनकी क्या उपयोगिता होती है और ये कितने सक्रिय रहते हैं?

-इस बार चुनाव आयोग ने बीएलए को कुछ ज्यादा अधिकार दे दिए। उन्हें फार्म लाकर जमा करने का अधिकार दे दिया। उन्हें बीएलओ के साथ बैठने का अधिकार दिया। ये पहले कभी नहीं हुआ। बीएलए से कहा जा रहा है कि वह 50 फार्म लाकर जमा करा सकता है।

कूड़े के ढेर में मिलीं वीवीपैट की पर्चियां, मतदानकर्मी निलंबित

कूड़े के ढेर में बिखरी वीवीपैट की पर्चियां ● सौजन्य : इंटरनेट मीडिया

जागरण संवाददाता, सिवान : बिहार के सिवान जिले के आठ विस क्षेत्रों में पहले चरण के मतदान के चार दिन बाद सोमवार को मौली के बथान में कूड़े के ढेर में चुनाव चिह्न युक्त पर्चियां मिलीं। ये पर्चियां महाराजगंज विस से संबंधित हैं। जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश ने बताया कि पर्चियां ईवीएम और वीवीपैट की कमिशनिंग में माक पोल की हैं।

मामले में संबंधित मतदानकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जिनकी संख्या पांच या छह हो सकती है। प्राथमिकी की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पर्चियों को नियमों के अनुसार नष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन लापरवाही से इन्हें कूड़े में फेंक दिया गया। लोगों ने पर्चियों का वीडियो बना प्रसारित कर दिया।

एक नजर में

बच्चे को चुनावी मंच पर लाने के मामले में एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान

पटना : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने समस्तीपुर जिले में एक नाबालिग को चुनावी रैली में मंच पर लाए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है। आयोग ने इसे बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए जिलाधिकारी को तीन दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग ने बताया कि बच्चे को मंच से लाठी और कट्टे जैसे शब्दों के प्रयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। जिले के अधिकारियों ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। (जासं)

पीएम ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ साझा किया मंच : तेजस्वी

पटना : राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जीत के लिए एनडीए हर प्रकार के हथकंडे अपना रहा है। वह चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस बल की सहायता ले रहा है। इसके बावजूद महागठबंधन की सरकार बनेगी। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार में एनडीए ने सभी मर्यादाएं तोड़ी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ मंच साझा किया, जिसमें भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले के आरोपित विपिन शर्मा की पीठ थपथपाई गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा भाषण दिया, जिससे बिहार की बदनामी हुई। (राब्यू)

एसआइआर पर आयोग गंभीर, बिहार चुनाव के बाद बढ़ाएगा और निगरानी

12 राज्यों में शुरू एसआइआर में तेजी नहीं, चार तक भरे जाने हैं गणना फार्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: एसआइआर के दूसरे चरण में बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों में घर-घर जाकर गणना फार्म देने और उसे वापस लेने का अभियान वैसे तो चार नवंबर से शुरू हो गया है लेकिन इसके करीब एक सप्ताह बाद भी यह सभी बूथों पर रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। चुनाव आयोग ने अभियान में ढिलाई को लेकर मिल रही खबरों के बाद राज्यों से इनमें तेजी लाने का निर्देश दिया है। साथ ही बिहार चुनाव के बाद इसकी प्रतिदिन निगरानी शुरू करने की बात भी कही है। बिहार में अंतिम चरण का चुनाव 11 नवंबर को है, जबकि नतीजे 14 नवंबर को आ जाएंगे।

चुनाव आयोग ने राज्यों को तेजी का यह निर्देश तब दिया है, जब दूसरे चरण के एसआइआर में मसौदा सूची का प्रकाशन नौ दिसंबर तक होना है। इससे पहले चार दिसंबर तक गणना फार्म लेने और उसको भरवा कर वापस लेने का काम पूरा करना है। करीब 51 करोड़ मतदाताओं को इस अभियान में शामिल होना है। यह बात अलग है कि बिहार से सबक लेते हुए आयोग ने दूसरे चरण में गणना फार्म के साथ किसी तरह का दस्तावेज नहीं मांगा है।

बंगाल के मौसुनी द्वीप स्थित मछुआरों के गांव में सोमवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए गणना प्रपत्र सौंपते बीएलओ ● एएफपी

7.64 लाख बूथ लेवल एजेंटों की भागीदारी

आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में जिन 12 राज्यों में एसआइआर का काम शुरू हुआ है, उनमें करीब 5.33 लाख मतदान केंद्र पर यह अभियान चलाया जाना है। इस पूरे अभियान में राजनीतिक दलों से जुड़े बूथ लेवल एजेंटों की भी सक्रिय भागीदारी दी गई है, जिनकी संख्या मौजूदा समय में करीब 7.64 लाख है।

ममता ने की एसआइआर पर रोक की मांग

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआइआर) पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तर बंगाल के दौरे पर सोमवार को दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी आईं ममता ने प्रशासनिक बैठक के बाद कहा कि लाखों लोग अभी तक फार्म नहीं प्राप्त कर पाए हैं। कब फार्म मिलेगा, कब इसे जमा करेंगे, इसको लेकर गहमा-गहमी की स्थिति है। उन्होंने तर्क दिया कि इतने कम समय में हर घर जाकर फार्म बांटना और भरवाना लगभग असंभव है, खासकर जब फरवरी में राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है। ममता ने एसआइआर को लेकर चुनाव आयोग के साथ ही केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार पर हमला बोला।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण पर कोर्ट पहुंची तृणमूल

तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में चार नवंबर से निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) शुरू किए जाने के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पार्टी की लोकसभा सदस्य माला राय और राज्यसभा सदस्य डोला सेन ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होने की संभावना है।

छह सीटों पर साथी बनाम साथी का महासंग्राम

महासमर बिहार

सुनील राज ● जागरण

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मंगलवार को होने वाले मतदान में महागठबंधन के प्रमुख दलों के बीच आधा दर्जन सीटों पर सीधा मुकाबला होगा। यहां संग्राम सत्ता-विपक्ष के बीच नहीं, साथी बनाम साथी की स्थिति में बदल गया है। इस चरण में चार सीटों पर राजद और कांग्रेस, एक सीट पर सीपीआइ और कांग्रेस तथा एक सीट पर राजद और वीआइपी के बीच टकराव होगा। मुकाबला

केवल उम्मीदवारों के बीच नहीं, विचारधाराओं और राजनीतिक वफादारी की टकराहट का प्रतीक बन गया है।

करगहर सीट पर कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा और सीपीआइ के महेंद्र प्रसाद गुप्ता के बीच टकराव होगा। यह वही सीट है, जहां कांग्रेस ने वामदलों को जमीन देने पर असहमति जताई थी। नरकटियागंज में राजद के दीपक यादव और कांग्रेस के शाश्वत केदार आमने-सामने हैं, जहां टिकट बंटवारे को लेकर विवाद रहा। सिकंदरा में कांग्रेस के विनोद चौधरी और राजद के उदय नारायण चौधरी के बीच मुकाबला गठबंधन की नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है।

कहलगांव सीट पर राजद के रजनीश भारती व कांग्रेस के प्रवीण सिंह कुशवाहा के बीच लड़ाई ने गठबंधन की रणनीति को झकझोर दिया है। सुल्तानगंज में राजद के चंदन सिन्हा और कांग्रेस के ललन कुमार का मुकाबला स्थानीय नेताओं की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है।

चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे तेजस्वी : भाजपा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग और भाजपा पर मिलीभगत कर गड़बड़ियों का आरोप लगाने वाले राजद नेता तेजस्वी यादव पर भाजपा ने पलटवार कर कहा कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद 'साइलेंस पीरियड' में तेजस्वी का यह रुख देखकर लग रहा है कि उन्होंने अंतिम चरण के मतदान से पहले ही सरेंडर कर दिया है। अब वह चुनाव हारने के बहाने ढूंढ रहे हैं। साथ ही भाजपा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर राजनीतिक पर्यटक होने का तंज कसते हुए निशाना साधा है।

भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बिहार में भाजपा-राजग की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। उन्होंने कहा-तेजस्वी यादव ने प्रश्न किया है कि सारे उद्योग भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों लगते हैं? बिहार या तमिलनाडु में क्यों नहीं लगते? इसका जवाब देते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री की दावेदारी करने वाले तेजस्वी यादव को होमवर्क की बहुत जरूरत है। बिहार में लगी औद्योगिक इकाइयों पर अपने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में 1.18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू पर दस्तखत हुए हैं। ये तभी संभव हो पाया, जब बिहार का वातावरण जंगलराज, आतंक, अपराध और खौफ से मुक्त हुआ।

इस चुनाव को जंगलराज बनाम सुशासन का चुनाव बता रविशंकर ने कहा कि तेजस्वी लालू यादव के भ्रष्टाचार, कुशासन और खौफ की विरासत को बढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जंगलराज का असली अर्थ है डर, अपहरण, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कार्रवाई का अभाव।

रविशंकर प्रसाद ● फाइल फोटो

बिहार में चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिलीभगत का आरोप लगाने पर सत्ताधारी दल का तेजस्वी यादव पर पलटवार

महागठबंधन के पास विकास का ठोस रोडमैप, राजग के पास अभद्र भाषा व झूठे वादे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: बिहार में दूसरे एवं अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले राजग के वादों-दावों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि महागठबंधन राज्य के विकास का स्पष्ट रोडमैप लेकर उतरा है, इसके विपरीत राजग के पास सिर्फ अभद्र भाषा और झूठे वादे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनावी कामयाबी को लेकर विपक्षी खेमे का हौसला मजबूत होने का संदेश देते हुए दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बिहार को 20 वर्ष के लाचार शासन से मुक्ति दिलाएगी।

भाजपा-राजग पर निशाना साधते हुए खरगे ने सोमवार को बिहार चुनाव के संदर्भ में एक्स पर पोस्ट में कहा कि अब पलायन रुकेगा, युवाओं के भविष्य से अंधेरा छटेगा, हर-घर नौकरी से उनका कल संवरेगा। सभी वर्गों के बीच महागठबंधन के समर्थन का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि महिला, किसान, युवा, समाज के हर वर्ग का आर्थिक उत्थान होगा और राज्य की तस्वीर बदलने के लिए बिहार की जनता कर चुकी है प्रस्थान। कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बिहार में 20 वर्ष के विनाश के बाद अब भी राजग नेताओं के पास केवल ''अभद्र भाषा और झूठे वादे'' हैं। खरगे व जयराम ने महागठबंधन की प्रमुख चुनावी गारंटियों को भी साझा किया। इनमें महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 500 में गैस सिलिंडर, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, जीविका दीदियों को 30,000 रुपये मासिक वेतन, बुजुर्गों को 1500 रुपये जैसे वादे शामिल हैं।

मल्लिकार्जुन खरगे ● फाइल फोटो

- खरगे ने कहा, बिहार को 20 वर्षों की लाचार व्यवस्था से मुक्ति दिलाएगा महागठबंधन
- दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन की गारंटियों पर कांग्रेस ने जताई प्रतिबद्धता

'वोट चोरी' के विरुद्ध अभियान में एक करोड़ हस्ताक्षर जुटाए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: 'वोट चोरी' के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान को कांग्रेस की कर्नाटक इकाई ने गति देते हुए 1.12 करोड़ से अधिक लोगों के हस्ताक्षर पत्र पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दिए।

कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष व प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दावा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक के बाद अब बिहार से वोट चोरी की शिकायतें आ रही हैं। दक्षिण बेंगलुरु लोस क्षेत्र के अंतर्गत महादेवपुरा विस क्षेत्र में 2024 के लोस चुनाव में कथित तौर पर एक लाख फर्जी वोट की बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के उजागर करने पर कांग्रेस ने वोट चोरी के विरुद्ध देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है।

कर्तव्य पथ पर अग्रसर...

जहानाबाद में सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए निर्वाचन सामग्री लेकर अपने बूथ की ओर जाते मतदान अधिकारी और सुरक्षाकर्मी ● प्रेट्र

'वंदे मातरम्' न गाएं मुस्लिम बच्चे, स्कूल से निकल जाएं : कासमी

मुंबई, आइएएनएस : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में 'वंदे मातरम्' गाना अनिवार्य करने की घोषणा पर मुस्लिम समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। जमीयत उलमा-ए-महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने कहा कि मुसलमानों को बच्चों को स्कूलों से निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें राष्ट्रगीत गाने के लिए मजबूर किया जाए। कासमी ने कहा, हम मुसलमान हैं। संविधान धर्म पालन की आजादी देता है। हमारा धर्म सिखाता है कि अल्लाह एक है और हम सिर्फ उसी की इबादत करेंगे। जो हो रहा है, वह मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए है।

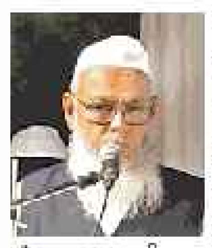

मौलाना कासमी

भाजपा नेता पर दोहरे मतदान का आरोप, प्रशासन बोला-होगी जांच

जागरण संवाददाता, बक्सर : भाजपा नेता और दिल्ली में पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा पर दोहरे मतदान का गंभीर आरोप लगा है। उन्होंने फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वोट डाला था, जबकि छह नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर में भी मतदान किया। आरोप है कि उनके मतदाता पहचान पत्र दोनों स्थानों पर सक्रिय हैं। दोनों अवसरों पर उन्होंने अपनी सेल्फी इंस्टाग्राम पर साझा की थी, लेकिन विवाद के बाद बक्सर में मतदान वाली तस्वीर हटा दी गई।

जिला प्रशासन ने अपने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि बक्सर में मतदान से संबंधित सभी दस्तावेज फिलहाल स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। 14 नवंबर को स्ट्रांग रूम खुलने के बाद आरोपों की जांच की जाएगी और यदि आरोप सत्य पाए गए तो उचित कार्रवाई की जाएगी। संतोष मूल रूप से बक्सर के सुरौंधा गांव के निवासी हैं। उनके पिता नागेंद्र नाथ ओझा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और रास के सदस्य रहे हैं।

संतोष ओझा ● फाइल फोटो

फरवरी में दिल्ली विस चुनाव में वोट डाला था, जबकि छह नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर में भी मतदान का आरोप

बिहार में शहरी सीटों पर मतदाताओं की उदासीनता नहीं हो रही दूर

राज्य ब्यूरो, जागरण, पटना : बिहार में राजनीतिक दलों के तमाम प्रयास एवं चुनाव आयोग की संपूर्ण जागरूकता के बावजूद मतदान के प्रति शहरी सीटों पर मतदाताओं की उदासीनता दूर नहीं हो रही है। चुनावी पारा भले ही राजनीतिक दलों के पोस्टर, दीवारों की रंगाई, इंटरनेट मीडिया अभियानों एवं रोज बदलते चुनावी बयानों से गरमाता रहा, लेकिन शहर के मतदान केंद्रों पर इसका असर कमजोर दिखा। लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में शहर के मतदाता फिर एक बार पिछड़ गए। आजादी के उपरांत रिकार्ड वोटिंग के बावजूद 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण के मतदान संबंधित आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं।

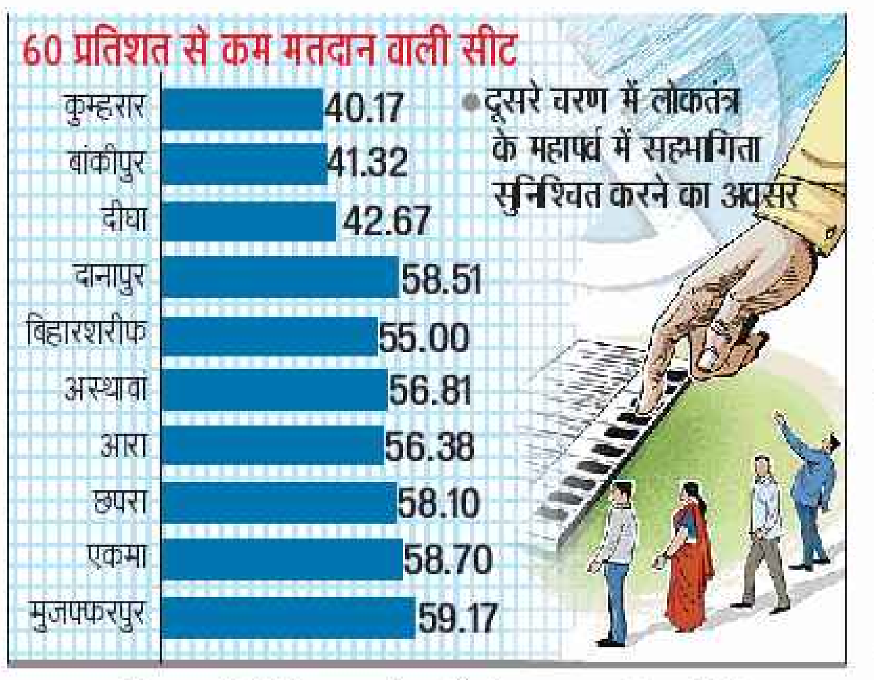

पटना की चार सीटों के साथ ही मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं छपरा जैसी कई सीटें सूची में सम्मिलित हैं। विशुद्ध रूप से शहरी विधानसभा क्षेत्र में सूचीबद्ध उपरोक्त सीटों पर पड़े वोट लोकतंत्र के प्रति निराशाजनक संकेत हैं। प्रथम चरण के 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को हुए मतदान के उपरांत 10 सीटें ऐसी चिह्नित हुईं, जहां 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ है। पिछले चुनावों की तुलना में शहरी क्षेत्र के मतदान प्रतिशत में सुधार भी हुआ है। ऐसे में अब मंगलवार को होने वाले मतदान के दौरान लोगों का दायित्व बनता है कि वह इस दाग को धोने का प्रयास सुनिश्चित करें।

उदासीनता के कारणों की बात करें तो लंबी लाइनों को लेकर अरुचि, भीड़भाड़ वाली पार्किंग, छुट्टी के दिन घर से नहीं निकलने की आदत और राजनीतिक दलों से उपजी निराशा जैसे कारण अक्सर सामने आते हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान से लेकर सेल्फी प्वाइंट तक तैयार किए, लेकिन इनका असर अपेक्षित नहीं दिखा। शहरों में रहने वाले मतदाता सूचना और सुविधाओं के मामले में आगे रहते हैं, फिर भी लोकतांत्रिक भागीदारी में पिछड़ रहे हैं। यह अंतर हर चुनाव के बाद बहस को जन्म देता है।

राजनीतिक दल भी इसे लेकर चिंतित हैं क्योंकि कम मतदान उनके समीकरणों को प्रभावित करता है। चुनाव विशेषज्ञों की राय है कि जब तक शहर का मध्यम वर्ग मतदान को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। लोकतंत्र तभी सशक्त होगा जब हर मतदाता अपनी भूमिका निभाए।

'नेहरू-गांधी परिवार के बाहर किसी की तारीफ कांग्रेस को पसंद नहीं'

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र: केरल भाजपा प्रमुख राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को यह पसंद नहीं है कि उसके नेता नेहरू-गांधी परिवार के बाहर किसी की प्रशंसा करें। उन्होंने शशि थरूर का समर्थन किया। थरूर की भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की प्रशंसा के लिए आलोचना की गई थी।

चंद्रशेखर ने कहा कि भाजपा को देश सेवा करने वाले किसी भी राजनीतिक नेता का सम्मान करने, उसे मान्यता देने में हिचकिचाहट नहीं है, चाहे वह किसी पार्टी का हो। कहा कि अगर थरूर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के इतालवी रिश्तेदारों की तारीफ करते, तो कांग्रेस उनकी तारीफों की बौछार कर देगी।

****

महिला आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर महिला सशक्तीकरण का पक्ष लेते हुए महिलाओं को देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह बताया है, तो आश्चर्य नहीं। गौर करने की बात है कि कुल आबादी का लगभग 48.4 प्रतिशत महिलाएं हैं, पर देश की मुख्यधारा में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह सवाल किया गया है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने में देरी क्यों हो रही है? इस याचिका पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब-तलब किया है। वैसे, आरक्षण के लिए कानून पारित हो चुका है और उसे लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर है। यहां न्यायालय कानून को जल्दी लागू करने के लिए खास कुछ नहीं कर सकता है। कानून का क्रियान्वयन सरकार का काम है। महिलाओं के लिए विधायिका में 33 फीसदी आरक्षण संबंधी संशोधन तो साल 2023 में ही हो गया था, लेकिन जब देश में अगला चुनाव क्षेत्र परिसीमन होगा, उसके बाद ही उच्च स्तरीय विधायिका में इसे लागू किया जाएगा। चूंकि मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है, इसलिए महिला सशक्तीकरण के पक्षधर लोगों की व्यग्रता को समझा जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पूछा है कि आरक्षण के बिना महिलाओं को टिकट क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? दुखद है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व घट रहा है। सदन में 33 प्रतिशत महिला भागीदारी बहुत दूर की बात है। अभी लोकसभा में 75 और राज्यसभा में 42 महिलाएं हैं, लेकिन अनेक विधानसभाओं में महिलाओं की कमी बहुत खलती है। इस आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने जो सक्रियता दिखाई है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जनहित याचिका और अदालती सक्रियता से यह पता चलेगा कि सरकार कब परिसीमन का काम करेगी। तय है कि परिसीमन के बाद भारतीय राजनीति में अनेक परिवर्तन होंगे और उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन महिला आरक्षण से आएगा। आज यह आरक्षण लागू हो जाए, तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कम से कम 179 हो जाएगी। अगर परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ी, तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या 200 पार कर जाएगी। निश्चित रूप से महिलाओं को इस दिन का इंतजार है।

अगर परिसीमन में सीटों की संख्या बढ़ी, तो लोकसभा में महिलाओं की संख्या 200 पार कर जाएगी। निश्चित रूप से महिलाओं को इस दिन का इंतजार है।

सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि मुख्यधारा राजनीति में महिलाओं की भागीदारी स्वयं बढ़ाने के प्रति राजनीतिक दल सजग नहीं हैं। आदर्श स्थिति तो यह होती कि हर पार्टी स्वयं ही कम से कम 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को टिकट देती। ऐसे में, अलग से महिला आरक्षण के लिए किसी पार्टी को कानूनन पाबंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज होता यह है कि हर पार्टी जीत सकने वाले उम्मीदवारों की तलाश में रहती है और महिलाओं का दावा कमजोर हो जाता है। एक पहलू यह भी है कि ज्यादातर महिलाएं स्थापित राजनीतिक परिवारों से आ रही हैं और पूरी तरह से अपनी योग्यता पर राजनीति में मुकाम बनाने वाली महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं को आरक्षण मिले, पर इसके लिए पहले से ही माहौल बनाने की जरूरत है। आरक्षण थोपने से महिलाओं को मजबूती नहीं मिलेगी। महिलाओं को स्वयं ही मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा और उन्हें यह मजबूती अपनी आधी आबादी से ही हासिल होगी। इसके लिए सबसे जरूरी है, महिलाओं के बीच व्यावहारिक जागरूकता।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 11 नवम्बर, 1950

नेपाल का गृह कलह

नेपाल की ताजा घटनाओं ने देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नेपाल भारत का पड़ोसी राज्य है और एक पड़ोसी राज्य में होने वाली घटनाओं से भारत कैसे अप्रभावित रह सकता है? तिब्बत में चीन द्वारा शक्ति के प्रयोग की रोशनी में नेपाल का घटनाचक्र और महत्व धारण कर लेता है। भारत अपनी उत्तरी सीमा की रक्षा के संबंध में अब तक निश्चिन्त था, किन्तु जैसा कि भारत के उप-प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने दिल्ली की सार्वजनिक सभा में कहा है, सुरक्षा की यह भावना अब नष्ट हो गई है। भारत की उत्तरी सीमा पर खतरे के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं और भारत को इन उठते हुए खतरों का सामना करने के लिए सतर्क होना पड़ेगा। नेपाल नरेश और वहां के प्रधानमंत्री में अनबन पैदा हो गई है। नेपाल के महाराजाधिराज त्रिभुवन वीर विक्रम शाह देव अपने युवराज और युवराज के प्रथम पुत्र के साथ काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास में शरण लेने को बाध्य हुए हैं। नेपाल में वैधानिक स्थिति बड़ी विचित्र है। नेपाल नरेश नाम के ही राजा हैं। शासन की समस्त सत्ता प्रधानमंत्री के हाथों में केन्द्रित है। वही राज्य के प्रधान सेनापति भी हैं। अतः नेपाल का राजा सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। कितनी साधारण-सी बात पर नेपाल नरेश और नेपाल के प्रधानमंत्री में अनबन हो गई, यह इसी से प्रकट हो जाता है कि नेपाल नरेश अपने इलाज के लिए भारत आना चाहते थे और प्रधानमंत्री ने उनको इसकी इजाजत नहीं दी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल नरेश नेपाल सरकार के बन्दी बनकर ही नेपाल में रह रहे थे। कहा जाता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री का कोपभाजन बनकर बड़े-से-बड़ा व्यक्ति भी नेपाल में सुरक्षित नहीं रह सकता। नेपाल नरेश ने अपने सारे परिवार सहित भारतीय दूतावास में जो शरण ली है, इसका और क्या कारण हो सकता है?

नेपाल सरकार की ओर से कहा गया है कि नेपाल नरेश को भारतीय दूतावास से वापस लाने का प्रयत्न किया गया, किन्तु उन्होंने नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों से मिलना तक स्वीकार नहीं किया। इसका अर्थ ही यह है कि नेपाल नरेश नेपाल सरकार की नेकनीयती पर भरोसा करने को तैयार नहीं हैं। जहां तक भारत सरकार का ताल्लुक है, वह नेपाल-नरेश और राज-परिवार के अन्य सदस्यों को शरण देने से इन्कार नहीं कर सकती थी।

आतंकी साजिशों पर बना रहे शिकंजा

दिल्ली और फरीदाबाद की घटना बता रही है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा आतंकियों के रडार पर है। यह खतरा हमेशा से रहा है। हां, उसकी आवृत्ति व तीव्रता ऊपर-नीचे होती रही है।

यहां स्कैन करें

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ओआरएफ

ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार की देर शाम धमाके की खबर चिंताजनक है। सुबह में जब राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद शहर से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री मिलने की खबर आई थी, तो माना गया था कि वह हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की बड़ी सफलता है। वह थी भी। मगर देर शाम राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह धमाका हो जाना संकेत है कि आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे थे। इससे पहले रविवार को गुजरात के अहमदाबाद में एटीएस ने आईएस के तीन संदिग्धों को दबोचा था। खबर यह भी है कि बांग्लादेश के अंदर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सक्रिय हो गए हैं और अब वहां से भारत में दहशतगर्दों के निर्यात का खतरा बढ़ गया है।

जाहिर है, हमारी राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा आतंकियों के रडार पर है। वैसे, यह खतरा तो हमेशा से रहा है। हां, उसकी निरंतरता व तीव्रता ऊपर-नीचे होती रही है। कभी खतरा बढ़ गया, तो कभी कम होता प्रतीत हुआ। पिछले एक-डेढ़ साल की तेजी से बदली भू-राजनीति भी हमारे सुरक्षा बलों की परीक्षा लेती रही है। बांग्लादेश के घरेलू हालात, नेपाल के उपद्रव और पाकिस्तान-परस्त आतंकी संगठनों की नई रणनीति (विशेषकर सीमा रेखा के पास बड़े आतंकी शिविरों के बजाय सुदूर इलाकों में छोटे-छोटे ठिकाने बनाना, ताकि भारतीय एजेंसियों की निगरानी से बचा जा सके) ने क्षेत्र में ऐसी अस्थिरता को जन्म दिया है, जिसमें भारत के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। नतीजतन, हमने अपनी सुरक्षात्मक रणनीति भी तेजी से बदली है।

यह सही है कि सभी आतंकी गतिविधियां कट्टर इस्लामी सोच से प्रेरित नहीं होतीं, लेकिन यह भी सच है कि भारत में कश्मीर से जुड़े आतंकी गुट या अंतरराष्ट्रीय जेहादी संगठन से प्रेरित आतंकवाद का खतरा कभी टला नहीं है। उसमें उतार-चढ़ाव आता रहा है। मुमकिन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान सीधे तौर पर कोई हिमाकत न करे, लेकिन उसकी जमीन पर पलने वाले आतंकी संगठन इसी कोशिश में होंगे कि किसी आतंकी घटना को अंजाम देकर भारत में अस्थिरता पैदा की जाए। वे इसको भारत का घरेलू मसला बताकर दुष्प्रचार भी कर सकते हैं। दिल्ली धमाके के बाद अगर ऐसा होता है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा।

फरीदाबाद में जम्मू-कश्मीर और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की थी। हालांकि, जो कहानी पुलिस ने सुनाई है, वह कुछ अतिरंजित लग सकती है, फिर भी इसे सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के तालमेल का सुखद नतीजा माना जाना चाहिए। जो विस्फोटक बरामद हुआ, वह अमोनियम नाइट्रेट था, जो कोई बना-बनाया विस्फोटक नहीं होता, बल्कि प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। इसके लिए प्रशिक्षण की दरकार होती है। जाहिर है, जिन संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके संपर्क तलाशे जाएंगे, ताकि पूरा षड्यंत्र उजागर हो सके। दिल्ली धमाके से भी तार जोड़ा जाएगा।

कहा जा रहा है कि वे जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि उसके पोस्टर चिपका रहे थे? एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि वे गजवातुल हिंद के सदस्य हो सकते हैं, जिसके नेतृत्व का सफाया भारतीय सुरक्षा बलों ने कुछ समय पहले कर दिया था? किसी अंतरराष्ट्रीय जेहादी गुट से भी उनके संबंध की बातें कही जा रही हैं। या, फिर यह कोई नया सेल है? सच का पता तो जांच के बाद ही चल सकेगा, लेकिन इतना तय है कि भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है और हमारी चुनौती खत्म नहीं हुई है। हमारी सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों को और तत्पर रहना होगा।

इस पूरे मामले के कुछ अन्य पहलू भी हैं, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। पहला तो यही कि आम धारणा रही है कि आतंकियों को वेश-भूषा से पहचाना जा सकता है। मगर इस घटना से यह धारणा टूटती है। इसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें दो डॉक्टर हैं, जो स्वाभाविक ही पढ़े-लिखे व उच्च शिक्षित लोग हैं। इसका अर्थ यह भी है कि गरीबी और अशिक्षा से आतंकवाद के जन्म लेने की जो कहानी गढ़ी जाती रही है, वह सच नहीं है। हालांकि, कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी कई पढ़े-लिखे और संपन्न तबके के लोग आतंकी वारदातों में लिप्त पाए गए हैं। खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन तो अरबपति परिवार से था, तो उमर सईद शेख, जिसे कंधार विमान अपहरण कांड में रिहा करवाया गया था, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रह चुका है। कई ऐसे अध्ययन भी हुए हैं, जो बताते हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर आतंकवाद के प्रति विशेष आकर्षित होते हैं, क्योंकि वे तय ढर्रे पर चलना पसंद करते हैं, बेशक कितने भी आधुनिक बन गए हों। साफ है, आधुनिक शिक्षा-दीक्षा उनकी सोच को प्रभावित नहीं कर पाती।

दूसरी बात, हम अक्सर राजनीतिक व सामाजिक कारणों से आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वैचारिक मसलों को दरकिनार कर देते हैं, जबकि आतंकवाद मूलतः एक वैचारिक आंदोलन है। यह विध्वंसक विचारों की देन है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि सभी इंसानों को शक की निगाह से देखा जाए, पर देश में सामाजिक तौर पर सतर्कता जरूरी है और लोगों को एक-दूसरे की गतिविधियों परअवश्य गौर करना चाहिए। इंडियन मुजाहिदीन के लड़ाके कितने पढ़े-लिखे और शिक्षित थे। कोई आसानी से यह पता नहीं लगा सकता था कि वे कौन हैं और किस मंशा से काम कर रहे हैं? ऐसे असामाजिक तत्वों को पढ़ने की क्षमता आम लोगों के अंदर विकसित करनी होगी।

तीसरी बात, भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां कट्टरपंथ से लोग प्रभावित होते रहे हैं। मगर हम किसी न किसी वजह से उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। अब समय आ गया है कि हम उस समाज की ध्वनि को सुनें। यह गौर करना होगा कि उनके बीच किस तरह की बहस चल रही है। उनकी नाराजगी, उनकी शंकाओं को समझना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। वास्तव में, हमें उनके मन को टटोलना होगा। यह कहने मात्र से काम नहीं चल सकता कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। बेशक, तमाम एजेंसियों में बेहतर तालमेल से हमने आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन दिल्ली जैसे धमाके बताते हैं कि खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। बीते दो दिनों की खबरें यही संकेत दे रही हैं कि यह चुनौती आगे भी कायम रहने वाली है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

एसआईआर का क्यों विरोध कर रहे केरल और तमिलनाडु

दक्षिण एक्सप्रेस
यहां स्कैन करें

एस. श्रीनिवासन | वरिष्ठ पत्रकार

दक्षिण के दो राज्यों- तमिलनाडु और केरल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इन दोनों सूबों में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु में द्रमुक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा है कि यह कवायद असल में एनआरसी को पिछले दरवाजे से थोपने जैसी है। केरल भी कुछ इसी तरह की राह पर चल पड़ा है। इन दोनों सरकारों को शक है कि चुनावों के करीब होने के कारण यह कवायद गलत इरादे से की जा रही है।

तमिलनाडु अपनी याचिका में इसे गैर-कानूनी और अव्यावहारिक बता रहा है। गैर-कानूनी इसलिए, क्योंकि चुनाव आयोग एसआईआर कराने जा रहा है, जबकि बिहार में इसकी अनियमितता से जुड़ी एक याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। द्रमुक व उसके सहयोगियों ने एक साझा प्रस्ताव पारित कर केंद्र पर वैध मतदाताओं को हटाने और फर्जी मतदाताओं को जोड़ने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। अन्नाद्रमुक, भाजपा और उसके अन्य सहयोगी इस बैठक से दूर रहे। केरल में भाजपा को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों ने एसआईआर का विरोध किया है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर द्रमुक की तरह ही चुनाव आयोग को चुनौती देने का फैसला किया। द्रमुक सरकार कई व्यावहारिक समस्याओं को भी उठा रही है। उसका तर्क यह है कि मानसून का समय होने के कारण राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक महीना बहुत कम है। भारत के अधिकांश हिस्सों में दक्षिण-पूर्वी मानसून आता है, जो जून मध्य में केरल से शुरू होता है और अगस्त तक उत्तर में चरम पर पहुंचता है, जबकि तमिलनाडु में मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी मानसून से बारिश होती है, जो नवंबर-दिसंबर में चरम पर होता है। साथ ही, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पोंगल जनवरी के मध्य में पड़ता है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, उस समय मतदाता पुनरीक्षण और बाढ़ राहत कार्य- दोनों के लिए पर्याप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होंगे।

तमिलनाडु और केरल जैसे सूबों में एसआईआर बिहार की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यहां की तमाम पार्टियां काडर आधारित हैं।

केरल व तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं, जहां अन्य राज्यों, खासकर उत्तर भारतीय प्रवासी सबसे अधिक आते हैं। यहां उन्हें मतदाता बनने में खासी दिक्कतें आती हैं। शुरू में अनेक मजदूर शहरों में ही आते थे, लेकिन धीरे-धीरे अब उनमें से बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में चले गए। इससे उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो गया है। चूंकि मतदाता के रूप में नाम सिर्फ एक जगह हो सकता है, इसलिए प्रवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने गृह राज्य की सूची से नाम कटवाकर काम करने की जगह पर जुड़वाएं। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों द्वारा मतदाता-सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर द्रमुक खुश नहीं है। उसे लगता है कि ये 'मेहमान मजदूर' द्रविड़ पार्टियों द्वारा कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए की गई कड़ी मेहनत व कोशिशों को तवज्जो नहीं देंगे। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग उत्तर की पार्टियों, खासकर भाजपा का साथ दे सकते हैं। उधर, केरल को चिंता है कि इस मुद्दे का पूरा फायदा उठाकर भाजपा राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सकती है। वहां हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां आरएसएस-भाजपा ने समाज में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की हैं। उदाहरण के लिए, जब केरल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा हुई, तो मुस्लिम विजेताओं पर वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने सीधे हमले किए। उन्होंने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया। इसमें दशकों से अभिनय की दुनिया में अपनी धाक जमाने वाले शीर्ष के अभिनेताओं को भी नहीं बख्शा गया। ममूटी को मुस्लिम व मोहनलाल को नायर बताया जा रहा है।

जाहिर है, दोनों राज्यों में बिहार की तरह एसआईआर नहीं होगा, क्योंकि यहां की पार्टियां काडर आधारित हैं। इन दोनों राज्यों में लंबे समय से पहचान का एक मार्कर जाति रही है। वहां इसका इस्तेमाल सामाजिक-कल्याणकारी नीतियां बनाने में आधार के तौर पर किया जा रहा है। उत्तर में किए गए प्रयोग, खासकर महिलाओं को 10,000 रुपये देने जैसी योजनाओं का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां ऐसी योजनाएं आम बात हैं और सभी राजनीतिक दल ऐसा ही करते हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

जहां प्रेम, वहीं क्रांति

भविष्य में आमूल परिवर्तन चाहने वाला या उस परिवर्तन को अंतिम लक्ष्य मानने वाला मन कभी सत्य को नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य क्षण-प्रतिक्षण पाया जाता है, हर पल नए सिरे से पाया जाता है; संचित अनुभव से कोई खोज संभव नहीं है। यदि आप पुराने के बोझ से दबे हैं, तो नए का अन्वेषण कैसे कर सकते हैं? उस बोझ के हटने पर ही आप नए को खोज पाते हैं।

नवीन को, शाश्वत को वर्तमान में प्रतिक्षण खोज पाने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति का मन असाधारण रूप से सतर्क हो। एक ऐसा मन, जो किसी परिणाम की खोज नहीं कर रहा, कुछ भी बनने का प्रयत्न नहीं कर रहा। कुछ बन जाने में लगा हुआ मन परितोष के उल्लास को कभी नहीं जान पाता। आत्ममुग्ध संतुष्टि नहीं, किसी फल की प्राप्ति से होने वाला परितोष नहीं, बल्कि ऐसा परितोष, जो तभी आता है, जब मन 'जो है' के सत्य और 'जो है' के मिथ्यात्व, दोनों को देख लेता है। इस सत्य का बोध क्षण-प्रतिक्षण होता है। इसे शब्दों में ढालने से बाधित हो जाता है।

आमूल परिवर्तन कोई लक्ष्य, कोई परिणाम नहीं है। परिवर्तन परिणाम नहीं है। परिणाम में अवशेष निहित है, कारण और कार्य निहित हैं। जहां कारण है, वहां कार्य का, प्रभाव का होना अनिवार्य है। वह प्रभाव बदलने की आपकी कामना का परिणाम भर होता है। जब आप रूपांतरित होने की कामना करते हैं, तब आप कुछ बनने की भाषा में सोच रहे होते हैं, और जो कुछ बनने की प्रक्रिया में है, वह उसे नहीं जान सकता, जो विद्यमान है। सत्य है क्षण-प्रतिक्षण होना। प्रसन्नता, सुख-शांति अस्तित्व की, होने की वह अवस्था है, जो कालातीत है। समय से परे की इस अवस्था का आगमन तभी होता है, जब गहन असंतुष्टि होती है- वह असंतुष्टि नहीं, जिसने पलायन करने का कोई तरीका, कोई रास्ता खोज रखा हो, अपितु ऐसी असंतुष्टि, जिससे कोई निकास, कोई पलायन है ही नहीं; जिसमें किसी तृप्ति-तुष्टि की तलाश रही ही नहीं। परम असंतुष्टि की उस स्थिति में ही यथार्थ अभिव्यक्त होता है। वह यथार्थ क्रय-विक्रय के लिए नहीं है, दोहराने के लिए नहीं है। उसे पुस्तकों में बांधा नहीं जा सकता। उसे क्षण-प्रतिक्षण पाना होता है, मुस्कराहट में, आंसू में, सूखे पत्ते में, आवारा विचारों में, प्रेम की परिपूर्णता में।

प्रेम सत्य से भिन्न नहीं है। प्रेम वह अवस्था है, जिसमें विचार की प्रक्रिया का समय के तौर पर पूर्णतया अवसान हो गया है। जहां प्रेम होता है, आधारभूत परिवर्तन हो जाता है।

प्रेम सत्य से भिन्न नहीं है। प्रेम वह अवस्था है, जिसमें विचार की प्रक्रिया का समय के तौर पर पूर्णतया अवसान हो गया है। जहां प्रेम होता है, आधारभूत परिवर्तन हो जाता है। प्रेम के अभाव में क्रांति का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तब क्रांति का अर्थ केवल विनाश और क्षय होगा। जहां प्रेम है, वहीं क्रांति है, क्योंकि प्रेम है क्षण-क्षण होने वाला रूपांतरण, आमूल परिवर्तन।

जे कृष्णमूर्ति

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

जलवायु संकट से लड़ने के लिए हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। अक्षय ऊर्जा क्रांति की वजह से स्वच्छ ईंधन वाली अर्थव्यवस्था का वादा अब कल का वादा नहीं रहा, बल्कि यह आज के विकास का इंजन बन गया है।

हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात का दोषी कौन

जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है, दीपावली की रात से बिगड़ी प्रदूषण की स्थिति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बद से बदतर होती जा रही है। वायु गुणवत्ता में लगातार गिरावट के कारण अब सांस लेना दूभर होने लगा है। एक्यूआई की तरह ही दिल्ली वालों की मायूसी भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वे यही पूछ रहे हैं कि अब कहां जाएं हम? सुबह की सैर तो छोड़िए, प्रदूषण घर में घुसकर मार रहा है। इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? जिस सरकार पर दिल्ली की हवा को प्रदूषण से बचाने की पहली जिम्मेदारी है, उसने खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर पटाखे चलाने की इजाजत मांगी और सिर्फ हरित पटाखे छोड़े जाएं, यह सुनिश्चित करने में बुरी तरह नाकाम रही।

विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ का पीएम10 सांद्रता के लिए दैनिक दिशा-निर्देश 45 माइक्रोग्राम/ प्रति घनमीटर है, जबकि दिल्ली में सोमवार को पीएम10 की सांद्रता 583 माइक्रोग्राम/ प्रति घनमीटर आंकी गई। इसी तरह, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से 400 के बीच दर्ज किया गया, जो बहुत खराब से गंभीर प्रदूषण की स्थिति को दिखाता है। आस-पास के शहरों में भी स्थिति बेहतर नहीं रही है। फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और नोएडा में भी बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में आते हैं। सोमवार सुबह-सुबह भी दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर स्तर तक पहुंच गई थी। आमतौर पर 100 या उससे कम एक्यूआई मान संतोषजनक माना जाते हैं। जैसे ही यह 100 से ऊपर होता है, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता जाता है। कई रिपोर्टों से यह पुष्ट हो चुका है कि वायु प्रदूषण के कारण देश में हर साल करीब 20 लाख लोग काल के गाल में समा रहे हैं।

दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठकें कर रही है और पराली जलाने को लेकर चेतावनी दे रही है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से कृत्रिम बारिश की कोशिश, भारी वाहनों पर रोक, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण और एंटी-स्मॉग गन के इस्तेमाल जैसे कदमों के बावजूद हालात में ज्यादा सुधार नहीं दिख रहा है, तो यह साफ हो जाना चाहिए कि दिल्ली में प्रदूषण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा के स्तर पर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आरोप है कि जहां-जहां वायु गुणवत्ता दर्ज करने वाली मशीनें लगी हैं, वहीं-वहीं जल के छिड़काव ज्यादा किए जा रहे। ऐसे दिखावों से यह मुश्किल जंग नहीं जीती जा सकती। जरूरी है कि दिल्ली सरकार और पूरा सिस्टम इसको गंभीरता से ले।

आकाश, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
वायु प्रदूषण

फिर सामने आया मध्यवर्ग का दोहरापन

इससे भला कौन इनकार कर सकता है कि राजधानी दिल्ली की आबोहवा साफ नहीं है? दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक छोटे-छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मगर इसके लिए सरकार और तंत्र को कोसने का जैसे रिवाज चल पड़ा है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या इस स्थिति के लिए सिर्फ सरकार दोषी है?

दिल्ली में लगभग 80 लाख चौपहिया वाहन हैं। एक-एक कोठी के आगे आप चले जाएं, भिन्न-भिन्न तरह की कारें आपको अंदर ही नहीं, बाहर सड़क पर खड़ी मिलेंगी। जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ये तमाम गाड़ियां राजधानी की हवा को दूषित ही नहीं करतीं, वे सड़कों का अतिक्रमण भी करती हैं और दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ाती हैं, क्योंकि कई बार नाबालिग भी इनको लेकर सड़कों पर उतर आते हैं। किसी भी समस्या को लेकर सरकार को घेरना और तपाक से नेताओं पर आरोप जड़ देना आसान है, मगर क्या ऐसा करने वाले लोग नागरिक कर्तव्य का पालन करते हैं? सरकार तो काफी समय से मना कर रही है कि इन दिनों में, खास तौर पर सूखे पत्ते न जलाएं, प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल न करें और किसान खेतों में पराली न जलाएं, मगर क्या हम सरकार का कहना मान रहे हैं? अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखे छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तमाम पर्यावरण विज्ञानियों ने मना किया कि पटाखे न जलाएं, इससे वायु प्रदूषण बहुत गहरा जाता है, फिर किसने जिद ठानी कि नहीं, हमें हरित पटाखे जलाने की छूट दी जाए?

दुनिया में कोई भी समस्या कभी सुलझाई नहीं जा सकती, अगर व्यापक जन-समुदाय का सहयोग न हो। हमारे पुरखों ने कारसेवा के जरिये ताल-तलैया बनाए, बाग-बगीचे लगाए और समाज को जिम्मेदारी सौंपी कि वह इनकी साफ-सफाई और हरियाली का ख्याल करे। हमने क्या किया? तालों को पाट दिया या उसे कचरे का कुंड बना दिया। बाग उजाड़ दिए गए या फिर समेट दिए गए। आर्थिक संपन्नता आने के बाद सबसे पहला काम लोग क्या करते हैं, वे विवेक का त्याग करते हैं। आडंबर और दिखावे ने पूरे वातावरण को दूषित किया है। निस्संदेह, सरकारों की भी गलती है। उन्होंने सख्ती नहीं बरती। मगर जब कभी वे सख्ती बरतती हैं, इसे उनका दमन-चक्र करार दे दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सख्त आदेश पारित करने पड़े। इसलिए प्रदूषण की समस्या का हल तभी होगा, जब लोग दूसरों से त्याग और संयम की अपेक्षा छोड़कर खुद इनको अपनाएंगे।

वेदना सिंह, टिप्पणीकार

नए आधार ऐप से क्यूआर कोड दिखाकर विवरण साझा कर सकेंगे

सुविधा

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार ऐप लॉन्च किया गया है। इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए इसमें फेस ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉक जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसकी मदद से क्यूआर कोड दिखाकर अपना आधार विवरण साझा किया जा सकेगा। साथ ही एक ही फोन में पांच आधार विवरण सुरक्षित किए जा सकते हैं।

प्राधिकरण के अनुसार, इस ऐप को एंड्रॉयड और आईफोन उपयोगकर्ता दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं। यह कई भाषाओं में उपलब्ध होगा। नया ऐप आधार की जानकारी डिजिटल प्रारूप में रखने की सुविधा देगा। इससे हर जगह आधार कार्ड की कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि, आधार धारक पहले से ही पीडीएफ प्रारूप या डिजीलॉकर के माध्यम से इसे रख सकते हैं, लेकिन नया ऐप उपयोगकर्ता को अपनी जानकारी साझा करने का पूरा नियंत्रण देता है।

पुराने ऐप से अलग कैसे: इससे पहले उपयोगकर्ता पुराना mAadhaar ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इसमें कुछ सुविधाएं मौजूद नहीं थी। इनमें डिजिटल कार्ड डाउनलोड करना, पीवीसी कार्ड के लिए अनुरोध भेजना, ईमेल और मोबाइल सत्यापित करना और वर्चुअल आईडी जनरेट करना शामिल है। नए ऐप में इन्हें जोड़ा गया है?

ये सहूलियतें जोड़ी गईं

चेहरे से तुरंत सत्यापन
1 इस ऐप में फेस आईडी तकनीक जोड़ी गई है, जिससे उपयोगकर्ता सिर्फ अपने चेहरे को स्कैन करके आधार सत्यापन कर सकते हैं। इससे ओटीपी या बायोमेट्रिक उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

क्यूआर कोड से शेयरिंग
2 भारतीय नागरिक क्यूआर कोड से डिजिटल आधार साझा कर सकेंगे। अब आधार कार्ड की कॉपी पास रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

पूरा नियंत्रण
3 लोग खुद तय कर सकेंगे कि आधार की कौन सी जानकारी सामने वाले को दिखानी है और कौन सी नहीं। उदाहरण के लिए नाम और फोटो साझा कर सकते हैं लेकिन पता, जन्मतिथि छिपा सकते हैं।

बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक
4 ऐप में बायोमेट्रिक जानकारी लॉक और अनलॉक करने की सुविधा जोड़ दी गई है। उपयोगकर्ता अपने फिंगरप्रिंट और फेस डाटा से को लॉक कर सकता है ताकि कोई और शख्स इसका इस्तेमाल न कर सके।

उपयोग हिस्ट्री
5 आधार का इस्तेमाल कहां और कब-कब हुआ, इसका पूरा विवरण ऐप में देखा जा सकेगा।

परिवार को जोड़ सकेंगे
6 नए ऐप में परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इससे परिवार के हर सदस्य के दस्तावेज तक पहुंच एक क्लिक में संभव हो सकेगी।

ऐसे करें इस्तेमाल

- सबसे पहले स्टोर या ऐप स्टोर से Aadhaar App डाउनलोड करें।
- पसंदीदा भाषा चुनें और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। ऐप आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर से एसएमएस भेजने के लिए कहेगा।
- ओटीपी करने के बाद चेहरे का सत्यापन करने के लिए कहा जाएगा। इसे पूरा करने के बाद छह अंकों का पासवर्ड दर्ज करें।
- इसके बाद ऐप के प्रोफाइल पेज पर आपका आधार कार्ड देख दिख जाएगा।
- अब इसमें चुनिंदा जानकारियों को छिपा सकते हैं और बायोमेट्रिक लॉक जोड़ सकते हैं।
- यही प्रक्रिया दोहराकर और चार आधार विवरण जोड़ सकते हैं।

बाजार 30s

शेयर बाजार

सेंसेक्स		निफ्टी	
83,535	+310.07	25,574	+82.05

कमोडिटी

	भाव	बदलाव
सोना	1,25,900	+1,300
चांदी	1,55,760	+2,460

करेंसी
डॉलर/रुपया
88.73 -0.08

अमेरिका ने भारत का दावा खारिज किया

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत के इस दावे को खारिज किया है कि वाशिंगटन का तांबे पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाना, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों के तहत रक्षोपाय है। अमेरिका ने कहा कि उसकी वस्तुओं पर शुल्क रियायतों को निलंबित करने के भारत के प्रस्ताव का कोई आधार नहीं है। ये शुल्क एक अगस्त को लगाए गए थे। भारत ने सितंबर में डब्ल्यूटीओ के सुरक्षा समझौते के तहत इस मामले पर अमेरिका से परामर्श की मांग की है।

व्यापार वार्ता में इस्पात को शामिल करने का आग्रह

कोलकाता। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन निकाय ईईपीसी इंडिया ने अमेरिका के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत में इस्पात और एल्युमीनियम उत्पादों को शामिल करने का आह्वान किया है। ईईपीसी इंडिया ने कहा कि खासतौर से छोटे और मझोले उद्योगों से संबंधित इस्पात उत्पादों को व्यापार वार्ता में शामिल करना चाहिए। निकाय ने यूरोपीय संघ के साथ वार्ता में मौजूदा शुल्क ढांचे को बनाए रखने की वकालत भी की है।

ट्राई इंटरकनेक्शन नियमों की समीक्षा करेगा

मुंबई। दूरसंचार नियामक ट्राई सभी नौ मौजूदा इंटरकनेक्शन नियमों की समीक्षा कर रहा है। उसने उपग्रह-आधारित दूरसंचार नेटवर्क के लिए अन्य दूरसंचार नेटवर्कों के साथ इंटरकनेक्ट ढांचे सहित कई पहलुओं पर संबंधित पक्षों के सुझाव मांगे हैं। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने कहा कि कुल मिलाकर, समीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नियामकीय ढांचा प्रौद्योगिकी के विकास और दूरसंचार क्षेत्र में बदलावों को ध्यान में रखे।

धोखाधड़ी वाली योजनाओं के खिलाफ नए पोर्टल की शुरुआत

फर्जी निवेश में फंसे हैं तो 'सचेत' पर करें शिकायत

कवायद

नई दिल्ली, एजेंसी। डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ने के साथ-साथ वित्तीय धोखाधड़ी के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में आम लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सचेत पोर्टल नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा दी है, जहां कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी वाले मामलों की शिकायत आसानी से दर्ज कर सकता है।

पोर्टल का उद्देश्य लोगों को फर्जी निवेश योजनाओं, अवैध चिट फंड, अनधिकृत वित्तीय कंपनियों और धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक करना और शिकायतों का समाधान तेजी से करना है। शिकायत दर्ज होने पर इसे तुरंत संबंधित विभाग या नियामक संस्था को भेज दिया जाता है। इनमें सेबी, इरडा, राष्ट्रीय आवास बैंक, पीएफआरडीए, राज्य सरकारें और पुलिस विभाग शामिल हैं।

शिकायत के सभी लिंक एक जगह: इस पोर्टल पर सभी प्रमुख वित्तीय शिकायत प्लेटफॉर्म के लिंक एक ही जगह उपलब्ध कराए गए हैं। उदाहरण के लिए, साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर शिकायत सीधे राष्ट्रीय साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा, आप तत्काल सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर शिकायत म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर या निवेश योजना से जुड़ी हो, तो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर जाकर दर्ज की जा सकती है। बीमा कंपनियों के खिलाफ शिकायतें इरडा द्वारा देखी जाती हैं, जबकि पेंशन योजनाओं की शिकायतें पीएफआरडीए के पास भेजी जाती हैं।

नियामक का ब्योरा भी उपलब्ध

सचेत पोर्टल की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यदि आपको यह पता नहीं कि आपकी शिकायत किस रेगुलेटर के अधीन आती है, तो 'नियामक की जानकारी नहीं' विकल्प पर क्लिक करके सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आरबीआई की टीम आपकी शिकायत सही विभाग तक पहुंचा देती है और आगे कार्रवाई शुरू हो जाती है।

शिकायत की प्रक्रिया काफी सरल

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी काफी सरल है। वेबसाइट पर जाकर 'शिकायत दर्ज करनी है' टैब पर क्लिक करें। इसके बाद कंपनी का नाम, स्कीम की जानकारी, आपकी समस्या का विवरण और मोबाइल नंबर भरना होता है। शिकायत दर्ज होते ही आपको एक संदर्भ संख्या दी जाती है।

यहां भी कर सकते हैं शिकायत

अगर आप साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो तुरंत टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल और दूरसंचार विभाग का चक्षु पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

सोना-चांदी के दाम में आया तेज उछाल

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया। सोना 1,300 रुपये बढ़कर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,460 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,760 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार करती दिखी।

विशेषज्ञों का कहना है कि कमजोर डॉलर और वैश्विक स्तर पर अनिश्चित आर्थिक संकेतों ने सोने को मजबूती दी है।

ई-खरीदारी में जान पाएंगे किस देश का है उत्पाद

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। जल्द ही आपको ई कॉमर्स मंचों पर खरीदारी करते वक्त यह पता लगाने में देर नहीं लगेगी कि जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं, वह कहां की बनी हुई है।

इसके साथ आप अपनी पसंदीदा मुल्क की बनी हुई वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। इससे मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को भी बल मिलेगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स मंचों के लिए पैकेटबंद वस्तुओं के लिए मूल देश के आधार पर खोज योग्य और क्रमबद्ध फिल्टर प्रदान करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

इस कदम से ऑनलाइन खरीदारी में उपभोक्ता के सशक्तीकरण के साथ पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ई-कॉमर्स को उत्पाद के साथ मूल देश के लिए फिल्टर प्रदान करना होगा।

एसबीआई ने एटीएम निकासी शुल्क बढ़ाया

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय स्टेट बैंक ने एक दिसंबर 2025 से एटीएम और ऑटोमेटेड डिपॉजिट कम विदड्रॉल मशीन ट्रांजेक्शन के सेवा शुल्क में बदलाव करने की घोषणा की है।

बैंक ने कहा कि इंटरचेंज फीस बढ़ने के कारण नए शुल्क लागू किए जा रहे हैं। पहले वेतन खाताधारकों के खातों में सभी एटीएम लेन-देन पूरी तरह निःशुल्क थे, लेकिन अब केवल 10 लेन-देन मुफ्त होंगे। इसके बाद नगद निकासी पर 23 रुपये जीएसटी के साथ लगेंगे।

गैर-वित्तीय लेन-देन पर 11 रुपये जीएसटी के साथ लगेंगे। इसी तरह से चालू खाताधारकों को पहले की तरह कोई निःशुल्क लेन-देन नहीं मिलेगा। नए बदलाव के तहत बचत खाता धारक ग्राहकों को हर महीने पांच मुफ्त लेन-देन मिलेंगे, लेकिन निःशुल्क सीमा के बाद शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। नकद निकासी पर शुल्क 21 से बढ़कर 23 और साथ में जीएसटी लगेगा। गैर-वित्तीय लेन-देन पर शुल्क 10 से बढ़कर 11 होगा और साथ में जीएसटी लगेगा।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीति लाई जाए

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में अर्थशास्त्रियों के साथ सोमवार से बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू कर दी है।

पहले दिन दो बैठक आयोजित की गई, पहली बैठक में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के साथ आर्थिक मामलों का विभाग से कई वरिष्ठ अधिकारी और अर्थशास्त्री शामिल हुए जबकि दूसरी बैठक में किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र जुड़े कई अर्थशास्त्री शामिल हुए।

बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों से बजट से जुड़ी नीतिगत प्राथमिकता, भविष्य में विकास की रणनीति, वित्तीय स्थिरता से लेकर प्राथमिकता वालों क्षेत्रों को लेकर चर्चा की गई।

रुपया आठ पैसे गिरकर 88.73 प्रति डॉलर पर

मुंबई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव में सोमवार को अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार के सुस्त कारोबारी सत्र में रुपया आठ पैसे गिरकर 88.73 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

श्रम योग्य कार्यबल में बेरोजगारी दर तिमाही में कम हुई

नई दिल्ली, एजेंसी। त्रैमासिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार सितंबर में तिमाही में देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की श्रम बल में भागीदारी मामूली सुधार के साथ 55.1% पर पहुंच गई।

इस दौरान इस वर्ग की आबादी में बेरोजगारी 0.2 प्रतिशत घट कर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आ गई। इस वर्ष अप्रैल जून तिमाही में श्रम योग्य आबादी के 55.0% लोग समग्र रूप से श्रम बल में शामिल थे।

इंटर्नशिप योजना की अवधि घटाने की तैयारी हो रही

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

सूत्रों का कहना है कि, इंटर्नशिप की मौजूदा 12 महीने की अवधि को घटाने पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालय का कहना है कि मिले फीडबैक के अनुसार, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आवेदक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की पेशकश स्वीकार नहीं कर रहे या इंटर्नशिप में शामिल नहीं हो रहे हैं।

उत्तर रेलवे

शुद्धिपत्र

संदर्भः 1. टेंडर नोटिस संख्या 48/2025-26. दिनांक 23.09.2025. क्रम सं0. 6
2. टेंडर संख्या. 08255011 नियत तिथि 10/11/2025
देय तिथि बदल दी गई है अर्थात 10.12.2025. अन्य सभी नियम व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
यह शुद्धिपत्र वेबसाइट पर मुद्रित किया गया है। **www.ireps.gov.in.**
ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ 3488/25

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ

संख्या :-11 /19/विज्ञापन अनुभाग/2016-25/18(5)2016
लखनऊः दिनांक-08 नवंबर, 2025
विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या-18(5)/2016 के अंतर्गत विज्ञापित आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश, उद्योग निदेशालय, कानपुर के नियंत्रणाधीन सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 16 पदों के सापेक्ष शार्टलिस्टिंग की कार्यवाही के उपरान्त साक्षात्कार के लिये अर्ह/औपबंधिक रूप से अर्ह कुल 92 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार **दिनांक 20-11-2025** को **उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकप भवन, तृतीय तल, विभूतिखंड, गोमती नगर, लखनऊ** में आयोजित किये जाने सम्बन्धी आयोग की आवश्यक सूचना **संख्या-186/06/कम्प्यूटर अनुभाग(बारह)/2018-25/18(5)2016, दिनांक 04 नवंबर, 2025** को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गयी है।

तदनुक्रम में प्रश्नगत पद हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पदों पर चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित किये जाने एवं प्रत्यावेदन उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी विस्तृत सूचना तथा साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।
UP 240166 Dt. 10.11.2025
Website: www.upgov.nic.in

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
ई-निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक WRS-R-25-26-OT-SS-wagon दिनांकः 06/11/2025
कार्य का नाम : खुली निविदा के माध्यम से डब्ल्यूआरएस/रायपुर के परिसर के भीतर "किसी भी प्रकार के एसएस बॉडी वैगनों की स्ट्रिपिंग, फिटिंग और वेल्डिंग **अनुमानित निविदा मूल्यः** रुपये 17,85,97,018.52 (रुपये सत्रह करोड़ पचासी लाख सत्तानवे हजार अठारह बावन मात्र) 18% जीएसटी सहित । **मात्रा और संविदात्मक अवधि :** संलग्नक के अनुसार, 24 (चोबीस) माह की अवधि के लिए। **बयाना राशि (रु.) :** Rs. 10,43,000.00 /- (रुपये दस लाख तैंतालीस हजार मात्र) **निविदा प्रपत्रों की लागत (रु.) :** शुन्य **निविदा समाप्ति तिथि और समय :** 28/11/2025 12:00 बजे **बिड प्रारंभ की तारीखः** 14/11/2025 **पात्रता मापदंडः** वेबसाइट पर देखा जा सकते हैं।
इस निविदा के विरुद्ध मैनुअल प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। निविदा का पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
उप. मुख्य यांत्रिक अभियंता वैरिशा
द.पू.म.रेलवे./ रायपुर
PR/R/WRS/AAA/209
South East Central Railway @secrail

पूर्वोत्तर रेलवे
विद्युत लोको शेड गोरखपुर
भारत के राष्ट्रपति की ओर वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर/टीआरएस/गोरखपुर, विद्युत लोको शेड गोरखपुर/पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नामः निविदा सूचना संख्याः **ELS-GKP-AUX-2025** "कन्वेन्शनल तथा 3 फेज लोकोमोटिव के आग्जिलरी मोटरो की मरम्मत और ओवरहॉलिंग" **अनुमानित लागत (रु. में) :** ₹43,46,256.80 **अग्रिम धन (रु. में):** ₹86,900.00 **निविदा प्रपत्र का मूल्यः** ₹00.00 **निविदा की अवधिः** 24 माह। ● ऑफर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 12.12.2025, 12:00 बजे तक एवं यह ई-निविदा 12.12.2025 को 12:00 बजे के बाद खोली जाएगी। ● इस ई-निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी, न्यूनतम आहर्ताएं तथा नियम एवं शर्तें, रेलवे की वेबसाइट, www.ireps.gov.in. पर उपलब्ध है। ● निविदाकार, ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस निविदा से संबंधित शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) को वेबसाईट पर संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
मं0वि0इंजी0/टीआरएस
विद्युत लोको शेड/
गोरखपुर
मुजाधि/विद्युत-180
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

पूर्वोत्तर रेलवे
निविदा सूचना संख्या-12 दिनांकः30.10.25
ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा आमंत्रण
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर कृते भारत के राष्ट्रपति तथा उनकी ओर से ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निम्नलिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। सामग्री का पूर्ण विवरण तथा नियम एवं शर्तें वेबसाईट www.ner.indianrailways.gov.in & www.tendrs.gov.in पर देखा जा सकता है। **क्र0 सं0: 1 निविदा संख्या एवं खुलने की तिथिः** 10245423 Corrigendum Dt. 13.11.2025 **मद का संक्षिप्त विवरणः** रेडिअल ड्रिलिंग मशीन विदाउट AMC इत्यादि। **मात्राः 03** Set **अर्नेस्ट मनी (रुपया):** 1,58,070/- 1 उपरोक्त निविदा आईआरईपीएस के साइट http/www.ireps.gov.in पर स्थित है। जो पतिष्ठान इलेक्ट्रानिकली पंजीकृत है वे ई-टेण्डर में सम्मिलित हो सकते हैं। जो प्रतिष्ठान क्लास 3 डिजिटल सर्टिफिकेट नही प्राप्त किये है वे अधिकृत एजेन्सी जो भारत सरकार के द्वारा अधिकार पत्र आईटी अधिनियम 2000 से अधिकृत है उनसे प्राप्त कर सकते है। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नही की जायेगी। 2. आपूर्तिकर्तागण को यह सूचित किया जाता है कि उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर विज्ञापित निविदाएं एवं सभी बलेटिन निविदाएं केवल ईपीएस (ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम) द्वारा खोली जा रही है, जो भी प्रतिष्ठान उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की निविदाओं के प्रति इच्छुक हो एवं भाग लेना चाहते हो उन्हे आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा एवं अपने प्रतिष्ठान को CRIS/NEW DELHI. में पंजीकृत कराना होगा। इस सम्बंध में आवश्यक विस्तृत विवरण वेबसाइट http//www.ireps.gov.in. से प्राप्त किया जा सकता है। 3. निविदा सूचना के अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रकाशन में भिन्नता होने की स्थिति में अंग्रेजी प्रकाशन मान्य होगा। 4. एलोकेशन शीर्ष निविदा प्रपत्र, जमानती धनराशि का 00844517 तथा बयाना धनराशि का 00084506 हैं। उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर द्वारा प्रकाशित ई0 निविदाओं का टेण्डर काश्ट तथा ईएमडी का भुगतान ऑन-लाइन IREPS PORTAL पर ही मान्य होगा जो दिनांक 01.09.2016 से या उनके बाद प्रकाशित निविदाओं पर प्रभावी होगा। यह Global tender पर प्रभावी नही होगा।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/डिपो
गोरखपुर
मुजाधि/स्टोर-58
ट्रेनों में बीड़ी/सिगरेट न पियें

आयुक्त, कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : civil.ctd@mp.gov.in वेबसाईट : www.tribal.mp.gov.in
निविदा आमंत्रण सूचना
क्रमांक/निर्माण/2025-26/23040 भोपाल, दिनांक : 06.11.2025
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न निर्माणाधीन एवं नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों के संपादन हेतु आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एवं डी.पी.आर. कन्सल्टेंसी तथा पी.एम.सी. (क्वालिटी कंट्रोल सहित) कार्य हेतु कंसल्टेंसी की स्थापना हेतु स्थापित अनुभवी एवं पंजीकृत कंपनी / फर्म से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम	सिविल कार्य लागत की संभावित राशि (करोड़ में)	अनुबंध की संभावित राशि (करोड़ में)	EMD राशि (लाख में)	निर्धारित समय अवधि
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संभाग नर्मदापुरम, शहडोल, उज्जैन, चंबल, ग्वालियर, भोपाल, सागर और रीवा जोन के निर्माण कार्यों हेतु आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, डी.पी.आर. एवं परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी का कार्य।	234.78	3.98	12.00	24 Months

1. इच्छुक फर्म / कम्पनी MP Tenders के पोर्टल पर विवरण देख सकते हैं।
2. NIT (निविदा आमंत्रण सूचना) में किसी प्रकार के परिवर्तन सूचना केवल www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।
3. निविदा प्रपत्र की उपलब्धता का विस्तृत विवरण : www.mptenders.gov.in में देखा जा सकता है।
4. प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया केवल उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
5. संशोधन/परिशिष्ट/स्पष्टीकरण/शुद्धि पत्रक केवल www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।
6. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
भोपाल म.प्र.
जी-21280/25 "पॉक्सो है सुरक्षा का हथियार, बच्चों पर न करें अत्याचार"

आयुक्त, कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल (म.प्र.)
ई-मेल : civil.ctd@mp.gov.in वेबसाईट : www.tribal.mp.gov.in
निविदा आमंत्रण सूचना
क्रमांक/निर्माण/2025-26/23039 भोपाल, दिनांक : 06.11.2025
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न निर्माणाधीन एवं नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों के संपादन हेतु आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एवं डी.पी.आर. कन्सल्टेंसी तथा पी.एम.सी. (क्वालिटी कंट्रोल सहित) कार्य हेतु कंसल्टेंसी की स्थापना हेतु स्थापित अनुभवी एवं पंजीकृत कंपनी / फर्म से निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

कार्य का नाम	सिविल कार्य लागत की संभावित राशि (करोड़ में)	अनुबंध की संभावित राशि (करोड़ में)	EMD राशि (लाख में)	निर्धारित समय अवधि
जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संभाग जबलपुर जोन के निर्माण कार्यों हेतु आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, डी.पी.आर. एवं परियोजना प्रबंधन कंसल्टेंसी का कार्य।	235.31	3.98	12.00	24 Months

1. इच्छुक फर्म / कम्पनी MP Tenders के पोर्टल पर विवरण देख सकते हैं।
2. NIT (निविदा आमंत्रण सूचना) में किसी प्रकार के परिवर्तन सूचना केवल www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी।
3. निविदा प्रपत्र की उपलब्धता का विस्तृत विवरण : www.mptenders.gov.in में देखा जा सकता है।
4. प्रस्ताव जमा करने की प्रक्रिया केवल उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।
5. संशोधन/परिशिष्ट/स्पष्टीकरण / शुद्धि पत्रक केवल www.mptenders.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे।
6. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

आयुक्त
जनजातीय कार्य
भोपाल म.प्र.
जी-21250/25 "पॉक्सो है सुरक्षा का हथियार, बच्चों पर न करें अत्याचार"

LOKPAL OF INDIA

Advertisement

Lokpal of India is conducting Essay/Slogan/Poster/Sketch writing competitions for observing International Anti-Corruption Day of 2025, on 09th December, 2025 as per the details given below:

Essay writing competition

Category 1: Students up to Class XII
Theme: "Greed breeds Corruption"

Category 2: Students of College (Graduate) level and above
Theme: "Global vis-à-vis National anti-corruption movements"

Slogan writing competition

Theme: "Anti-corruption drive"

Poster/Sketch making competition

Theme: "Eradication of Corruption"

The first two (2) winners in each category will be **felicitated on the 16th of January, 2026,** on the occasion of the **Lokpal Foundation Day.**

The last date of submission of essays is 9th December, 2025. For further details, please visit Lokpal of India's website Lokpal https://lokpal.gov.in/

हमें वैश्वीकरण को पर्यावरण अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। -सिगमार गेब्रियल

तीव्र जलवायु प्रभावों और ऐतिहासिक पेरिस समझौते की राह में मौजूद भारी चुनौतियों के मद्देनजर ब्राजील के बेलेम में शुरू हुआ संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का तीसवां सम्मेलन कॉप-30 एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, बशर्ते यह औपचारिक वादों से आगे बढ़ सके।

वादों से आगे

भीषण गर्मी, बेमौसम बारिश व मौसम के असामान्य रवैये जैसे जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों और इन्हें लेकर वैश्विक निष्क्रियता की पृष्ठभूमि में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) का तीसवां सम्मेलन कॉप-30 कल से ब्राजील के बेलेम में शुरू हुआ है, जिसका प्रतीकात्मक महत्व है। दरअसल बेलेम, जो अमेजन वर्षावनों का प्रवेश द्वार होने के साथ ही धरती पर जैव-विविधता के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, वनों की अवैध कटाई की वजह से खतरे में है। यह भी उल्लेखनीय है कि दुनिया के विभिन्न देश जलवायु में आ रहे बदलावों की गति को धीमी करने पर चर्चा करने के लिए ब्राजील के उत्तरी शहर में एकत्रित हुए हैं, जबकि यहीं का दक्षिणी राज्य पराना बीते दिनों आए तूफान से हुई क्षति से जूझ रहा है। गौरतलब है कि यूएनएफसीसीसी के सदस्य देशों द्वारा पेरिस समझौते को अपनाए एक दशक बीत चुका है, जो कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता था, जिसके तहत सदस्य देश औसत सतही तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए प्रतिबद्ध हुए थे। हालांकि, वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि जारी है और वादों व व्यवहार के बीच खाई और चौड़ी हो रही है। पिछले दस वर्षों में बाढ़, आंधी-तूफान और चक्रवातों से आई तबाही और 2024 की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जलवायु परिवर्तन के असर स्पष्ट हैं। कॉप-30 से पहले जारी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की हालिया रिपोर्ट कहती है कि विकासशील देशों को चिलचिलाती गर्मी और घातक तूफानों से बचाने के लिए अब से लेकर 2035 के बीच सालाना 310 अरब डॉलर की जरूरत होगी। ऐसे में, कॉप-30 की सर्वोच्च प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि वह जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सदस्य देशों की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक रोडमैप तैयार करे। कॉप-30 के मंच पर सभी देशों को इस बात पर एकमत होना भी जरूरी है कि सामाजिक असमानताओं कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में ज्यादा असुरक्षित बनाती

हैं। दरअसल, बेलेम सम्मेलन के निष्कर्ष यह निर्धारित करने में मददगार होंगे कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय अब भी उत्सर्जन के वक्र को मोड़ सकता है और क्या भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत रहते हुए आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जगह और समर्थन प्राप्त कर सकती हैं? कॉप अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति का केंद्र बिंदु है, जहां तीस से भी ज्यादा वर्षों में, रियो से लेकर क्योटो और पेरिस तक, दुनिया के देश महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमत हुए हैं। बेशक पेरिस समझौता जलवायु कार्रवाई को मुख्यधारा में लाया, लेकिन इस समझौते के कार्यान्वयन की राह में मौजूद चुनौतियों और तीव्र जलवायु प्रभावों के मद्देनजर बेलेम सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है।

वैश्वीकरण की रफ्तार थमने के मायने

ट्रंप की वैश्वीकरण विरोधी टैरिफ नीतियों ने दुनिया की आर्थिक परेशानियों को बढ़ा दिया है, लेकिन इन संकटों की जड़ वह नहीं हैं। उनका दृष्टिकोण इस सच्चाई को सामने लाता है कि अमेरिका अब दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्ति व वैश्विक विकास के इंजन के रूप में अपने वर्चस्व के पतन की ओर बढ़ रहा है।

करीब चार सदियों से वैश्विक अर्थव्यवस्था लगातार गहराते एकीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, जिसे दो विश्वयुद्ध भी पूरी तरह से पटरी से नहीं उतार पाए। ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) का यह लंबा सफर तेजी से बढ़ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश से ताकत पाता रहा। इसके साथ ही, सरहदों के पार बड़े पैमाने पर इन्सानों की आवाजाही और परिवहन व संचार तकनीक में क्रांतिकारी तब्दीलियों ने इस पूरे सफर को नई दिशा और गति दी है।

आर्थिक इतिहासकार जे. ब्रैडफोर्ड डीलॉन्ग के अनुसार, 1990 के स्थिर मूल्यों पर मापा गया विश्व अर्थव्यवस्था का मूल्य 1650 में, जब यह कहानी शुरू होती है, 81.7 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 तक बढ़कर 70.3 खरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, यानी लगभग 860 गुना वृद्धि। यह तीव्र विकास मुख्य रूप से दो ऐसे दौरों में देखा गया, जब वैश्विक व्यापार ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी। पहला, लंबी 19वीं सदी के दौरान, यानी फ्रांसीसी क्रांति के अंत से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध की शुरुआत तक और दूसरा, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद, 1950 के दशक से लेकर 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी तक व्यापार उदारीकरण लगातार बढ़ता गया। हालांकि, अब यह विशाल वैश्वीकरण परियोजना पीछे हटती नजर आ रही है।

स्टीव शिफेरेस
मानद रिसर्च फेलो, लंदन विश्वविद्यालय

बेशक ग्लोबलाइजेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रफ्तार जरूर थमने लगी है। क्या यह जश्न मनाने का विषय है, या चिंता का? और क्या तस्वीर तब बदलेगी, जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी व्यापक आर्थिक उथल-पुथल पैदा करने वाली टैरिफ नीतियां समाप्त हो जाएंगी? लंबे समय तक *बीबीसी* के आर्थिक संवाददाता के रूप में कार्य करने के अनुभव से मैं यह कह सकता हूं कि ट्रंप के जाने के बाद भी हमारे पास डी-ग्लोबलाइज्ड भविष्य को लेकर चिंतित होने के ठोस ऐतिहासिक कारण मौजूद हैं। ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने दुनिया की आर्थिक परेशानियों को और बढ़ा दिया है, लेकिन इन संकटों की जड़ वह नहीं हैं। दरअसल, उनका दृष्टिकोण उस सच्चाई को सामने लाता है, जो दशकों से धीरे-धीरे उभर रही थी, लेकिन जिसे पहले की अमेरिकी सरकारें और दुनिया के कई अन्य देश मानने से हिचकते रहे और वह सच्चाई यह है कि अमेरिका अब दुनिया की नंबर एक आर्थिक शक्ति और वैश्विक विकास के इंजन के रूप में अपने वर्चस्व के पतन की ओर बढ़ रहा है।

वैश्वीकरण के आलोचक हमेशा से रहे हैं, लेकिन हाल तक वे दक्षिणपंथी की तुलना में मुख्यतः वामपंथी रहे हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब वैश्विक अर्थव्यवस्था अमेरिकी प्रभुत्व में तेजी से बढ़ी, कई वामपंथियों ने तर्क दिया कि वैश्वीकरण के लाभ असमान रूप से वितरित किए गए, जिससे अमीर देशों में असमानता बढ़ी, जबकि गरीब देशों को मुक्त बाजार नीतियों को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कोई नई चिंता नहीं थी। 1841 में, जर्मन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट ने तर्क दिया था कि मुक्त व्यापार ब्रिटेन के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने से रोकने के लिए बनाया गया था, और उन्होंने कहा था-जब कोई महानता के शिखर पर पहुंच जाता है, तो वह उस सीढ़ी को लात मारकर गिरा देता है, जिसके सहारे वह ऊपर चढ़ता है, ताकि अन्य लोग उसके बाद ऊपर न चढ़ पाएं।

अमेरिका में, वैश्वीकरण की आलोचना अमेरिकी श्रमिकों पर इसके घरेलू प्रभावों पर केंद्रित थी, यानी नौकरी छूटना और कम वेतन। इससे अधिक संरक्षणवाद की मांग उठी। हालांकि, शुरू में इसका नेतृत्व ट्रेड यूनियनों और कुछ डेमोक्रेटिक राजनेताओं द्वारा किया गया था, लेकिन धीरे-धीरे इसे कट्टर दक्षिणपंथियों का भी समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संगठनों को कोई भी भूमिका देने का इस आधार पर विरोध किया कि वे अमेरिकी संप्रभुता पर अतिक्रमण करते हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में, ये आलोचनाएं कट्टरपंथी व अत्यधिक विघटनकारी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में बदल गई हैं, जिनके केंद्र में टैरिफ और संरक्षणवाद है। अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा (हाई-टेक सेक्टर) चीन के भारी दबाव में है, जिसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही जीडीपी के मामले में अमेरिका से बड़ी है। इस बीच, ज्यादातर अमेरिकी नागरिकों को स्थिर आय, महंगाई और ज्यादा असुरक्षित नौकरियों का सामना करना पड़ रहा है। जब बात अमेरिका के बदले दुनिया की अग्रणी प्रभुत्वशाली शक्ति बनने की आती है, तो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले उम्मीदवार के रूप में यूरोपीय संघ और चीन ही हैं। लेकिन इस पर संदेह करने के मजबूत कारण हैं कि दोनों में से कोई भी यह भूमिका निभा सकता है। एकदलीय, अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था वह मुख्य कारण है कि चीन को लोकतांत्रिक देशों के बीच सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने में कठिनाई होगी। इस बीच यूरोप (जो वैश्विक स्तर पर अमेरिका का स्थान लेने वाला एकमात्र दूसरा दावेदार है) राजनीतिक रूप से गहराई से विभाजित है। पूर्व और दक्षिण में छोटी, कमजोर अर्थव्यवस्थाएं वैश्वीकरण के लाभों के बारे में अधिक संशयी हैं। ऐसे में, यह असंभव हो जाता है कि वर्तमान में गठित यूरोपीय संघ अपने दम पर एक नई वैश्विक विश्व व्यवस्था की शुरुआत कर सके और उसे लागू कर सके।

स्पष्ट रूप से, ट्रंप प्रशासन उन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को पुनर्जीवित करने, या यहां तक कि उनके साथ जुड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाता है, जिन पर कभी अमेरिका का प्रभुत्व था, और जिन्होंने विश्व आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में मदद की थी-जैसा कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने हाल ही में *न्यूयॉर्क टाइम्स* में तिरस्कारपूर्वक लिखा- 'हमारी वर्तमान, अनाम वैश्विक व्यवस्था, जिस पर विश्व व्यापार संगठन का प्रभुत्व है और जिसे सैद्धांतिक रूप से आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने और अपने 166 सदस्य देशों की व्यापार नीतियों को विनियमित करने के लिए तैयार किया गया है, अस्थिर और अस्थायी है। अमेरिका ने इस व्यवस्था की कीमत औद्योगिक नौकरियों और आर्थिक सुरक्षा के नुकसान के रूप में चुकाई है।'

हालांकि, अमेरिका अभी तक आईएमएफ से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उससे आग्रह किया है कि वह जलवायु परिवर्तन की चिंता को दरकिनार करते हुए, चीन के इतने बड़े व्यापार अधिशेष के लिए उसे फटकार लगाए। ग्रीर ने निष्कर्ष निकाला कि अमेरिका ने 'अपने देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जरूरतों को वैश्विक सहमति के सबसे निचले स्तर के मानक के अधीन कर दिया है।' - द कन्वर्सेशन

जीवन धारा

मेल रॉबिंस

जब आप दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपके पास वास्तव में कितनी ताकत है। जो जैसा कर रहा है, उसे वैसा करने दें और खुद पर ध्यान दें।

दूसरों की नहीं, अपनी खुशी के लिए काम करें

अगर आप अपनी जिंदगी बदलने, अपने लक्ष्य हासिल करने या ज्यादा खुशी महसूस करने के लिए जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि समस्या आप नहीं हैं। समस्या वहां है, जहां आप अनजाने में दूसरों को अपने फैसले लेने का अधिकार सौंप देते हैं। हम सब ऐसा करते हैं, अक्सर बिना परिणाम जाने। अक्सर आप मान बैठते हैं कि अगर आप सही बात कह देंगे, तो सब खुश हो जाएंगे। अगर आप खुद को हद से ज्यादा झुका लेंगे, तो शायद आपका साथी आपसे नाराज नहीं होगा। अगर आप ज्यादा मिलनसार बन जाएं, तो शायद सहकर्मी आपको ज्यादा पसंद करने लगें। अगर आप हर हाल में शांति बनाए रखें, तो शायद आपका परिवार आपकी जिंदगी के फैसलों को लेकर ताना मारना छोड़ दे।

मैं यह बात इतने पुख्ता तौर पर इसलिए कह रही हूं, क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है। वर्षों तक हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करती रही, यह सोचते हुए कि अगर मैं बस थोड़ा और कर लूं, सही बातें कहूं और सबको खुश रखूं, तो शायद मैं भी एक दिन खुद के बारे में अच्छा महसूस कर पाऊंगी। लेकिन, होता क्या है? आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद को और ज्यादा मोड़ते-बदलते हैं, अपने आप को और छोटा बनाते हैं, फिर भी कोई न कोई नाखुश रह ही जाता है, कोई न कोई आलोचना करता ही है, और अंत में आपको यही महसूस होता है कि आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें, वह कभी भी काफी नहीं होता है।

लेकिन, जिंदगी को तो हमेशा इस तरह से नहीं जिया जा सकता न। इसलिए, आप अपना वक्त, ऊर्जा और खुशियां उन बातों पर बर्बाद करना छोड़ दें, जिन्हें आप बदल नहीं सकते-जैसे, दूसरों की राय, उनका मूड या बर्ताव। इसके बजाय आप उस एक चीज पर ध्यान दें, जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। और अब जानिए सबसे हैरान करने वाली बात। जब आप दूसरों को खुश करने की जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आपके पास वास्तव में कितनी ताकत है।

इसलिए, दूसरों को बदलने या खुश करने के बजाय आपको यह सीखने का जतन करना चाहिए कि जो जैसा कर रहा है, उसे वैसा करने दें। दरअसल, जब तक आप खुद इजाजत न दें, कोई दूसरा आप पर न तो असर डाल सकता है और न ही अधिकार जता सकता है। जब आप उन बातों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं, जिन पर आपका वश नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। और अपना समय, सुकून तथा ध्यान वापस पा लेते हैं। तब आपको समझ आता है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार या राय पर नहीं, बल्कि आपके अपने कामों पर टिकी होती है। - बेस्टसेलर पुस्तक द लेट देम थ्योरी के अनूदित अंश

अपनी ऊर्जा व्यर्थ न गंवाएं

सूत्र

जीवन तब सरल और सुखद होता है, जब आप यह समझ लेते हैं कि हर किसी को खुश करना आपका काम नहीं है। दूसरों की राय, मूड या बर्ताव आपके नियंत्रण में नहीं, इसलिए उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ खर्च न करें। अपनी शक्ति अपने विचार, काम और दृष्टिकोण पर लगाएं। जब आप खुद के प्रति सच्चे रहते हैं, तभी आपको वास्तविक शांति और खुशी मिलती है।

दूसरा पहलू

मौलाना आजाद ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान न जाने की अपील की थी। विभाजन के दर्द को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब *इंडिया विन्स फ्रीडम* में उकेरा है।

मौलाना आजाद की किताब के उन 30 पन्नों का राज

जामा मस्जिद से उठती अजान की आवाज आज भी उन लोगों के कानों में गूंजती है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र पर उन्हें खिराजे अकीदत पेश करने आते हैं। मजार से जामा मस्जिद साफ दिखती है-वही मस्जिदस, जहां से 23 अक्तूबर, 1947 को मौलाना आजाद ने भारत के मुसलमानों से पाकिस्तान न जाने का आह्वान किया था। उनकी गुजारिश के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का इरादा छोड़ दिया। वह लोधी रोड रेलवे स्टेशन तक पहुंचे और लोगों से जिन्ना के पाकिस्तान न जाने की अपील की।

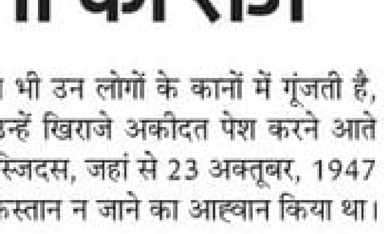

विवेक शुक्ला

उन्होंने हुमायूं कबीर से वे 30 पन्ने भी अनुवाद करवाए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित करने की अनुमति दी थी।

दरअसल, देश के बंटवारे से मौलाना आजाद टूट गए थे। विभाजन के दर्द को उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब *इंडिया विन्स फ्रीडम* में उकेरा है। दिल्ली की मौलाना आजाद रोड पर स्थित चार नंबर बंगले में, जहां अब विज्ञान भवन की एनेक्सी है, वह 1947 से लेकर 22 फरवरी, 1958 को अपनी मृत्यु तक रहे। यहीं उन्होंने 1957 में अपनी किताब पूरी की, जो 1959 में प्रकाशित हुई। रात के वक्त अक्सर नेहरू मंत्रिमंडल के जूनियर मंत्री हुमायूं कबीर उनसे मिलने आते और आजाद के लिखे पन्नों का उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद करते। सवाल यह है कि उर्दू व अरबी के इस महान लेखक ने अपनी आत्मकथा अंग्रेजी में क्यों लिखवाई।

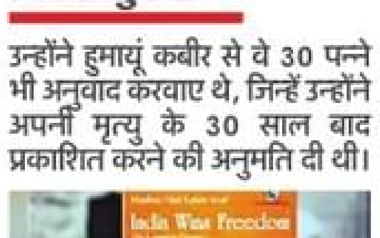

जब 1988 में उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर वे 30 पन्ने सामने आए, तो उम्मीद थी कि बड़े खुलासे होंगे, पर उनमें कुछ विशेष नहीं था। यह रहस्य बरकरार है कि उन्होंने इन्हें तीस साल तक रोककर क्यों रखा।

मौलाना ने हुमायूं कबीर से वे 30 पन्ने भी अनुवाद करवाए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी मृत्यु के 30 साल बाद प्रकाशित करने की अनुमति दी थी। *इंडिया विन्स फ्रीडम* मुख्यतः 1935 से 1947 तक की राजनीतिक घटनाओं पर केंद्रित है, जिसमें कांग्रेस की रणनीतियां, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान भारत की राजनीतिक उथल-पुथल, और अंततः विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति शामिल हैं। इसमें उन्होंने गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना के साथ अपने मतभेदों और निकटता का खुलासा भी किया है। किताब में हिंदू-मुस्लिम एकता और पाकिस्तान निर्माण की त्रासदी पर उनका दृष्टिकोण झलकता है।

नाटककार डॉ. एम सईद आलम के अनुसार, जब 22 फरवरी, 1988 को मौलाना आजाद की 30वीं पुण्यतिथि पर वे 30 पन्ने सामने आए, तो उम्मीद थी कि बड़े खुलासे होंगे, पर उनमें कुछ विशेष नहीं था। यह रहस्य बरकरार है कि उन्होंने इन्हें तीस साल तक रोककर क्यों रखा। वहीं, मौलाना आजाद के भतीजे नुरुद्दीन अहमद के पुत्र फिरोज बख्त अहमद का दावा है कि 1988 में जो पन्ने प्रकाशित हुए, वे असली नहीं थे। असली पन्नों में नेहरू पर गंभीर आरोप थे, जिन्हें राजीव गांधी सरकार ने दबा दिया। खैर, अब तो नहीं लगता कि उन 30 पन्नों का सच कभी सामने आएगा।

आंकड़े

ग्रीनहाउस गैसें

वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है।

ऊर्जा क्षेत्र	27
परिवहन	15
औद्योगिक क्षेत्र	11
कृषि	11
तेल उत्पादन	10
औद्योगिक प्रक्रम	09

आंकड़े कुल जीएचजी उत्सर्जन के, प्रतिशत में
स्रोत : उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट-2025

व्यास जी ने बताया कि अन्याय से अर्जित धन से किए गए यज्ञों से देवी-देवता रुष्ट होते हैं। शुद्ध मंत्रों व द्रव्य से किए जाने वाले यज्ञ का ही सुफल मिलता है।

देवी यज्ञ का महत्व

राजा जनमेजय एक बार वेदव्यास जी के चरणों में बैठकर सत्संग कर रहे थे। व्यास जी ने विस्तार से उन्हें भगवती देवी के विभिन्न रूपों की जानकारी दी और बताया कि सभी अवतारों तथा देवादिदेव शिवजी ने भी अनेक बार देवी की आराधना और कृपा प्राप्त करके सफलता पाई।

राजा जनमेजय ने प्रश्न किया, 'देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए?' व्यास जी ने बताया, 'यदि शुद्ध द्रव्य अर्थात पूर्ण ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित कमाई को यज्ञ में लगाया जाता है और पूर्ण शास्त्रीय विधि-विधान तथा शुद्ध मंत्रों से आहुति दी जाती है, तो यज्ञ का सुफल मिलता है। अन्याय द्वारा उपार्जित धन से यदि पुण्य कार्य किए जाएं, तो परलोक में भी उसका फल नहीं मिलता।'

व्यास जी ने बताया कि अन्याय से अर्जित धन से किए गए यज्ञों से देवी-देवता प्रसन्न नहीं, रुष्ट होते हैं। उन्होंने कहा, 'यज्ञ करने वाले को सर्वप्रथम अपने मन को काम, क्रोध, लोभ जैसे दुर्गुणों से मुक्त करके शुद्ध बनाना चाहिए। यज्ञकर्ता को इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र होने के बाद ही यज्ञ करना चाहिए।'

अंतर्यात्रा
संकलित

उन्होंने बताया, 'किसी का अहित करने के उद्देश्य से किया गया यज्ञ विनाशकारी होता है। अतः परमार्थ और धर्मरक्षार्थ ही यज्ञ करना चाहिए।' यज्ञ का महत्व सुनकर राजा जनमेजय ने विधिपूर्वक देवी-यज्ञ करने का संकल्प लिया।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 11 नवंबर, 1949

यूपी का नाम आर्यावर्त हो जाने की पूरी आशा

यू० पी० का नाम आर्यावर्त होजाने की पूरी आशा

लखनऊ, ८ नवम्बर । आज युक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रान्त के शिक्षासचिव माननीय संपूर्णानंद जी यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि प्रान्त का नाम "आर्यावर्त" कर दिया जाय । प्रधानमंत्री माननीय पंतजी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे ।

आशा की जाती है कि शिक्षासचिव का प्रस्ताव बहुमत से पास

आज युक्तप्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में प्रांत के शिक्षा सचिव माननीय संपूर्णानंद जी यह प्रस्ताव रख रहे हैं कि प्रांत का नाम 'आर्यावर्त' कर दिया जाए। माननीय पंत जी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

बढ़ती खरीदारी का दूसरा पहलू

बढ़ती खरीदारी से भले ही टैरिफ के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड का भारी उपयोग चिंता का सबब भी है।

डॉ. पीएस वोहरा | **मुद्दा**

वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ी तेजी से आगे बढ़ना अब ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य नहीं रहा है, क्योंकि यह बात सर्वमान्य हो चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी घरेलू बाजार में लगातार बढ़ रही खरीदारी है। दिवाली के त्योहार पर इसने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया, जब वर्ष 2024 की तुलना में इस समय तकरीबन 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की क्रय क्षमता में बढ़ोतरी हुई।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 की दिवाली तथा उसके आसपास के दिनों में भारत के घरेलू बाजार में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी हुई। इससे तीसरी तिमाही की विकास दर में बढ़ोतरी दर्ज होगी। और इसका आखिरी परिणाम आम लोगों के पक्ष में भी जाएगा। इस संदर्भ में यह पक्ष ध्यातव्य है कि बीते कुछ महीनों से ट्रंप की टैरिफ नीतियों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे मनोवैज्ञानिक दबाव को भी इस खरीदारी ने एक जवाब जरूर दिया है। इसमें कोई दोराय नहीं है कि मोदी सरकार के जीएसटी रेट कट की इसमें बड़ी भूमिका रही है।

भारतीय घरेलू बाजार, विश्व की सभी बड़ी कंपनियों को अपनी तरफ आकर्षित करने में भी सफल हो रहा है और इसी कारण भारतीय बाजार की उपेक्षा अब संभव नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय तकरीबन अपनी क्रय क्षमता का 32 प्रतिशत अपनी जरूरतों पर, तो करीब 29 प्रतिशत विभिन्न प्रकार की इच्छाओं पर खर्च कर रहे हैं। इस खरीदारी में लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, फैशन व मनोरंजन ने प्रमुख स्थान ले लिया है। एक रिसर्च फर्म के आंकड़ों के मुताबिक, 20,000 रुपये मासिक वेतन से लेकर 10,0000 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले लोगों की खरीदारी के बीच यह ट्रेंड अब उपभोक्ताओं की सोच में गहराई तक स्थापित हो चुका है।

लेकिन इन सब के बीच चिंता का सबब यह भी है कि इस खरीदारी का भुगतान क्या वित्तीय बचत को प्रभावित कर रहा है? क्या इस तरह की खरीदारी आम व्यक्ति के जीवन में वित्तीय ऋण को बढ़ा रही है? हकीकत में ये दोनों बातें इन दिनों भारतीय समाज में हर तरफ देखी जा रही हैं। हालांकि, यह भी एक सच है कि प्रतिवर्ष वेतन में हर जगह 10 प्रतिशत की न्यूनतम बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और महंगाई के आंकड़े इससे कम हैं। पिछले वर्ष आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक, महंगाई पांच फीसदी से थोड़ी ऊपर रही है, यानी यह वेतन बढ़ोतरी महंगाई की आंकड़ों से संघर्ष करने में सक्षम है। लेकिन अचंभित करने वाली बात यह है कि भारतीयों की खरीदारी का भुगतान अल्पकालीन वित्तीय ऋणों के माध्यम से हो रहा है, जिसमें क्रेडिट कार्ड बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है।

अप्रैल 2023 तक, करीब आठ करोड़ भारतीयों के पास क्रेडिट कार्ड थे, वहीं अप्रैल 2024 तक इसकी संख्या 25 प्रतिशत बढ़ गई। अर्थात 50 करोड़ की आबादी को (औसतन चार से पांच सदस्यों का परिवार) ये क्रेडिट कार्ड अपनी भुगतान क्षमता से प्रभावित कर रहे हैं। इसी के चलते वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हुई है। अचंभित करने वाली बात यह भी सामने आई है कि 20 हजार रुपये महीना वेतन पाने वाले व्यक्ति के जीवन में मासिक 25 प्रतिशत खर्चा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई खरीदारी पर है, वहीं 40 हजार रुपये तक तनख्वाह पाने वाले के मासिक खर्च में इसका हिस्सा 40 प्रतिशत, 75 हजार रुपये तक आय वालों के जीवन में इसका खर्चा 50 प्रतिशत से अधिक और एक लाख व उससे अधिक वेतन पाने वालों के जीवन में इसकी भागीदारी मासिक 58 से 62 फीसदी की हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हर भारतीय, खरीदारी के इस बढ़ते ट्रेंड के चलते ईएमआई के वित्तीय दबाव में फंस गया है।

इस संदर्भ में कुछ समय पूर्व आरबीआई ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। वर्ष 2006 में अमेरिका की मंदी का मुख्य कारण भी यही था कि व्यक्तियों की क्रय क्षमता वित्तीय ऋण पर निर्भर थी और वित्तीय ऋणों के भुगतान न होने पर बैंक संकट में आ गए थे। समय आ गया है कि अब भारतीय बैंक, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से होने वाली खरीदारी पर कुछ नए दिशा-निर्देश जारी करें। मसलन, छोटी मासिक आय वाले उपभोक्ताओं को महंगे उत्पादों की खरीदारी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करने पर नियंत्रण लगाया जाए। बड़े शहरों में एकाएक प्रचलन में आए हवाई यात्रा के ट्रेंड पर नियंत्रण भी जरूरी है।

ये दिशा-निर्देश इसलिए भी जरूरी हैं कि भारतीयों की वित्तीय बचत 30 प्रतिशत से कम हो गई है और इससे उनके वित्तीय निवेश, आभूषणों, जमीन, बैंक निवेश और स्टॉक मार्केट इत्यादि जीडीपी का पांच प्रतिशत ही रह गया है, जो कि बीते 50 वर्षों में सबसे कम है। अब इसका हल यही है कि भारतीयों की खरीदारी को वित्तीय ऋणों या क्रेडिट कार्ड के आवश्यक भुगतानों से बचाकर, बचत के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और आखिर में वित्तीय निवेश की तरफ मोड़ा जाए, वरना भारतीय समाज आर्थिक हताशा के दौर में चला जाएगा।

edit@amarujala.com

एजुकेशन & कॅरिअर

हार मान लेना असफलता नहीं है, बल्कि यह फिर से शुरुआत करने का मौका है।

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पदों पर करें आवेदन

5636 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 08 दिसंबर, 2025
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : sso.rajasthan.gov.in

पंजाब नेशनल बैंक में संभावनाएं ■ 750 पद

लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर रिक्तियां
आवेदन की अंतिम तिथि
23 नवंबर, 2025
पात्रताएं
स्नातक व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
pnb.bank.in

भारतीय वायु सेना में रिक्तियां ■ 340 पद

वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (एएफसीएटी)
आवेदन की अंतिम तिथि
14 दिसंबर, 2025
योग्यताएं
बारहवीं, स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें
afcat.edcil.co.in

आरआरबी ने निकाली भर्ती ■ 2569 पद

जूनियर इंजीनियर व अन्य पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 30 नवंबर, 2025
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 33 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : rrbapply.gov.in

राइट्स लिमिटेड में आवेदन आमंत्रित ■ 40 पद

मैनेजर के पदों पर योग्य उम्मीदवार करें अप्लाई
आवेदन की अंतिम तिथि
30 नवंबर, 2025
पात्रताएं
इंजीनियरिंग डिग्री व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें
rites.com

नीपको में रोजगार के मौके ■ 30 पद

एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर नौकरी के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि
17 नवंबर, 2025
वेतनमान
रुपये 50,000 से लेकर रुपये 1,60,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें
neepco.co.in

योग्य उम्मीदवार करें आवेदन ...

- डाक विभाग, संचार मंत्रालय : स्टाफ कार ड्राइवर का पद खाली।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 02 जनवरी, 2026
- indiapost.gov.in
- मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय : सहायक आयुक्त के पदों पर रिक्तियां।
  आवेदन की अंतिम तिथि : 30 नवंबर, 2025
- dof.gov.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

क्या नए संगठन में मेरी भूमिका बनी रहेगी

कॅरिअर में मुश्किलें आती रहती हैं, पर एक अच्छा पेशेवर वही है, जो अपने अनुभवों से सीखकर निर्णय लेता है

मार्लेट जैक्सन
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू

बदलाव के दौर में कार्यस्थल पर सबसे बड़ी चुनौती अनिश्चितता होती है, और यही पेशेवरों के मन में कई चिंताएं पैदा करती है। उनको लगता है कि कहीं उनका कॅरिअर रुक न जाए या वे नई स्थिति में खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं। स्वाभाविक है कि ऐसे समय में यह सवाल उठते हैं कि क्या नए संगठन में मेरी भूमिका बनी रहेगी? क्या मेरे कौशल पर्याप्त हैं? ऐसी आशंकाएं मनोबल कम कर सकती हैं और कामकाज पर भी असर डाल सकती हैं। इन चिंताओं से बाहर आने और खुद को मजबूत बनाए रखने के लिए कुछ सरल और व्यावहारिक उपाय अपनाना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, जो न सिर्फ मन को शांत रखते हैं, बल्कि आपको भविष्य के अवसरों के लिए तैयार भी करते हैं।

■ भविष्य के लिए तैयारी करें

पेशेवरों को बदलाव का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि वे नए अवसर पहचानकर अपने कॅरिअर में आगे बढ़ सकें। वे यह सीख सकते हैं कि प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारी अनिश्चित स्थितियों को कैसे संभालते हैं, जिससे मजबूत नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। बदलाव के समय पदोन्नति के मौके कम हो सकते हैं, इसलिए कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वे अपनी वर्तमान भूमिका में सीखते रहें और नए कौशल विकसित करें, ताकि भविष्य की भूमिकाओं में आसानी से फिट हो सकें। जरूरत पड़ने पर कोचिंग लेना भी मददगार होता है, क्योंकि इससे संचार कौशल, नेतृत्व शैली और टीम के साथ काम करने की क्षमता मजबूत होती है।

Harvard Business Review

■ अनुभवों को रोज के कामों से जोड़ें

पेशेवरों को विकास कार्यक्रमों के दौरान बदलती प्राथमिकताओं और रोजमर्रा के काम के दबावों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इस स्थिति में खुद को ढालने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करना जरूरी है। दिनचर्या में लचीलापन होना अच्छा है, लेकिन बिना स्पष्ट प्राथमिकताओं के यह बेअसर हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि विकास कार्यक्रमों से मिलने वाले अनुभवों को अपने रोज के काम की गति के साथ जोड़कर चलें। साथ ही, बदलते कॅरिअर में आगे बढ़ने के लिए सीमित समय में भी व्यावहारिक और उपयोगी सीख लेते रहें। आपको इन विकास पहलों को व्यवसाय और अपने कॅरिअर, दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानकर आगे बढ़ना चाहिए।

■ परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालें

परिवर्तन के समय पदोन्नति पर जोर देना आम तौर पर सही रणनीति नहीं होती, क्योंकि उस दौरान कंपनी कई बदलावों से गुजर रही होती है और निर्णय प्रक्रियाएं अस्थायी रूप से धीमी पड़ जाती हैं। ऐसे समय में बेहतर है कि आप अपने कौशल सुधारने, अपनी भूमिका में अच्छा प्रदर्शन करने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने पर ध्यान दें। जब संगठन स्थिर हो जाता है और स्थितियां स्पष्ट होती हैं, तो प्रतिभाशाली और तैयार लोग स्वाभाविक रूप से बेहतर अवसर पाते हैं और अक्सर अपने साथियों से भी आगे निकल जाते हैं।

खुद को परखें

1. दक्षिण एशिया में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला देश कौन-सा है?
   (a) बांग्लादेश
   (b) नेपाल
   (c) भूटान
   (d) म्यांमार
2. वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
   (a) महाराष्ट्र (b) तमिलनाडु
   (c) कर्नाटक (d) केरल
3. दुर्लभ सफेद आइबिस, जिसे काले सिर वाला आइबिस भी कहा जाता है, का एक झुंड हाल ही में किस राज्य में देखा गया?
   (a) महाराष्ट्र
   (b) केरल
   (c) तमिलनाडु
   (d) कर्नाटक

उत्तर-1.a, 2.b, 3.c

आवेदन आमंत्रित

लैटिनो फिल्म फेस्टिवल पोस्टर कॉन्टेस्ट

द इंटरनेशनल लैटिनो कल्चर सेंटर ऑफ शिकागो द्वारा लैटिनो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला लैटिनो फिल्म फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के लिए पोस्टर कॉन्टेस्ट भी आयोजित होगा, जिसमें दुनिया भर के कलाकार अपने पोस्टर कॉन्सेप्ट भेज सकते हैं। पोस्टर में फिल्म के माध्यम से इबेरो-अमेरिका की विविध संस्कृतियों को दिखाना और उनका जश्न मनाने की भावना झलकनी चाहिए। कलाकार चाहे तो अकेले या टीम के रूप में भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता को 1,000 डॉलर का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। आप आधिकारिक लिंक chicagolatinofilmfestival.org/poster-contest पर जाकर इस कॉन्टेस्ट में ऑनलाइन माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप

आरआईकेईएन सीबीएस समर प्रोग्राम-2026

आरआईकेईएन सेंटर फॉर ब्रेन साइंस (सीबीएस) समर प्रोग्राम-2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं और दुनिया भर के छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम दिमाग के कार्यों में रुचि रखने वाले छात्रों को न्यूरोसाइंस की गहरी समझ और प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। उम्मीदवार दो महीने की लैब इंटर्नशिप या पांच दिनों के गहन लेक्चर कोर्स में से किसी एक को चुन सकते हैं। आवेदन के समय और पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित होना या किसी कंपनी में कार्यरत होना आवश्यक है, जिसके लिए नामांकन या संबद्धता का प्रमाण देना होगा। हाई स्कूल के छात्र पात्र नहीं हैं और विदेशी प्रतिभागियों के लिए वैध पासपोर्ट जरूरी है। जिन आवेदकों का वित्तीय सहायता अनुरोध स्वीकृत होगा, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 07 जनवरी, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक लिंक riken.jp/en/summer/applying.html पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एग्जाम अलर्ट हफ्ते की परीक्षाएं

यूपीएसएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 16 नवंबर, 2025
- इस परीक्षा में हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी तथा उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों पर आधारित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कुल 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित है।
- **यहां से परीक्षा केंद्र का विवरण देखें** tinyurl.com/3jbutncc

बिहार सहकारी बैंक सहायक मुख्य परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 17 नवंबर, 2025
- इस परीक्षा में तर्कशक्ति, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान व मात्रात्मक योग्यता से 200 अंकों के 200 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/53js993y

सामान्य ज्ञान

एस्केपेड मिशन

■ क्या है

यह अंतरिक्ष मिशन है, जिसमें दो अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिन्हें 'ब्लू' और 'गोल्ड' कहा जाता है।

■ चर्चा में क्यों

ब्लू ओरिजिन ने मौसम संबंधी समस्याओं के कारण नासा के बहुप्रतीक्षित एस्केपेड मंगल मिशन के अपने न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च को टाल दिया है।

■ इसका लक्ष्य

ये दोनों उपग्रह मंगल की कक्षा में अलग-अलग जगहों से एकसाथ जानकारी जुटाएंगे। वे यह देखेंगे कि सूरज की सौर-हवा मंगल से कैसे टकराती है और इसी कारण उसका वातावरण समय के साथ कैसे कम होता गया।

■ खास क्यों है

यह मिशन खास है, क्योंकि इससे हमें मंगल के माहौल और वहां मौजूद खतरों को समझने में मदद मिलेगी। भविष्य में इन्सानों को मंगल पर भेजने से पहले यह जानकारी उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होगी।

ऊर्जा Life Dream Love

बीमार कर सकती है पानी की कमी

बच्चों का शरीर नाजुक होता है। पानी की कमी से बच्चों में मुंह सूखने से लेकर कई अन्य परेशानियां हो सकती हैं। इससे उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वे बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं।

आज के समय में पानी की कमी केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रही, बल्कि यह स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। विशेष रूप से बच्चों के लिए यह स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर नाजुक होता है और उन्हें सही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। पानी न केवल प्यास बुझाने के लिए जरूरी है, बल्कि शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए भी आवश्यक है। जब बच्चों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, तो उनके शरीर में कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

डॉ. संजय तेवतिया
वरिष्ठ चिकित्सक

सबसे पहले, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन बच्चों में आम समस्या बन जाती है। पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, पाचन तंत्र को ठीक रखने और विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। जब बच्चे पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो उन्हें सिरदर्द, थकान, कमजोरी, चक्कर आना और मुंह सूखने जैसी परेशानियां होती हैं। यदि लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे, तो उनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे वे बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं। इसके अलावा, पानी की कमी का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। शोध बताते हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घट जाती है, जिससे बच्चे पढ़ाई में कमजोर पड़ने लगते हैं और उनका मूड भी चिड़चिड़ा हो सकता है।

पानी की कमी का प्रभाव पाचन तंत्र पर भी गहरा पड़ता है। इससे बच्चों में कब्ज, पेटदर्द और भूख न लगने जैसी समस्याएं होने लगती हैं। शरीर में पर्याप्त पानी होने से भोजन आसानी से पचता है और शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। जब पाचन सही नहीं होता, तो बच्चा कमजोर पड़ने लगता है और उसकी वृद्धि पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार के साथ-साथ पर्याप्त पानी का सेवन भी उतना ही जरूरी है।

इसके अलावा, पानी की कमी से त्वचा और आंखों से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सूखी त्वचा, फटे होंठ, आंखों में जलन या खुजली जैसी दिक्कतें आम हैं। खासकर गर्मी के मौसम में, जब बच्चे बाहर खेलते हैं और पसीने के रूप में शरीर से काफी मात्रा में पानी निकल जाता है, तो उन्हें बार-बार चक्कर आना, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में उन्हें बार-बार पानी या तरल पदार्थ देना बेहद आवश्यक होता है, ताकि शरीर में तरल संतुलन बना रहे।

स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी सीधे तौर पर बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। यदि बच्चे गंदा या दूषित पानी पीते हैं, तो उन्हें डायरिया, टायफाइड, हैजा और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। भारत जैसे देश में अब भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है। ऐसे में यह जरूरी है कि बच्चों को हमेशा साफ, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही दिया जाए।

माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की आदत डालें। अक्सर बच्चे जूस, सोडा या कोल्ड ड्रिंक को पानी से ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन यह आदत उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ऐसे पेय पदार्थों में चीनी और रसायन अधिक होते हैं, जो शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के बजाय नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि सादा पानी ही सबसे अच्छा पेय है। गर्मियों में नींबू पानी, नारियल पानी और फलों का रस जैसे प्राकृतिक पेय भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं, जो न केवल पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं।

आज के समय में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण के कारण जलस्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पानी बचाना भी उतना ही जरूरी है जितना पानी पीना। बच्चों को बचपन से ही जल संरक्षण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि ब्रश करते समय नल बंद रखें, अनावश्यक रूप से पानी न बहाएं और वर्षा जल संचयन जैसी आदतों को अपनाएं। जब बच्चे पानी के महत्व को समझेंगे, तभी वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे।

अंत में कहा जा सकता है कि पानी बच्चों के लिए जीवन का आधार है। यह उनके शरीर, मस्तिष्क और विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम पानी की सही मात्रा और स्वच्छता का ध्यान रखें, तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से दूर रहेंगे। हमें यह समझना होगा कि पानी बचाना और पानी पीना दोनों ही हमारी सेहत और भविष्य के लिए समान रूप से जरूरी हैं। यदि आज से हम पानी का सम्मान करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकेंगी।

योग टिप्स

शरीर के संतुलन के लिए आलथी-पालथी

आलथी-पालथी लगाकर सही ढंग से बैठना बहुत जरूरी होता है। यह शरीर में संतुलन और लचीलापन बनाए रखता है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि आप गलत तरीके से बैठते हैं, तो इससे कमर, घुटनों, पिंडलियों और टखनों में दर्द हो सकता है। शरीर का यह असंतुलित भार कई शारीरिक समस्याओं का कारण बनता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कोई गाड़ी एक ओर झुक जाए। ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर झुकता है, तो हमें असुविधा का अनुभव होता है। इसके लिए सबसे पहले शरीर का निरीक्षण करें। अब आप आलथी-पालथी लगाकर बैठें और आंखें बंद करें। महसूस करें कि आपके शरीर का भार कहां पड़ रहा है। क्या यह भार दाहिने कूल्हे पर पड़ रहा है या बाएं कूल्हे पर? यदि भार किसी एक ओर अधिक महसूस हो रहा है, तो आपके बैठने की मुद्रा सही नहीं है। गलत मुद्रा में बैठने से पेट आगे की ओर निकल जाता है। छाती दब जाती है और कमर झुक जाती है। जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं तो पेट अंदर खिंचा हुआ होता है। कमर सीधी रहती है और छाती स्वाभाविक रूप से उभरी हुई होती है। अभ्यास के लिए दाहिने कूल्हे को हथेली से सहारा देकर थोड़ा दाहिनी ओर खींचें। बाएं कूल्हे को हथेली से सहारा देकर थोड़ा बाईं ओर खींचें और देखें। शरीर का भार अब दोनों कूल्हे पर समान रूप से वितरित है या नहीं। सांस खींचकर पेट को थोड़ा खींचें और छाती को ऊपर उठाएं। इससे शरीर संतुलित और स्थिर हो जाएगा।

ढाकाराम
योगाचार्य

आज का दिन

11 नवंबर, 1966

नासा ने जेमिनी शृंखला का अंतिम अंतरिक्ष यान 'जेमिनी-12' लॉन्च किया था। यह पृथ्वी के वायुमंडल में स्वचालित रूप से प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था।

- **1872 :** अमेरिकी अभिनेत्री मौड एडम्स का जन्म हुआ था।
- **1889 :** वाशिंगटन को 42वें अमेरिकी राज्य के रूप में शामिल किया गया था।
- **1975 :** अंगोला को पुर्तगाल से आजादी मिली थी।
- **1992 :** चर्च ऑफ इंग्लैंड ने महिलाओं को पुजारी नियुक्त करने के लिए मतदान किया था।

व्रत त्योहार

आज : मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष सप्तमी।
कल : महाकाल भैरवाष्टमी, हेमंत ऋतु, सूर्य दक्षिणायने, दक्षिण गोले। **राहुकाल :** दिन में 12.00 से 13.30 तक।

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2082, 21 कार्तिक मास शक 1947, कार्तिक मास 27 प्रविष्टे, 20 जमादिउलअवल हिजरी 1447, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी 22.58 तक उपरांत नवमी, आश्लेषा नक्षत्र 18.34 तक उपरांत मघा नक्षत्र, शुक्ल योग 08.01 तक उपरांत ब्रह्म योग, बालव करण 11.03 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा सिंह राशि में 18.34 बजे।

■ सूर्योदय : 06.45
■ सूर्यास्त : 17.25
(भारतीय मानक समयानुसार)

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : व्यक्तिगत स्तर पर संवेदनशील रहेंगे। अतिउत्साह से बचें। प्रयासों में सफलता संदिग्ध रहेगी।

वृष : समाज में मान-सम्मान बना रहेगा। किसी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। यात्रा संभव है।

मिथुन : अध्ययन में अरुचि रहेगी। स्वजन सहयोग मिलेगा। कॅरिअर संबंधी चिंता रहेगी। व्यवसाय में लाभ होगा।

कर्क : आत्मविश्वास बनाए रखें। इच्छापूर्ति का अवसर मिलेगा। नौकरी में पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

सिंह : मन अशांत रहेगा। स्वजनों की चिंता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यक्षेत्र में मन नहीं लगेगा।

कन्या : पूर्वनियोजित योजना में सफलता मिलेगी। चल-अचल संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा।

तुला : सरकारी क्षेत्र में अनुकूलता रहेगी। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। अर्थ प्राप्ति संभव है। विरोधी से बचें।

वृश्चिक : भाग्य सहायक रहेगा। अटके कार्य में सफलता मिलेगी। विरोधी परास्त होंगे। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

धनु : दिनमान सामान्य रहेगा। अजनबी से सचेत रहें। धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। घर में शांति बनाए रखें।

मकर : योजना में सफलता मिलेगी। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। मित्र सहायक रहेंगे।

कुंभ : समाज में सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में व्यस्तता बनी रहेगी। विरोधी परास्त होंगे। व्यवसाय में लाभ होगा।

मीन : मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता रहेगी। नौकरी में सहकर्मियों से परेशानी होगी।

जन्मदिन

बोनी कपूर, निर्देशक

इस वर्ष लोकप्रियता में वृद्धि होगी। शुभचिंतक सहायक रहेंगे। अटके कार्य में सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहेगा। मकान या प्लॉट का क्रय हो सकता है। परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। साझेदारी में किसी नए व्यवसाय का प्रारंभ हो सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

सुडोकू

8		3	6			9		
4			9					
		7			1	3		
			8	1				7
		9				8		
7				6	5			
		8	2			6		
					7			9
		4			6	2		1

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

8	5	3	6	7	2	9	1	4
4	6	1	9	3	8	7	5	2
2	9	7	5	4	1	3	6	8
3	4	6	8	1	9	5	2	7
5	1	9	7	2	3	8	4	6
7	8	2	4	6	5	1	9	3
1	3	8	2	9	4	6	7	5
6	2	5	1	8	7	4	3	9
9	7	4	3	5	6	2	8	1

डेली हेल्थ कैप्सूल

कई बीमारियों से बचाते हैं बेल के पत्ते

बेल के पत्तों में ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव में मददगार साबित होते हैं।

आयुर्वेद में बेल के पत्तों को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। खाली पेट इसका सेवन करने से सेहत से जुड़ी कई समस्याओं से बचाव होता है। बेल के पत्ते में एंटीऑक्सिडेंट्स, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, विटामिन-ए, सी ,राइबोफ्लेविन, विटामिन-बी6, बी12 और बी1, कैल्शियम और फाइबर होते हैं, जो आपको सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। बेल के पत्ते में मौजूद तत्व पैंक्रियाज को सक्रिय करके इन्सुलिन के स्राव को बढ़ावा देते हैं, जिससे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। इन पत्तों में मौजूद फाइबर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाचन को बेहतर बनाकर गैस, कब्ज, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में आराम पहुंचाते हैं। सुबह-सुबह बेल के पत्ते को चबाने से शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। यह किडनी और लीवर को साफ करके संक्रमण के खतरे को कम करता है। इन पत्तों में विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर वायरल संक्रमण, सर्दी-जुकाम से बचाव करते हैं। खाली पेट बेल के पत्ते चबाने से मुंह के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

बेल के एक या तीन ताजे और साफ पत्तों का ही सेवन करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से नुकसान हो सकता है। थायरॉइड या अन्य बीमारी से पीड़ित सेवन से पहले आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह जरूर लें। -डॉ. राजीव पुंडीर
वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक

अस्तित्व बचाए रखने के लिए डिजिटल भुगतान पर जोर दें शहरी सहकारी बैंक : शाह

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लॉन्च किए दो मोबाइल एप्लिकेशन

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सोमवार को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए दो मोबाइल एप्लिकेशन 'सहकार डिजी पे' और 'सहकार डिजी लोन' पेश किए।

मंत्री ने कहा, भुगतान के तरीके बदल गए हैं। डिजिटल भुगतान समय की मांग है। अगर शहरी सहकारी बैंक डिजिटल भुगतान पर जोर नहीं देंगे और इसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, तो वे इस दौड़ से बाहर हो जाएंगे। शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने दो वर्षों में 1,500 बैंकों को इस मंच से जोड़ने का लक्ष्य रखा। साथ ही कहा, यूसीबी और सहकारी ऋण समितियों को पेशेवर बनाने के लिए, सरकार ने कई प्रयास किए हैं। अब शहरी सहकारी बैंकों को भी आगे आना होगा और तेजी से बढ़ती नकदी रहित अर्थव्यवस्था में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाना होगा।

शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अमित शाह। एजेंसी

हर शहर में एक यूसीबी खोलने का लक्ष्य

शाह ने नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लि. (एनएएफसीयूबी) से आगे विस्तार करने का आग्रह किया। उन्होंने एनएएफसीयूबी के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया कि पांच साल के भीतर दो लाख से अधिक आबादी वाले हर शहर में कम-से-कम एक अतिरिक्त शहरी सहकारी बैंक स्थापित किया जाए। **उन्होंने फेडरेशन से कहा, सफल सहकारी ऋण समितियों को शहरी सहकारी बैंकों में बदलने पर विचार करना चाहिए।**

■ **युवा उद्यमियों और वंचितों पर ध्यान दें यूसीबी :** शाह ने जोर देकर कहा, सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि ही राष्ट्रीय प्रगति का मापदंड नहीं हो सकती। **जीडीपी में वृद्धि के साथ आजीविका के विकल्प भी पैदा होने चाहिए, जो सहकारी बैंक कर सकते हैं।** उन्होंने शहरी सहकारी बैंकों से युवा उद्यमियों और आर्थिक रूप से वंचितों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

चिंता : 20 शहरी सहकारी बैंक अब बंद होने के कगार पर पहुंचे

एनएएफसीयूबी के मानद अध्यक्ष एवं कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि देश में अब तक बंद होने के कगार पर पहुंचे 20 शहरी सहकारी बैंकों को लेकर चिंता जताई और उन्होंने यस बैंक की तरह ही इनके पुनरुद्धार के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, किसी बैंक को इसलिए बंद करना सही तरीका नहीं है, क्योंकि वह अलाभकारी है।

■ **एनपीए में अच्छा सुधार :** शाह ने कहा, इस क्षेत्र की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। दो वर्षों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 2.8 फीसदी से घटकर 0.6 फीसदी रह गईं। एनपीए में अच्छे सुधार के साथ उनका संचालन और वित्तीय अनुशासन भी बेहतर हुआ है।

सेंसेक्स में 319 अंक की तेजी 1.89 लाख करोड़ बढ़ गई पूंजी

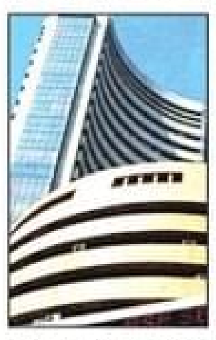

नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट सोमवार को थम गई। सेंसेक्स 319 अंक चढ़ गया, जबकि निफ्टी 25,500 के पार बंद हुआ। आईटी एवं वित्तीय शेयरों में खरीदारी और वैश्विक बाजारों में तेजी का घरेलू बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

सेंसेक्स 319.07 अंक की बढ़त के साथ 83,535.35 पर बंद हुआ। दिन में यह 538.21 अंक उछलकर 83,754.49 पर पहुंच गया था। निफ्टी 82.05 अंक चढ़कर 25,574.35 पर बंद हुआ। सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 1.89 लाख करोड़ बढ़कर 468.20 लाख करोड़ पहुंच गई। सेंसेक्स की 30 में से 19 कंपनियों के शेयर बढ़त में रहे। इन्फोसिस सर्वाधिक 2.52 फीसदी बढ़त में बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शुद्ध 4,114.85 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। ब्यूरो

न्यूज डायरी

इमामी प्रति शेयर देगी 4 रुपये का लाभांश

नई दिल्ली। एफएमसीजी प्रमुख इमामी लि. का मुनाफा दूसरी तिमाही में 30 फीसदी कम होकर 148 करोड़ रुपये रह गया है। घरेलू बाजार में इसके ग्रीष्मकालीन पोर्टफोलियो की कम बिक्री के कारण यह गिरावट आई है। राजस्व 10.3 फीसदी घटकर 798 करोड़ रुपये रह गया। खर्च घटकर 620 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर चार रुपये लाभांश देने की घोषणा की है। कर्मचारी लागत बढ़कर 121.2 करोड़ रुपये हो गई। ब्यूरो

टीटी लि. वियतनाम में खोलेगी मार्केटिंग ऑफिस

नई दिल्ली। टेक्सटाइल कंपनी टीटी लि. वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में मार्केटिंग और सोर्सिंग ऑफिस खोलेगी। इसके जरिये वह वैश्विक स्तर पर कपड़ा आपूर्ति शृंखला का फायदा उठाएगी। टीटी लि. के एमडी संजय कुमार जैन ने कहा, इस ऑफिस के जरिये कंपनी यूरोप और अमेरिका में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा पाएगी। इसके अलावा, अविनाशी प्लांट में नया उपक्रम भी स्थापित करेगी। ब्यूरो

कोटक म्यूचुअल ने लॉन्च किया ग्रामीण फंड

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कोटक रूरल अपॉर्च्यूनिटीज फंड लॉन्च किया है। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है, जो ग्रामीण और इससे जुड़े क्षेत्रों की कंपनियों में निवेश पर फोकस करेगी। कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह स्कीम 6 नवंबर से खुली है और निवेशक 20 नवंबर तक इसमें पैसा लगा सकते हैं। इस स्कीम का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी रूरल इंडेक्स टीआरआई होगा। ब्यूरो

जिंदल स्टेनलेस को 808 करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली। जिंदल स्टेनलेस को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 808 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 32 फीसदी अधिक है। बिक्री बढ़ने से कंपनी के लाभ में तेजी आई है। आय 12 फीसदी बढ़कर 9,823.88 करोड़ रुपये रही। बिक्री 5,64,627 टन से बढ़कर 6,48,050 टन हो गई। 2024-25 में वार्षिक कारोबार 40,182 करोड़ रुपये रहा। एजेंसी

एसजेवीएन के मुनाफे में 30 फीसदी गिरावट

नई दिल्ली। एसजेवीएन लि. को 2025-26 की सितंबर तिमाही में 307.80 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में यह 30 फीसदी कम है। कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये की धन जुटाने की योजना बनाई है। इस दौरान आय भी घटकर 1,078 करोड़ रुपये रह गई, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,108 करोड़ रुपये थी। खर्च बढ़कर 658 करोड़ रुपये हो गया। एजेंसी

अक्तूबर की मुद्रास्फीति के आंकड़े पर दिखेगा टमाटर, आलू और प्याज के सस्ते होने का असर

राहत : 0.40 फीसदी के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ सकती है खुदरा महंगाई दर

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महंगाई के मोर्चे पर लगातार राहत मिल रही है। यह अक्तूबर के आंकड़ों में घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 0.40 से 0.60 फीसदी के दायरे में आ सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि आलू, प्याज और टमाटर के लगातार कम होते भाव के कारण यह असर होगा। सितंबर में खुदरा मुद्रास्फीति की दर घटकर 1.54 फीसदी पर आ गई थी, जो आठ साल का निचला स्तर था। अक्तूबर लगातार दूसरा महीना होगा, जब खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के 2-6 फीसदी दायरे से नीचे आ जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख सब्जियां (टमाटर, प्याज और आलू) लगातार सस्ते हो रहे हैं। मंडियों में अच्छी आवक से इनमें दोहरे अंकों में गिरावट दर्ज की गई। अन्य प्रमुख वस्तुओं में दालों, विशेष रूप से अरहर दाल की कीमतों में भी गिरावट आई है। यह अक्तूबर, 2024 की तुलना में अक्तूबर, 2025 में 29 फीसदी सस्ती हुई है। जनवरी, 2018 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। वैश्विक कीमतों में कमजोरी के चलते खाद्य तेल की मुद्रास्फीति में भी कुछ नरमी के संकेत दिख रहे हैं। जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में कमी से खुदरा मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान भी बेहतर दिख रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्तूबर के महंगाई के आंकड़ों में आने वाली तेज गिरावट मुख्य रूप से आधार प्रभाव के कारण है। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के विपरीत खाद्य कीमतें स्थिर रहीं, जिससे मूल्य दबाव कम हुआ। खाद्य एवं पेय समूह की कीमतों में सालाना आधार पर 3.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। चीनी और मसालों को छोड़कर सभी उप समूहों में खुदरा मुद्रास्फीति अक्तूबर में कम होने की संभावना है। सबसे ज्यादा गिरावट खाद्य तेल और वसा उप समूह में है।

1.54% रह गई थी खुदरा महंगाई सितंबर में

अनाज की भी कीमतें घटीं

सीएमआईई के मुताबिक, अनाज एवं उत्पाद में मुद्रास्फीति अक्तूबर के आंकड़ों में लगभग आधी होकर 1.1 फीसदी रहने की संभावना है। सितंबर में यह 2.1 फीसदी रही थी।

■ गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थों और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति सितंबर के 4.1 प्रतिशत से घटकर अक्तूबर में चार प्रतिशत से नीचे आ गई है। यह राहत जीएसटी कटौती से मिली है।

इन वस्तुओं की घटीं कीमतें

प्याज	51.1%
टमाटर	39.9%
आलू	31.3%
अरहर दाल	29.4%
उड़द दाल	8.8%
चना दाल	8.3%
मूंग दाल	4.9%
मूंगफली तेल	2.5%
मसूर दाल	0.6%

सितंबर, 2024 में कच्चे व रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेलों पर सीमा शुल्क में 20% की वृद्धि की गई। इससे रिफाइंड तेल की कीमतों में तेजी आई।

20 में से 10 वस्तुओं के दाम घटे

बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट कहती है कि एक साल पहले की तुलना में 20 में से 10 वस्तुओं के दाम घट गए हैं। सबसे ज्यादा प्याज के दाम घटे हैं। आलू की कीमतों में भी बीते 7 महीनों में निरंतर गिरावट देखी गई है।

महंगाई में इस तरह आएगी कमी

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) के मुताबिक, सितंबर में तेल और वसा की महंगाई दर 18.3 फीसदी थी जो अक्तूबर में 11.5 फीसदी रहेगी।

■ जीएसटी में कटौती के कारण घी और मक्खन के भाव घटे हैं। दालों और सब्जियों की कीमतों में लगातार नौवें महीने गिरावट जारी रहने की आशंका है। अक्तूबर में सब्जियों के दाम मासिक आधार पर 2.4 प्रतिशत बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे जुड़े अन्य उत्पादों में 25.6 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।

डाटा सेंटर निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष आकर्षक बाजारों में भारत

■ 20% डाटा उत्पादन देश में, पर क्षमता का सिर्फ तीन फीसदी

नई दिल्ली। डाटा सेंटर निवेश के लिए भारत दुनिया के सबसे आकर्षक बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। मुंबई 2025 में विश्व स्तर पर दूसरे सबसे कम लागत वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। टर्नर एंड टाउनसेंड डाटा सेंटर निर्माण लागत सूचकांक के अनुसार, मुंबई में डाटा सेंटर निर्माण की लागत मात्र 6.64 डॉलर प्रति वॉट है। इससे शहर 52 वैश्विक बाजारों में 51वें स्थान पर है।

यह रैंकिंग डाटा सेंटर बनाने की प्रति वॉट लागत पर आधारित है। इसमें पहली रैंक सबसे ज्यादा निर्माण लागत व 52वीं सबसे कम निर्माण लागत दर्शाती है। मुंबई का 51वां स्थान यह दर्शाता है कि यह डाटा सेंटर निर्माण के लिए दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता शहर है। यह कम लागत वाला वातावरण भारत को निवेश के लिए एक रणनीतिक बढ़त देता है, जो टोक्यो, सिंगापुर और ज्यूरिख जैसे अन्य प्रमुख केंद्रों की तुलना में कम है। यहां प्रति वॉट लागत दोगुनी है। मुंबई को 6.71 अमेरिकी सेंट/किलोवॉट घंटा की सस्ती बिजली दर का भी लाभ मिलता है, जो शंघाई की तुलना में 50 फीसदी से कम है। भारत दुनिया के 20 फीसदी डाटा का उत्पादन करता है, लेकिन वैश्विक डाटा केंद्र क्षमता का केवल तीन फीसदी ही उसके पास है, जो विदेशी होस्टिंग पर महत्वपूर्ण निर्भरता को उजागर करता है। इसका अर्थ घरेलू बाजार के व्यापक विस्तार की संभावना है। एजेंसी

चीन के बाद भारत सबसे बड़ा डाटा सेंटर बाजार

जापान और सिंगापुर के साथ भारत पहले से ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बाद सबसे बड़े डाटा सेंटर बाजारों में से एक है। भारत को क्षेत्रीय विस्तार के लिए 156 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक मोड़ पर है, जहां मुंबई जैसे बाजार प्रतिस्पर्धी निर्माण लागत का संयोजन प्रदान करते हैं। यहां एक विशाल अनुमानित बाजार अवसर है, जिसमें क्षेत्रीय निर्माण के लिए 156 अरब डॉलर की आवश्यकता है। यह कम लागत वाला आधार भारत को डाटा सेंटर निवेश के लिए प्रमुख लाभ प्रदान करता है।

आपूर्ति शृंखला प्रमुख बाधा

लागत लाभ के बावजूद विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करना और आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करना प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि 2025 में औसत लागत मुद्रास्फीति 5.5 फीसदी होगी। रिपोर्ट में ग्राहकों को आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूत करने व एआई डाटा केंद्रों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए खरीद रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने की सलाह दी गई है।

ई-कॉमर्स मंचों पर पैकेज वस्तुओं के मूल देश का फिल्टर अनिवार्य करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए पैकेज वस्तुओं के मूल देश का फिल्टर अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इससे ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदी के समय आसानी से उत्पादों की उत्पत्ति की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे डिजिटल मार्केटप्लेस में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

इसके संबंधित नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत आयातित उत्पाद बेचने वाली प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को उत्पाद सूची के साथ मूल देश के लिए एक खोज योग्य फिल्टर देना होगा। यह संशोधन ग्राहकों को खरीदी के समय उत्पादों के मूल स्रोत की आसानी से पहचान करने की सुविधा देकर उन्हें सही निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। इससे उत्पाद सूची में जानकारी ढूंढ़ने में लगने वाला समय कम होगा। संशोधन नियमों का मसौदा परामर्श के लिए विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है। हितधारकों से 22 नवंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं। यह संशोधन मेड इन इंडिया उत्पादों को आसानी से खोज योग्य बनाकर आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल पहल का प्रत्यक्ष समर्थन करता है। साथ ही, भारतीय निर्माताओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित होने की उम्मीद है, जिससे घरेलू उत्पादों को आयातित वस्तुओं के बराबर दृश्यता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहकों को स्थानीय स्तर पर निर्मित विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, मूल देश के फिल्टर की शुरूआत से प्राधिकारियों को अनुपालन की सही निगरानी करने, उत्पाद जानकारी की पुष्टि करने व सूची की मैन्युअल समीक्षा की जरूरत के बिना उल्लंघनों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। एजेंसी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा, संबंधित नियमों में होगा बदलाव

वोडाफोन आइडिया का घाटा कम होकर 5,524 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया का घाटा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कम होकर 5,524 करोड़ रुपये रह गई। एक साल पहले की समान अवधि में घाटा 7,175.9 करोड़ रहा था।

कंपनी ने सोमवार को बताया, इस अवधि में उसका राजस्व 2.4 फीसदी बढ़कर 11,195 करोड़ रुपये पहुंच गया। प्रति ग्राहक औसत राजस्व 166 रुपये से 8.7 फीसदी बढ़कर 180 रुपये पहुंच गया। दूसरी तिमाही तक कंपनी पर 2,02,951 करोड़ कर्ज है। एजेंसी

सोना 1,300 रुपये महंगा, चांदी की कीमतों में 2,460 का उछाल

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक संकेतों और डॉलर में कमजोरी से सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,300 रुपये महंगा होकर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। चांदी की कीमत भी 2,460 रुपये बढ़ गई और यह 1,55,760 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, सुरक्षित निवेश की मौजूदा मांग और कमजोर अमेरिकी वृहद आर्थिक आंकड़ों के कारण सोने में सकारात्मक रुख के साथ कारोबार फिर से शुरू हुआ। इससे अगले महीने होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कमजोर डॉलर ने भी सराफा कीमतों को और समर्थन दिया है। वैश्विक बाजार में हाजिर सोना 83.12 डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 4,082.84 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। एजेंसी

आईपीओ का उत्साह ठंडा : लेंसकार्ट की खराब शुरुआत फिजिक्सवाला और ग्रो के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट

अजीत सिंह

नई दिल्ली। नए जमाने के आईपीओ को लेकर निवेशकों का उत्साह ठंडा पड़ता दिख रहा है। लेंसकार्ट का शेयर आईपीओ मूल्य 402 रुपये से तीन फीसदी कम पर सूचीबद्ध हुआ है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 108 रुपये था, लेकिन निवेशकों को इस इश्यू से जमकर निराशा हुई है।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, इस समय आईपीओ की बाढ़ में काफी सारी कंपनियां बहुत ऊंचा भाव रख रही हैं। लेकिन, लेंसकार्ट सहित कई शेयरों की सुस्त लिस्टिंग ने उच्च मूल्यांकन वाले डिजिटल शेयरों में निवेशकों का विश्वास डगमगा दिया है। यह रुझान अन्य जानी-मानी नई कंपनियों को लेकर भी दिख रहा है, जिनका आईपीओ खुला है या जो कुछ दिनों में सूचीबद्ध होंगी।

आईपीओ बाजार पर नजर रखने वालों के अनुसार, **ग्रो का ग्रे मार्केट प्रीमियम** 16 रुपये से घटकर 5 रुपये हो गया है। यानी लिस्टिंग पर सिर्फ पांच फीसदी फायदा होगा। यह इसी हफ्ते लिस्ट होगा। 6,632 करोड़ रुपये के इश्यू का भाव 100 रुपये तय किया गया था।

फिजिक्सवाला के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 9 से घटकर 4 रुपये हो गया है। यानी चार फीसदी का फायदा मिल सकता है। 3,480 करोड़ का यह इश्यू 103 से 109 रुपये के भाव पर 11 से 13 नवंबर तक खुलेगा।

पाइन लैब्स का प्रीमियम 35 रुपये था, अब 4 रुपये के आसपास है। यानी दो फीसदी मुनाफा मिल सकता है। इश्यू मंगलवार को बंद होगा। भाव 210 से 211 रुपये तय किया गया है।

एक रुपये की कमाई, आईपीओ में मांगे 238 रुपये

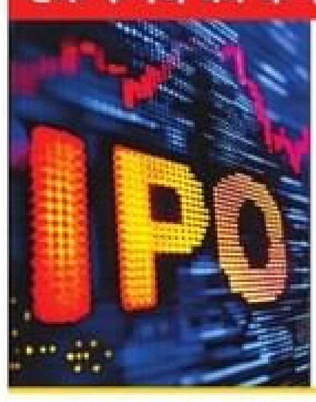

लेंसकार्ट की प्राइस टू अर्निंग 235 से 238 रुपये है। यानी कंपनी एक रुपये की कमाई पर निवेशकों से 238 रुपये मांग रही थी। 7,278 करोड़ रुपये का इश्यू 403 रुपये पर बंद हुआ। 402 रुपये भाव था। यह ऊपर की ओर 413 रुपये तक और नीचे की ओर 11 फीसदी लुढ़ककर 355 रुपये तक चला गया। पूंजी 69,967 करोड़ रुपये रही। यह इश्यू 28 गुना भरा था। इसे संस्थागत निवेशकों के कारण इतना रिस्पांस मिला था।

स्टॉक का नाम	सीएमपी (रू.)	लक्ष्य (रू.)	वृद्धि (%)
श्रीराम फाइनेंस	821	860	5%
रेडिको खेतान	3260	3600	10%
रुबिकॉन रिसर्च	618	740	20%
वारी एनर्जीज़	3311	4000	21%
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स	1141	1450	27%

Note: *Investment in securities are subject to market risks, please carry out you due diligence before investing.

SHRIRAM Finance
श्रीराम फाइनेंस
श्रीराम फाइनेंस एक मजबूत विविध परिसंपत्ति मिश्रण, बेहतर परिचालन दक्षता और अनुशासित ऋण प्रबंधन के बल पर दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। कंपनी ने गाड़ियों को फाईनांस करने की निरंतर बढ़ रही मांग के कारण कंपनी ने स्थिर एयूएम का विस्तार किया है और वर्ष की दूसरी छमाही में भी यह गति जारी रहने की उम्मीद है। बेहतर लिक्विडिटी मैनेजमेंट और संभावित क्रेडिट रेटिंग के सुधार, फंडस की लागत में सुधार के साथ इसके मार्जिन में भी सुधार का अनुमान है। नई गाड़ियों और सोने के ऋण व्यवसाय के विस्तार में प्रबंधन का ध्यान और साथ में क्रॉस-सेलिंग के अवसरों से, इसकी दीर्घकालिक विकास की संभावना को बल मिलता है। कंपनी की स्थिर परिसंपत्ति गुणवत्ता और इसकी नई-2 उत्पादकता पहले इसके लाभप्रदता के दृष्टिकोण को और अधिक बढ़ाती हैं। अत: श्रीराम फाइनेंस का अच्छा प्रोफिट, परिचालन लचीलापन और रणनीतिक व्यावसायिक विस्तार स्थायी मूल्य सृजन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

Radico Khaitan Limited
रेडिको खेतान
रेडिको खेतान अपनी मजबूत ब्रांड इक्विटी, प्रीमियमीकरण और बाजार में बढ़ती उपस्थिति के दम पर अपने दीर्घकालिक विकास गति को लगातार मजबूत कर रहा है। कंपनी के प्रेस्टीज और पोर्टफोलियो से अधिक लगातार अच्छी वृद्धि दर्ज की है, जबकि रेगुलर सेगमेंट ने आंध्र प्रदेश में बेहतर वितरण क्षमता और बाजार हिस्सेदारी के विस्तार से उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया है। कंपनी प्रबंधन अपने लक्जरी सेगमेंट के विस्तार पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 26 में 5 अरब रुपये की बिक्री करने का है और कंपनी को उम्मीद है कि अगले तीन वर्षों में मैजिक मोमेंट्स की बिक्री 1 करोड़ तक पहुँच जाएगी।

मार्जिन में वृद्धि स्थिर कच्चे माल की लागत, ऑपरेशन क्षमता और अनुशासित लागत प्रबंधन से प्रेरित होगी। वित्त वर्ष 27 तक ऋण मुक्त होने की योजना और दक्षता पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही यह निरंतर विकास हासिल करने और प्रीमियम स्पिरिट सेगमेंट में अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

Rubicon RESEARCH INNOVATION | QUALITY | CARE
रुबिकॉन रिसर्च
रुबिकॉन रिसर्च विनियमित बाज़ार विशेषत: संयुक्त राज्य अमेरिका पर केंद्रित एक शोध-संचालित दवा कंपनी के रूप में अपनी स्थिति को लगातार मज़बूत कर रही है। कंपनी ने अपनी संपूर्ण आरएंडडी क्षमताओं, कुशल विनिर्माण और लगातार अनुपालन रिकॉर्ड के माध्यम से एक मज़बूत आधार तैयार किया है। जेनेरिक और नेज़ल स्प्रे के नए लॉन्च, स्थिर अनुसंधान एवं विकास उत्पादकता और प्रिस्क्रिप्शन आधारित सीएनएस थेरेपी सेगमेंट पर विशेष ध्यान के कारण रेवेन्यू और प्रॉफिट में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त की है। कंपनी की मज़बूत व्यावसायीकरण दर और अनुशासित उत्पाद विकास दृष्टिकोण परिचालन उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं। प्रबंधन का नवाचार, गुणवत्ता अनुपालन और लागत कुशल संचालन पर ध्यान दीर्घकालिक सतत विकास के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करता है। हम रुबिकॉन को खरीदने की रेटिंग देते हैं, क्योंकि इसकी रणनीतिक कार्यान्वयन और मज़बूत अनुसंधान एवं विकास क्षमताएँ इसे निरंतर मूल्य सृजन के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

WAAREE One with the Sun
वारी एनर्जीज़
वारी एनर्जीज़ भारत के सौर ऊर्जा के विनिर्माण क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है जो देश के स्वच्छ ऊर्जा विस्तार और घरेलू उत्पादन के लिए मज़बूत नीतिगत समर्थन से लाभान्वित होने की स्थिति में है। कंपनी की मॉड्यूल, सेल और संबंधित वर्टिकल्स जैसे ईपीसी, बैटरी ऊर्जा स्टोरेज सिस्टम और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे संबंधित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर एकीकृत संचालन के परिणामस्वरूप इसकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता और दीर्घकालिक विकास की संभावना को और अधिक बढ़ाते हैं। एक मजबूत ऑर्डर बुक और निरंतर हो रही क्षमता का विस्तार प्रबंधन को रिजिलंट मूल्य निर्धारण और परिचालन दक्षता की सहायता से अच्छे मार्जिन सुधार के साथ-2 आमदन में भी अच्छी वृद्धि की उम्मीद है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षमताओं में इसके रणनीतिक निवेश इसकी दूरदर्शी कार्य निष्पादन क्षमताओं को रेखांकित करते हैं। अपने मजबूत सिद्धांतों, दूरदर्शी प्रबंधन और भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के परिणामस्वरूप वारी एनर्जीज़ लगातार दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार है।

TATA CONSUMER PRODUCTS
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो, निरंतर नवाचार और कैटेगरी डायवर्सीफिकेशन के कारण निरंतर दीर्घकालिक विकास के लिए अच्छी स्थिति में है। भारत का यह ब्रांडेड व्यवसाय प्रीमियमीकरण और व्यापक वितरण पहुँच द्वारा चाय और नमक में लगातार दोहरे अंकों में विस्तार के साथ विकास का एक प्रमुख इंजन बना हुआ है। रेडी-टू-ड्रिंक, कैपिटल फ़ूड्स और ऑर्गेनिक इंडिया बिजनैस का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से लगातार नए-2 उभरते क्षेत्रों में कंपनी की उपस्थिति मज़बूत हो रही है। कॉफ़ी की लागत और मूल्य संशोधन में सामान्यीकरण से अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को लाभ होने की उम्मीद है और इससे कंपनी के मार्जिन में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी छमाही में मार्जिन बढ़ाने और उत्पाद मिश्रण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने का प्रबंधन का विश्वास लंबे समय के लिए प्रोफिट की संभावना को मज़बूत करता है। इसकी मज़बूत कोर वृद्धि, बेहतर मार्जिन और आशावान प्रबंधन के नजरिये को देखते हुए यह कंपनी एक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाती है।

ADVT.

CCI NG 3.7 Product: NBTDelhiBS PubDate: 11-11-2025 Zone: Mahanagar Edition: 1 Page: NBTMAH12 User: dilip.lal Time: 11-10-2025 22:52 Color:

लापरवाही छोटी हो या बड़ी, उसका परिणाम हमेशा खतरनाक होता है।

– थॉमसफुलर, इतिहासकार

भरोसा बनाए रखें

दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके की असल वजह पता चलना अभी बाकी है, लेकिन इसके पीछे किसी आतंकी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। यह वारदात देश को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। सारी कड़ियां जुड़ने के बाद ही पूरी कहानी सामने आएगी। तब तक जरूरत है संयम और सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा बनाए रखने की।

संवेदनशील इलाका । यह विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुआ। इस इलाके में सुबह से शाम तक बहुत भीड़ रहती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यह एरिया बेहद संवेदनशील है। हर दिन हजारों पर्यटक लाल किला और पुरानी दिल्ली की गलियां घूमने आते हैं। अगर यह आतंकी वारदात निकलती है, तो कुछ सवाल पुलिस पर भी उठेंगे। आखिर इतना विस्फोटक राजधानी में आ कैसे गया?

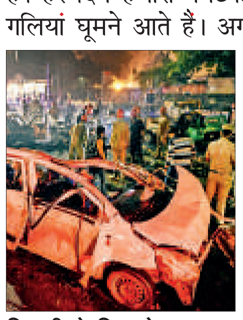

दिल्ली में विस्फोट

आतंकी नेटवर्क । यह वारदात ऐसे वक्त हुई है, जब जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यूपी से लेकर हरियाणा तक आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है और कई गिरफ्तारियां की हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इन गिरफ्तारियों का दिल्ली ब्लास्ट से कोई संबंध है।

निशाने पर राजधानी । संसद पर अटैक, 2005 और 2008 के सीरियल ब्लास्ट समेत राजधानी को आतंकियों ने कई बार निशाना बनाया है। वहीं, इस साल अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों को गोली मार दी थी। तब पूरा देश जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के साये तले एकजुट हो गया था, उसने यह संदेश दिया कि आतंकी मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वही जज्बा बनाए रखने की जरूरत है।

आतंकवाद में कमी । हालिया बरसों में आतंकवादी घटनाओं में लगातार कमी दर्ज की गई है। 2004 से 2014 के बीच 7,217 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जबकि इसके बाद के दशक में यह आंकड़ा 2,242 रहा। इस दौरान आतंकी वारदातों में मरने वालों की संख्या में भी 70% की गिरावट आई। बॉर्डर पर कड़ी चौकसी की वजह से सीमापार से होने वाली घुसपैठ में कमी आई है।

पड़ोस में हलचल । जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है, तो झूठी सूचनाएं और अफवाहें फैलाने वाला तंत्र सक्रिय हो जाता है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और नेपाल-श्रीलंका तक - हालात जटिल बने हुए हैं। भारत इकलौता देश है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर है। वह दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में है और यह रफ्तार थमनी नहीं चाहिए।

ऐवें कुछ भी

हम स्वर्गवासी हुए

आलोक सिंह भदौरिया

सुबह के साढ़े पांच बजे छोटे को जगाया, उसे स्कूल के लिए तैयार होना था, बचपन वाली कविता दोहराई, उठो लाल लाल आंखें खोलो... पल्यूशन की वजह से उसकी क्लास के बच्चों की आंखों में इन्फेक्शन हो गया है।

बाहर भयानक रूमानी माहौल था, गहरी सांस ली। डेढ़ किलो स्मॉग के साथ कुछ और भी अंदर चला गया। फेफड़ों सहित आत्मा को झकझोरने वाली खांसी आ गई। हवा में कचरे की खुशबू थी। ओह... आज गुरुवार है क्या। पास ही डंपयार्ड से कचरा उठ रहा था, हर गुरुवार और रविवार को उठता है। सोचा बच्चे को बस में बैठाकर जरा कचरे के ढेर तक चला जाऊं मन फ्रेश हो जाएगा। दिन भर की भागदौड़ के लिए जरूरी ताजगी मिल जाएगी। कचरा उठाने वाली JCB को भी देख लूंगा।

लौटते समय पार्क के गेट के पास एक नई मूर्ति टाइप चीज दिखी। उसकी नाक एकदम हमारे शुक्ला जी जैसी थी। हमने छूकर देखना चाहा, मूर्ति में जैसे जान आ गई। शुक्ला जी ही थे। उन्होंने आंखें खोलीं, गरियाना चाहा फिर रुक गए। बोले, इस रोमांटिक माहौल में धुंध, धुएं, धूल और स्मॉग के बीच विपश्यना कर रहा था। आपसे बर्दाश्त न हुआ। हम बोले, सॉरी आपके ऊपर इतनी गर्द जमा हो गई थी कि लगा मूर्ति हैं।

नहा कर ऑफिस के लिए निकले, कुछ कमी सी महसूस हो रही थी। बगल से एक डंपर मौरंग, गिट्टी लिए निकला। हल्के से लचका। पाव-आध पाव हमारे सिर पर चढ़ा गया... हां अब ठीक है। पंडित जी कह रहे थे, पृथ्वी तत्व कमजोर है तुम्हारा, यही कमी थी अब पूरी हो गई। दिल से चाहो तो क्या नहीं होता।

मोहल्ले में नगर निगम नाली खुदवा रहा था, बिजली विभाग अंडरग्राउंड केबल डाल रहा था और ग्रीन गैस वाले पाइप लाइन बिछा रहे थे। तीनों का संगम चौराहे पर हो गया। वहां हल्दी घाटी जैसा मनोरम दृश्य था। सबके समवेत प्रयासों से मलबे का जो पहाड़ था उसके ऊपर एक कुत्ता महोदय खड़े होकर माहौल का जायजा ले रहे थे। दिल ने कहा, अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है... फिर मन स्वर्गवासी होने को होने लगा।

बोल वचन

दिलीप लाल

एकदम झक्कास

बोलचाल में 'झक्कास' खूब प्रचलित है, जबकि लिखित भाषा में इसका प्रयोग कम होता है। अर्थ की दृष्टि से यह शब्द शानदार, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, दमदार या बेहद आकर्षक के समानार्थी है। हालांकि अगर बोलने में जरा भी कमी रह जाए, तो जितना जोश इस शब्द में है, वह प्रकट नहीं हो पाता। यह शब्द मूल रूप से मराठी और बंबइया हिंदी का स्लैंग है, जो फिल्मों के माध्यम से लोकप्रिय हुआ, विशेषकर 1980 के दशक में अनिल कपूर का यह सिग्नेचर डायलॉग बन गया था। 1985 में आई फिल्म 'युद्ध' में जैकी श्रॉफ के साथ उनका एक डायलॉग है, 'मानता हूं तेरी पसंद को... मस्का-मस्का... एकदम झक्कास!' यह शब्द आम बोलचाल में उत्साह, जोश और प्रशंसा का प्रतीक बन गया। व्याकरण की दृष्टि से यह विशेषण के रूप में प्रयोग होता है और मानक हिंदी में इसे बोलचाल का शब्द या लोकप्रिय अपभ्रंश माना गया है। झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रचलन में है, झकास। जिसका अर्थ साफ-सुथरा या चमकदार भी है, जैसे आपका घर-आंगन झकास है। अंग्रेजी के Cool, Stylish या Dashing शब्द उसके पूरे भाव को नहीं पकड़ पाते। झक्कास में जो जोश, मस्ती और भारतीयता है, वह उसे सचमुच 'झक्कास' बनाती है।

AI Image

बिहार के नौजवान वोटर चाहते सब कुछ हैं, लेकिन इसके लिए लड़ने का जज्बा खोते जा रहे

युवा वोटरों के मन में क्या चल रहा है

मनीषा प्रियम

बिहार चुनाव 2025

बिहार में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग आज होने जा रही है। इस बीच सबकी नजरें छोटी पार्टियों जैसे चिराग पासवान की LJP (RV), जीतनराम मांझी की HAM, उपेंद्र कुशवाहा की RLM और मुकेश सहनी की VIP पर टिकी हुई हैं। बड़ी पार्टियां हाशिये पर पहुंचे खास तबकों, विशेषकर महिलाओं और सब-ऑल्टर्न युवाओं में पैठ रखने वाले इन दलों को अपने साथ जोड़े रखना जरूरी मानती हैं।

प्रचार का ग्लोबल पैटर्न । इस चुनाव में दक्षिणपंथी रुझान वाली पार्टियों ने जहां घुसपैठियों का मुद्दा जोर-शोर से उठाया वहीं महिलाओं तथा बेरोजगारों को कैश ट्रांसफर के जरिए लुभाने का प्रयास किया। यह ऐसी रणनीति है, जिसका यूरोप और लैटिन अमेरिका में खूब इस्तेमाल हुआ है। महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में नागरिक अधिकारों से जुड़ी शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, जो ब्राजील में बोल्सोनारो के खिलाफ चले सूचना का अधिकार से जुड़े अभियानों की याद दिलाता है।

युवाओं पर जोर । वोटर अधिकार यात्रा ने पढ़ाई-कमाई (शिक्षा-रोजगार) के मुद्दों को उठाते हुए सब-ऑल्टर्न युवाओं का भी ध्यान खींचा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी युवाओं पर जोर दिया। NDA ने ठोस सरकारी नौकरी का वादा भले ही न किया हो, लेकिन नौकरी तलाश रहे युवाओं को 1000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देने की बात तो की ही है।

रोजगार का सवाल । ऐसे में बिहार चुनाव का युवा वर्ग के लिए क्या अर्थ है? क्या बेरोजगारी के जाल से बचने की कोशिश कर रहे गरीब युवाओं की आवाज सुनाई देगी या वे सिर झुकाए प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में डूबा एक मूक तबका बने रह जाएंगे? बिहार की आबादी का करीब एक तिहाई युवा है। युवा बेरोजगारी दर भी काफी ऊंची (करीब 10%) है।

कोचिंग सेंटर की दुनिया । एक समय में उच्च शिक्षा का प्रतिष्ठित केंद्र माना जाने वाला पटना विश्वविद्यालय शिक्षा और नौकरी की तलाश में गांवों और छोटे शहरों से यहां पहुंचने वाले युवाओं की निगाह से उतर चुका है। विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बजाय ये युवा उसके सामने स्थित मुसल्लहपुर हाट की संकरी गलियों में पांव टिकाने की कोशिश करते हैं। यह इलाका किसी जमाने में सब्जियों का बड़ा हाट हुआ करता था। यहां के कई कोल्ड स्टोरेज और गोदाम अब कोचिंग सेंटर का रूप ले चुके हैं।

बेरोजगारों की पिछली पीढ़ी । ये सेंटर खान सर, गुरु रहमान और सम्राट अशोक जैसे स्वघोषित एजुकेटर्स से जुड़े हैं जो बेरोजगार युवाओं की पिछली पीढ़ी से वास्ता रखते हैं। सरकारी नौकरी की जो परीक्षा ये खुद नहीं निकाल सके, उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी कराने के व्यवसाय में अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी को पार्टी पॉलिटिक्स और करप्शन का ऐसा अड्डा बताते हैं, जहां सिर्फ वक्त बर्बाद होता है।

AI Image

युवा शक्ति पर बंदिशें
- विश्वविद्यालय युवा उम्मीदों के केंद्र नहीं रहे
- जॉब्स के ख्वाब पर पल रहे हैं कोचिंग सेंटर
- प्रोटेस्ट के हौसले पर भारी रोजगार का गम

वर्चस्व का टकराव । इन गलियों को ऐसी अराजनीतिक जगह बताया जाता है, जहां सिर्फ मेहनती युवा होते हैं। सचाई यह है कि दो पिछड़ी जातियां - कुर्मी और कुशवाहा - कोचिंग इलाकों में वर्चस्व के लिए टकराती रहती हैं। ये इन इलाकों में हॉस्टल और मेस चलाने के बिजनेस पर अपना कब्जा चाहते हैं। कुर्मियों का पटेल हॉस्टल यहां बड़ा प्रसिद्ध है। दूसरी ओर, कुशवाहा सम्राट अशोक से अपना नाता मानते हुए इस पूरे इलाके को अपना बताते हैं।

कुछ निष्कर्ष । अगर मोटे तौर पर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो इन बातों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं?

- कृषि संकट और भूमिहीनता के कारण पलायन को मजबूर युवा सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए बेकरार हैं।
- बिहार की राजनीति को लालू, नीतीश और सुशील मोदी जैसे नेता देने वाले विश्वविद्यालय अब युवा उम्मीद का स्थान नहीं रहे। राजनीतिक विरोध अब विकल्प नहीं है। इससे युवा का 'चरित्र' खराब होता है और उसे सरकारी नौकरी के लिए अपात्र घोषित किया जा सकता है।
- गली संस्कृति जाति या आरक्षण पर बात नहीं करती, लेकिन युवाओं को कुर्मी और कुशवाहा की ताकत का अहसास कराती है। ओबीसी की ये जातियां गली में तो वर्चस्व के लिए आपस में लड़ती हैं, लेकिन राजभवन में सत्ता साझा करती हैं।
- सुरक्षित नौकरी का वादा युवाओं के लिए खासा अहम है, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कोचिंग वाले सरों और स्थानीय नेताओं के कंट्रोल में है, जिनका कहा वे टाल नहीं सकते। उनका भविष्य चुपचाप नौकरी की तैयारी करने और राजनीति से दूरी बनाए रखने में है।

(लेखिका मोनैश यूनिवर्सिटी, मेलबर्न में विजिटिंग प्रफेसर हैं)

कांटे की बात

सोचिए जो गीत (वंदे मातरम्) देश की आजादी का मंत्र बना हो, उसे भी सांप्रदायिक कहकर उसमें संशोधन करने का प्रयास किया गया। कांग्रेस ने कहा कि पांच या छह छंद क्यों पढ़ना है दो छंद ही काफी हैं।

योगी आदित्यनाथ, *यूपी के मुख्यमंत्री*

AI की दुनिया

जब मशीन से बातचीत असली लगे, समझिए ख़तरा

एक शब्द इधर चर्चा में है AI Psychosis। कुछ लोग AI चैटबॉट्स से बातचीत के दौरान मानसिक भ्रम और खतरनाक सोच जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। वे वास्तविकता और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहे।

AI Image

सच और झूठ में भ्रम

AI Psychosis को लेकर हुई स्टडी बताती है कि चैटबॉट्स सच और झूठ के बीच की पहचान कमजोर कर सकते हैं। यूजर के सवालों का सकारात्मक लेकिन अधिकतर गैर-यथार्थवादी जवाब देते हैं। इससे उन यूजर्स में खासकर भ्रम बढ़ता है, जो पहले से मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। लोग काउंसिलिंग, सपोर्ट या स्यूसाइड प्रिवेंशन जैसी मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के लिए चैटबॉट से मदद ले रहे हैं। कुछ मामलों में मशीन गलत रेस्पॉन्स दे देती है, तब मरीज के लिए दिक्कत बढ़ जाती है।

एक्सपर्ट ने दिए ये सुझाव

1. AI थेरेपी टूल्स का इस्तेमाल तभी करें जब पारंपरिक विकल्प न हो।
2. गंभीर मानसिक समस्या के लिए प्रफेशनल से संपर्क जरूर करें।
3. AI से मिले सुझाव अंतिम नहीं, इसे इंसानी थेरेपी का पूरक समझें।
4. चैटबॉट से बातचीत के बाद भ्रम हो तो साइकॉलजिस्ट से संपर्क करें

–प्रदीप तिवारी

जनता जंक्शन

इरफ़ान

रेल हादसे रोकने पर क्यों नहीं हुई बात

गुलशन राय खत्री

2014 से अब तक भारतीय रेलवे में कई बड़े बदलाव हुए हैं। नई वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। कई रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहे हैं और रेलवे का टिकटिंग सिस्टम लगभग डिजिटल हो चुका है। रेलवे सेफ्टी पर भी काम हो रहा है। 2014-15 में जहां सालाना 135 दुर्घटनाएं होती थीं, वहीं 2022-23 में यह संख्या 48 पर आ गई। फिर भी सिग्नल की गड़बड़ी, मानवीय चूक और तकनीकी खराबी के चलते होने वाली रेल दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं।

गंभीर हादसों का असर । पिछले मंगलवार को एक बार फिर एक यात्री ट्रेन ने खड़ी मालगाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्री ट्रेन का न सिर्फ इंजन बल्कि एक कोच भी मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। इससे पहले बालासोर में भी इसी तरह का बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हालांकि कुल रेल दुर्घटनाओं में ऐसे गंभीर हादसों का प्रतिशत महज 14 ही है लेकिन ये एक्सीडेंट मन-मिजाज पर ज्यादा असर करते हैं।

कॉमन रूम

खुले फाटकों की समस्या । ऐसा नहीं कि रेलवे में एक्सीडेंट कम करने पर कोई काम नहीं हुआ। कुछ साल पहले तक सबसे अधिक एक्सीडेंट बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर होते थे। सुरेश प्रभु के कार्यकाल में इस पर तेजी से काम हुआ और जैसे-जैसे खुले रेल फाटकों पर चौकीदार तैनात करके बैरियर लगाए गए, इन दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आती गई। अब जरूरत है कि रेलवे, डिरेलमेंट और ट्रेनों की टक्कर रोकने पर जोर दे।

फॉल्स अलार्म । कुछ साल पहले मुरादाबाद और इलाहाबाद डिविजन में एक तकनीक का प्रयोग किया गया था। इसमें व्यवस्था यह थी कि अगर ट्रेक में कहीं क्रेक हो तो अलार्म बज जाए। दिक्कत यह हुई कि इस प्रयोग में कई बार फॉल्स अलार्म बज रहा था। बिना किसी क्रेक के ही गलत अलार्म बजने का प्रतिशत 30 तक जा पहुंचा था। लिहाजा, माना गया कि बार-बार गलत अलार्म बजने से ट्रेनें बिना वजह लेट होंगी। सो, इस तकनीक को रोक दिया गया।

कवच में देर । कवच प्रणाली में देरी की एक वजह ये रही कि उससे पहले यूरोप की ETCS प्रणाली लागू करने पर विचार हुआ था। ये प्रणाली न सिर्फ ट्रेनों की टक्कर रोकती है बल्कि एक तय सीमा से अधिक की स्पीड पर जाते ही ट्रेनों में ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेक लगा देती है। लेकिन यह काफी महंगी पड़ रही थी। आकलन करने पर पाया गया कि यूरोपीय तकनीक के मुकाबले भारत की कवच प्रणाली लगभग आधे दाम में लग जाएगी। सो इसे ही चुना गया और अब कवच तकनीक से भारतीय ट्रेनों को लैस करने की दिशा में काम चल रहा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

जब भावनाएं हैं ऑफ़लाइन क्या करेंगे ऑनलाइन रिश्ते

संजय तेवतिया

विज्ञान और तकनीक ने जीवन को जितना आसान बनाया है, उतना ही मनुष्यता को भीतर से कठोर बना रहा है। स्वभाव में लचीलेपन का अभाव दिख रहा है। हम स्मार्टफोन और AI के युग में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे भीतर का संवेदनशील मनुष्य पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे समय में अपने भीतर दया-भाव को बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ नैतिक गुण नहीं, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है।

मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख-सुविधाओं से पूर्ण नहीं होता। यदि आत्मा में शुद्धि और करुणा नहीं है, तो हर उपलब्धि अधूरी रह जाती है। दया वह शक्ति है जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता देती है। यह संवेदनशीलता बनाए रखती है और मनुष्य को ईश्वर से और मानवता से जोड़ती है।

डिजिटल दुनिया में, जहां रिश्ते ऑनलाइन हैं और भावनाएं ऑफलाइन, वहां दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना कठिन होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम संवेदना तो दिखाते हैं, पर व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में यदि कोई मनुष्य सच्चे अर्थों में करुणामय है, दूसरों की मदद करता है, पशु-पक्षियों या प्रकृति के प्रति दया रखता है, तो वही सबसे बड़ी पूंजी है।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

प्राचीन ऋषियों ने कहा था, 'अहिंसा परमो धर्मः'। इसका मतलब है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी भी जीव के प्रति हिंसा, क्रोध या द्वेष नहीं रखते, तो हमारा मन निर्मल होता है। यह संदेश आज जलवायु संकट, युद्ध और सामाजिक विभाजन के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है। इसलिए दया सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का आधार है। यह धर्म, भाषा, देश और विचारों से परे जाकर मानवता से जोड़ती है। जब हम दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं, तब न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि समाज में संतुलन और शांति भी स्थापित होती है। इसलिए आज के इस भागदौड़ और असंवेदनशील समय में दया को अपनाना सबसे बड़ी ताकत है। जो हृदय करुणा से भरा है, वही सच्चे अर्थों में आधुनिक, धार्मिक और ईश्वर के निकट है।

SIR पर क्या विपक्षी दल एकजुट बने रहेंगे

हेमंत राजौरा

विशुद्ध राजनीति कसौटी

चुनाव आयोग की ओर से नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होने के साथ इस पर सियासत भी तेज हो रही है। बिहार में SIR लागू होने पर विपक्षी दलों ने मिलकर आरोप लगाया कि यह खास समुदायों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास है। अब जब यह अभियान तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में आगे बढ़ा है तो इसका विरोध और तेज हो गया है। राज्यों में स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ रहने वाले विपक्षी दल इस मुद्दे पर बैठक करते दिख रहे हैं। दूसरी ओर, BJP और उसके समर्थक दल इसे चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का कदम बता रहे हैं।

ममता-कांग्रेस साथ आए

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बड़े मार्च का नेतृत्व करते हुए SIR को वोट धांधली की तैयारी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP इस प्रक्रिया का उपयोग उन वर्गों और क्षेत्रों को निशाना बनाने के लिए कर रही है, जहां विपक्ष मजबूत है। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची का हवाला देते हुए कहा कि जिस सूची के आधार पर BJP सत्ता में आई, अब उसी को अवैध बता रही है।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर SIR को चुनौती दी है। स्टालिन के नेतृत्व में DMK और 46 अन्य पार्टियों ने राज्य में इस मुद्दे पर बैठक की और साझा विरोध करने का फैसला किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस समेत अधिकतर दल राज्य सरकार के साथ दिखे।

SIR विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब 2026 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष संशोधन की प्रक्रिया इन राज्यों में राजनीतिक संतुलन पर असर डाल सकती है। ऐसे में SIR वह मुद्दा बनता जा रहा है, जिसने विपक्ष को फिर साझा मंच पर आने का अवसर दिया है। बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और कथित वोट चोरी के खुलासों ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच जमी बर्फ को पिघलाया है। I.N.D.I.A. ब्लॉक की बैठकों में अब तृणमूल के वरिष्ठ नेता भी शामिल हो रहे हैं। अगस्त में राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को कर्नाटक में कथित वोट चोरी के सबूत दिखाए थे। तब विपक्ष ने SIR के खिलाफ साझा आंदोलन की रणनीति बनाई थी और संसद में मिलकर इसका विरोध किया था। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले हरियाणा में वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी SIR पर विपक्ष के एकजुट होने की बात कही।

क्या एकजुट हो पाएगा विपक्ष

हालांकि विपक्षी एकता की राह उतनी सीधी नहीं है। बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल आमने-सामने हैं, केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा प्रतिद्वंद्वी हैं और पंजाब व दिल्ली में आप और कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाती रही हैं। ऐसे में क्या यह मुद्दा विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? या यह भी कई अन्य मुद्दों की तरह सिर्फ विरोध सभाओं, बयानों और अदालती याचिकाओं तक सीमित रह जाएगा? यदि विपक्ष इसे राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना पाता है तो यह 2026 और 2027 के चुनावों से पहले राजनीतिक परिदृश्य को बदले की क्षमता रखता है, लेकिन यदि विरोध असंगठित, बिखरा या राज्य विशेष तक सीमित रहा तो NDA को इसका लाभ होगा।

रीडर्स मेल

नेतृत्व की विश्वसनीयता

10 नवंबर का लेख 'क्या रेवड़ी तय करेगी जीत' पढ़ा। लेखक ने राजनीति में 'रेवड़ी कल्चर' पर गहरे और संतुलित विचार पेश किए हैं। नकद सहायता देने या वादे करने से चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव में जातीय समीकरण, विकास और नेतृत्व की विश्वसनीयता अधिक प्रभावी होती है। नीतीश कुमार ने बिहार को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाया है, और चुनाव परिणाम केवल मुफ्त योजनाओं का नतीजा नहीं, बल्कि शासन और सामाजिक समीकरणों के मिश्रित प्रभाव की झलक देंगे।

प्रियंका श्रीवास्तव, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन: 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क: 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार: नेपाली 5 रु.; रविवार: नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट): आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

खबरों में रहे स्टॉक

कैरीसिल

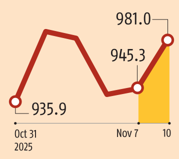

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 62 प्रतिशत बढ़ा

₹ 945.3 पिछला बंद भाव
₹ 981.0 आज का बंद भाव
3.8 % ▲

एमक्योर फार्मास्युटिकल्स

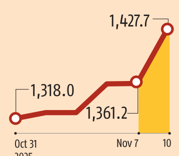

भारत में पोविजट्रा के व्यवसायीकरण को नोवो नॉर्डिस्क के साथ साझेदारी

₹ 1,361.2 पिछला बंद भाव
₹ 1,427.7 आज का बंद भाव
4.9 % ▲

ग्रेफाइट इंडिया

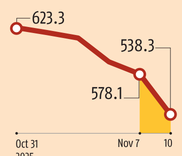

दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 61 प्रतिशत लुढ़का

₹ 578.1 पिछला बंद भाव
₹ 538.3 आज का बंद भाव
-6.9 % ▼

सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया

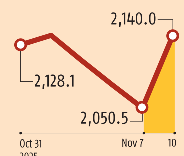

वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 58 प्रतिशत बढ़ा

₹ 2,050.5 पिछला बंद भाव
₹ 2,140.0 आज का बंद भाव
4.4 % ▲

एपिग्रल

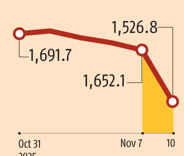

दूसरी तिमाही के दौरान शुद्ध लाभ पिछले साल की तुलना में 37 प्रतिशत घटा

₹ 1,652.1 पिछला बंद भाव
₹ 1,526.8 आज का बंद भाव
-7.6 % ▼

वोडा-आइडिया का घाटा घटा

बीएस संवाददाता और भाषा
नई दिल्ली/मुंबई, 10 नवंबर

सितंबर 2025 में समाप्त तिमाही के दौरान वोडाफोन आइडिया (वी) का समेकित शुद्ध घाटा घटकर 5,584 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही (वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही) में 7,176 करोड़ रुपये था। घाटे में यह कमी उद्योग जगत की मौजूदा चुनौतियों के बावजूद कंपनी के परिचालन में सुधार को दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में राजस्व 2.4 फीसदी बढ़कर 11,194.7 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में 10,932 करोड़ रुपये था। एबिटा 4,685 करोड़ रुपये रहा, जो 4,550 करोड़ रुपये से अधिक है। वित्त की लागत घटकर 4,784 करोड़ रुपये रह गई, जो पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समान तिमाही में 6,613.6 करोड़ रुपये थी।

वी के मुख्य कार्याधिकारी अभिजित किशोर ने कहा, 'हम अपना 4जी कवरेज बढ़ाकर 90 फीसदी आबादी तक पहुंचाने और 5जी हैंडसेटों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ क्षेत्रों में 5जी उपस्थिति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम 500-550 अरब रुपये की अपनी व्यापक पूंजीगत व्यय योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऋणदाताओं के साथ जुड़े हुए हैं।'

बजाज फाइनैंस का शुद्ध मुनाफा 24 प्रतिशत नीचे आया

बजाज फाइनैंस ने सोमवार को बताया कि जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ एकल आधार पर 24 फीसदी घटकर 4,251 करोड़ रुपये रह गया। इसका कारण कर्ज के नुकसान को लेकर ज्यादा प्रावधान था।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष की इसी अवधि में वित्तीय कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में बजाज हाउसिंग फाइनैंस के इक्विटी शेयरों की बिक्री के कारण 2,544 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ दर्ज किया था। एकीकृत आधार पर बजाज फाइनैंस का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 23 फीसदी बढ़कर 4,948 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इस तिमाही में इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर 9,275 करोड़ रुपये रही, क्योंकि ऋणदाता द्वारा दिए नए ऋणों की संख्या वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 26 फीसदी बढ़कर 1.2 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संख्या 95.9 लाख रही थी।

जिंदल स्टेनलेस के शुद्ध लाभ में 32 प्रतिशत की उछाल

जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 32 प्रतिशत बढ़कर 808 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने बयान में कहा कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 609 करोड़ रुपये था। बयान के अनुसार, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की कुल आय 12 प्रतिशत बढ़कर 10,982.46 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले की समान अवधि में 9,823.88 करोड़ रुपये थी।

इमामी के लाभ में 29.7% गिरावट

रोजमर्रा की जरूरत का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली घरेलू कंपनी इमामी लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ 29.7 प्रतिशत घटकर 148.35 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी ने सोमवार को शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। कंपनी ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती की उम्मीद में अस्थायी रूप से बिक्री घटने और कुछ उत्पाद श्रेणियों पर अत्यधिक बारिश के प्रभाव के कारण उसका मुनाफा कम हुआ। कोलकाता स्थित इस कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 210.99 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ कमाया था।

केपीआईटी का शुद्ध मुनाफा 17 प्रतिशत लुढ़का

मझोली श्रेणी की आईटी सेवा कंपनी केपीआईटी का शुद्ध लाभ दूसरी तिमाही में 17 प्रतिशत घटकर 169 करोड़ रुपये रह गया। एक साल पहले इसी तिमाही में उसे 203.7 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। मुनाफे में यह गिरावट संयुक्त उद्यम में लगभग 23 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण हुई। परिचालन राजस्व लगभग 8 प्रतिशत बढ़कर 1,587.7 करोड़ रुपये हो गया। इसे संबंद्ध, स्वचालित वाणिज्यिक वाहनों और यूरोपीय बाजार में वृद्धि से मदद मिली जिससे लंबे समय की नरमी के बाद सुधार का संकेत मिलता है।

हुडको का शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 3 प्रतिशत मजबूत

हाउसिंग ऐंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) ने सोमवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ तीन प्रतिशत बढ़कर 710 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 689 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। हुडको ने शेयर बाजार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 2,526 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,251 करोड़ हो गई।

संक्षेप में

वरुण बेरी का ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज से इस्तीफा

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के पद से वरुण बेरी ने इस्तीफा दे दिया है। बेरी 13 वर्षों से ब्रिटानिया में थे। शेयर बाजार को दी गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में कहा गया है कि फाइलिंग में कहा गया है कि बेरी ने 6 नवंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फाइलिंग में कहा गया है, 'कंपनी के निदेशकों ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, सोमवार को हुई अपनी-अपनी बैठकों में उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और वरुण बेरी की नोटिस अवधि पूरी करने की बाध्यता को माफ कर दिया।' पिछले हफ्ते ब्रिटानिया में मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किए गए रक्षित हर्गवे 15 दिसंबर से प्रबंध निदेशक का पद भी संभालेंगे। *बीएस*

गूगल के प्रभु रामभद्रन रेजरपे में नियुक्त

फिनटेक कंपनी रेजरपे ने प्रभु रामभद्रन को इंजीनियरिंग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। दो दशकों से अधिक के अनुभव वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्र के दिग्गज रामभद्रन इंजीनियरिंग टीमों और उद्यम स्तरीय प्रणालियों के निर्माण और विस्तार की गहरी समझ रखते हैं। वे गूगल क्लाउड से रेजरपे में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने क्लाउड सुरक्षा, गूगल के एपीआई प्रबंधन समाधान और कई उद्यम सॉफ्टवेयर उत्पादों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास की अगुआई की। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब रेजरपे एआई-प्रथम, वैश्विक रूप से अनुकूल प्लेटफॉर्म बनाने के अपने दृष्टिकोण को रफ्तार दे रही है। *बीएस*

बोल्ट डॉट अर्थ की नजर मुनाफे पर

सोहिनी दास
मुंबई, 10 नवंबर

भारत में सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग नेटवर्क मुहैया कराने वाली बेंगलूरु स्थित कंपनी बोल्ट डॉट अर्थ को उम्मीद है कि वह वित्त वर्ष 2027 में लाभ की स्थिति में आ जाएगी और 2027 या 2028 की शुरुआत में आईपीओ लाएगी। ईवी को अपनाने का चलन महानगरों से आगे बढ़कर टियर-2 और 3 शहरों में भी तेजी से बढ़ रहा है।

कंपनी के सीईओ एस राघव भारद्वाज का दावा है कि यह मुनाफे में आने वाली पहली ईवी चार्जिंग नेटवर्क प्रदाता होगी। 1800 शहरों और कस्बों (लक्षद्वीप सहित) में 1,00,000 से ज्यादा चार्जर लगाने के बाद कंपनी का लक्ष्य 2028 तक सालाना 10 लाख चार्जर लगाना है, क्योंकि यह विकास के अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है।

उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि अगले साल के मध्य तक हम मुनाफे में आ जाएंगे और इससे हमें आईपीओ की तैयारी शुरू करने के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिलेगा है। हम और हमारे निवेशक, दोनों ही 2027 के आसपास या 2028 की शुरुआत में संभावित लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर, पहले से ही सार्वजनिक ईवी चार्जिंग कंपनियां मौजूद हैं और मुझे लगता है कि भारत भी ईवी अपनाने के पैमाने के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है।'

उन्होंने कहा, 'आज, भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी वे बहुत ज्यादा नहीं हैं। एक बार जब हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या पेट्रोल वाहनों से अधिक हो जाएगी, तो बाजार रॉकेट की तरह तेजी से उड़ान भरेगा और तब चार्जिंग इकोसिस्टम वास्तव में फलेगा-फूलेगा। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक स्तर पर हो रहे प्रयासों के बावजूद, मैंने अभी तक दुनिया में कहीं भी एक भी लाभदायक

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कंपनी नहीं देखी है। इस क्षेत्र में लाभप्रदता हासिल करना हमें एक खास स्थिति में रखता है।'

भारद्वाज ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि इस वित्त वर्ष में कंपनी का राजस्व 50 लाख डॉलर रहने की संभावना है, जो अगले वित्त वर्ष में चार गुना बढ़कर 2 करोड़ डॉलर हो जाएगा। उनका कहना है कि निवेश पर बेहतर रिटर्न (आरओआई) और लाभप्रदता की राह का कारण इसका बिजनेस मॉडल है।

भारद्वाज का कहना है कि उनके नेटवर्क में उनकी औसत उपयोग दर लगभग 18-20 प्रतिशत है।

लगभग 60 प्रतिशत नए तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हैं, जबकि दोपहिया वाहनों में ईवी की पहुंच 40 प्रतिशत तक हो गई है। लगभग 90-95 प्रतिशत चार्जिंग अब घरों, कार्यालयों और निजी स्थानों पर होती है। बोल्ट.अर्थ ने पहले दोपहिया और तिपहिया चार्जिंग पर ध्यान केंद्रित किया, फिर चार पहिया फास्ट चार्जिंग सेवा का विस्तार किया।

इसने हाल में उसने दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए बनाया गया ब्लेज डीसी फास्ट चार्जर लॉन्च किया है, जो सभी ओईएम और प्रोटोकॉल (टाइप 6, टाइप 7 चार्जिंग) पर काम करता है।

1 प्रतिशत प्रति मिनट की फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ एक वाहन 15 मिनट में 40-50 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। स्विगी, जेप्टो, रैपिडो जैसे फ्लीट ऑपरेटर इसके लक्षित क्षेत्र होंगे। भारद्वाज का कहना है कि ब्लेज डीसी चार्जर्स आगामी नेटवर्क का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होंगे।

शैलेश चंद्रा ओआईसीए प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय

अंजलि सिंह
मुंबई, 10 नवंबर

ऑर्गनाइजेशन इंटरनैशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स (ओआईसीए) ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) के अध्यक्ष और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा को 1 नवंबर, 2025 से शुरू होने वाले कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। वह एलायंस फॉर ऑटोमोटिव इनोवेशन, अमेरिका के अध्यक्ष और सीईओ जॉन बोजेला का स्थान लेंगे।

चंद्रा ओआईसीए का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जो वैश्विक ऑटोमोटिव निर्णय लेने में भारत की उपस्थिति के लिए एक महत्त्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा, 'भारत से पहला ओआईसीए अध्यक्ष बनना सम्मान की बात है। इससे संगठन का वैश्विक प्रतिनिधित्व जाहिर होता है।' उन्होंने कहा कि उद्योग सतत गतिशीलता और नेट-जीरो लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में क्षेत्रीय विविधता को स्वीकार करने में ओआईसीए की भूमिका अहम होगी क्योंकि हम सब मिलकर अपने वाहनों को अधिक आकांक्षी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं।

जेबीएम ऑटो लिमिटेड
(CIN: L74899HR1996PLC123264)
पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 133, सेक्टर 24, फरीदाबाद - 121 005 (हरियाणा)
ई–मेल: secretarial.jbma@jbmgroup.com
वेबसाइट: www.jbmgroup.com
JBM Group Our milestones are touchstones

पोस्टल बैलेट का नोटिस और रिमोट ई–वोटिंग की सूचना

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110, आम बैठकों पर सचिवालयीन मानदंड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में तथा रिमोट ई–वोटिंग से पोस्टल बैलेट के संचालन हेतु समय–समय पर कार्पोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी संगत परिपत्रों और अन्य लागू वैधानिक कानूनों और विनियमों (इनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक सुधारों या अधिनियमन और समय समय पर किए गए संशोधनों सहित), यदि कोई है, के अनुपालन में, कंपनी केवल रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट ई–वोटिंग) के तहत **पोस्टल बैलेट नोटिस दिनांक 30 अक्टूबर, 2025** के तहत यहां नीचे निर्धारित किए गए संकल्पों के लिए अपने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना चाहती है:

क्रम सः	संकल्प का विवरण	संकल्प की प्रकृति (विशेष/साधारण)
1.	जेबीएम ईकोलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सामग्री संबंधी पक्ष लेनदेन	साधारण

याख्यात्मक विवरण के साथ पोस्टल बैलट नोटिस ई–मेल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषण की प्रक्रिया **सोमवार, 10 नवंबर, 2025** को पूरी हो गई है। कंपनी ने केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिनटेक') को अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त किया है।

पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट https://jbmbuses.com/jbm-auto-ltd/agm-notice-to-shareholders/ केफिनटेक–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस प्राप्त नहीं होता है, वे इसे ऊपर बताई गई किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

वर्तमान में लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप, सदस्य उक्त प्रस्तावों पर केवल रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकते हैं, **जो मंगलवार, 11 नवंबर, 2025 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और बुधवार, 10 दिसंबर, 2025 को सायं 05.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी**, जिसके बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

केवल वे सदस्य उक्त प्रस्तावों पर अपना मत देने के हकदार हैं, जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में **कट–ऑफ तिथि, अर्थात शुक्रवार, 31 अक्टूबर, 2025** को दर्ज थे, एक बार किसी प्रस्ताव पर मतदान करने के बाद, सदस्य को बाद में उसे बदलने या दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं होगी। दूरस्थ ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश नोटिस में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों के ईमेल पते पंजीकृत/अद्यतित नहीं हैं और इसलिए, उन्हें अभी तक उपरोक्त सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे अपना विवरण निम्नलिखित तरीके से पंजीकृत कर सकते हैं:

क. जिन सदस्यों के शेयर डीमैट रूप में हैं और जिनका ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतित नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतित करा लें।

ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिनका ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आरटीए) को admin@mcsregistrars.com पर पत्र भेजकर या +91 11 41406151 पर संपर्क करके अपना ई–मेल पता पंजीकृत/अद्यतन करें।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए e-voting@kfintech.com पर या 1800 309 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

डाक मतपत्र के परिणाम रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति की तिथि से दो कार्यदिवसों के भीतर घोषित किए जाएँगे। घोषित परिणाम, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट https://jbmbuses.com/jbm-auto-ltd/scrutinizer-report-e-voting-results/ और केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध होंगे। कंपनी द्वारा ऐसे परिणाम एनएई और बीएसई को भी भेजे जाएँगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं और उनकी संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए जाएँगे।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के समाधान के लिए संपर्क विवरणः

नामः पेरला एस एन कमल क्रांति,
ईमेल आईडीः Kranthi.perla@kfintech.com
संपर्क नंबरः 091 4067161637
पताः केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टावर–बी, प्लॉट संख्या 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032, भारत

सेबी ने कंपनी/आरटीए को भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सभी सदस्यों से पैन कार्ड, केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फॉर्म आदि की प्रतियाँ प्राप्त करने का आदेश दिया है। इसलिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित दस्तावेजों/विवरणों के साथ पैन, केवाईसी और अन्य विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराएँ। इसके अतिरिक्त, डीमैटरियलाइजेशन के अंतर्निहित लाभ प्राप्त करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को यथाशीघ्र डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित कर लें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://jbmbuses.com/jbm-auto-ltd/forms-for-registering-updating-the-kyc-details/ पर जाएँ।

कृते **जेबीएम ऑटो लिमिटेड**
हस्ता/-
संजीव कुमार
कंपनी सचिव और अनुपालना अधिकारी
सदस्यता सं. 18087

स्थानः गुरूग्राम
दिनांकः 10.11.2025

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरण के लिए विज्ञापन
क्षेत्रीय निदेशक (केंद्रीय सरकार), उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, कॉरपोरेट कार्य मामले के मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में
"बीई इंजीनिरिंग सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड"
सीआईएन - U74900DL2007PTC159814
पंजीकृत कार्यालय बी-59 (एलजीएफ) सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017 के मामले में
...याचिकाकर्ता

सूचना

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र" से "कर्नाटक राज्य" में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 को आयोजित अठारहवीं वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टी की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन क्षेत्रीय निदेशक (केंद्रीय सरकार), उत्तरी क्षेत्रीय पीठ के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है।

कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, वे अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों के अंदर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ, पता बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉमप्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके नीचे उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:
बी-59 (एलजीएफ) सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110017, भारत

बीई इंजीनिरिंग सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/-
सव्यसाची किट्टने श्रीनिवास
निदेशक
डीआईएनः 06525882

दिनांकः 11 नवम्बर, 2025
स्थानः नई दिल्ली

आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
(कारपोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC053579)
पंजीकृत कार्यालय : जीएफ-1-ए, 6, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
कारपोरेट कार्यालय : तीसरी मंजिल, टॉवर न० 1, आईटी/आईटीईएस एसईजैड ऑफ अर्था इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड, प्लॉट न० 21, सेक्टर टेकजोन-IV, ग्रेटर नौयडा वेस्ट, गौतम बुद्ध नगर, उ०प्र०,- 201 306, इण्डिया
दूरभाष: +91 120 4303500; ईमेल: rsil@rsystems.com; वेबसाइट : www.rsystems.com

शेयरधारकों हेतु सूचना - भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल कराने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक जुलाई 02, 2025, के अनुसार, आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड ("कम्पनी") के शेयरधारकों को एत्दद्वारा सूचित किया जाता है कि जुलाई 07, 2025 से जनवरी 06, 2026 तक छः माह की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है जिसमें उन भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है जो अप्रैल 01, 2019 से पहले प्रस्तुत किये गये थे, और दस्तावेजों, प्रक्रिया अथवा अन्य कमियों के कारण अस्वीकार कर दिये गये थे। इस अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किये गये शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैट मे ही किया जायेगा। ऐसे हस्तांतरण–सह–डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

जो शेयरधारक इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, एमयूएफजी इनटाइम इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, नोवल हाईट्स, प्रथम मंजिल, प्लॉट न० एनएच-2, सी-1 ब्लॉक, एलएससी, सावित्री मार्किट के नजदीक, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058, ईमेल आईडीः Investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com, दूरभाषः 011 - 49411000, से सम्पर्क करें।

कृते आर सिस्टम्स इन्टरनेशनल लिमिटेड
भास्कर दुबे
(कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

दिनांक : नवम्बर 11, 2025
स्थान : ग्रेटर नौयडा (उ०प्र०)

CHL LIMITED
Regd. Office: Hotel The Suryaa, New Friends Colony, New Delhi 110025
Tel.: 91-11-26835070, 47808080, **Fax:** 26836288, **E-mail:** cs@chl.co.in
CIN No: L55101DL1979PLC009498
THE SURYAA NEW DELHI

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE PERIOD ENDED 30th SEPTEMBER 2025

(INR in Lacs)

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025	30.09.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations(net)	2,376.75	2,681.44	4,779.81	4,849.44	11,134.38	3,545.28	3,766.98	7,149.94	7,049.92	15,229.92
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,550.74	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	887.28
3	Net Profit/(Loss) for the period (after exceptional items)	(581.69)	753.82	98.70	1,276.67	3,436.57	(1,340.96)	(36.93)	(1,246.60)	(238.19)	773.12
4	Net Profit/(Loss) for the period (after tax & exceptional items)	(444.27)	563.91	98.70	954.62	2,492.56	(1,203.54)	(226.85)	(1,285.56)	(560.24)	(170.90)
5	Total comprehensive income for the period [comprising Net Profit/(Loss) for the period & Other Comprehensive Income/(expense)]	(444.27)	563.91	59.74	954.62	2,475.01	(2,740.03)	(324.92)	(3,228.70)	(1,082.17)	(678.23)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37	1,096.37
7	Reserves excluding Revaluation Reserves**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Earning Per Share (a) Basic and Diluted (fully paid up equity share of Rs. 2/- each)	–0.81	1.03	0.11	1.74	4.51	(5.00)	(0.59)	(5.89)	(1.97)	(1.24)

** Reserves for standalone as on 31.03.2025, is Rs. 16,839.82 Lacs and for consolidated is Rs. (13,198.84) Lacs

NOTES :
1) The above is an extract of the detailed format of quarter & half year ended 30.09.2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of quarter & half year ended 30.09.2025 are available on the websites of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.chl.co.in).
2) The results for the quarter & half year ended 30.09.2025 have been subjected to limited review by the statutory auditors of the company.
3) The above results can be viewed on the website of the Company (www.chl.co.in) as well as on the website of the Bombay Stock Exchange (www.bseindia.com).

By Order of the Board
CHL LIMITED
Sd/-
(Luv Malhotra)
Managing Director
DIN 00030477

Place : New Delhi
Date : 10th November, 2025

PUBLIC NOTICE

It is informed to the General public that my client Shri Shantanu Sharma s/o Shri J.B. Sharma is the owner of property i.e. Residential Flat No. 201, 2nd Floor (Riddhi) Block Riddhi, Type MIG-I, Mahagun Puram, NH-24, Mehrauli, Ghaziabad, the said property is presently mortgage with SBI RACPC Arya Nagar Ghaziabad by him. The Original Sale Deed dated 04.03.2013 vide document no. 1679 of the said property is in dilapidated condition due to a fire incident at the IDBI document storage facility in Maharashtra when it was earlier mortgaged with IDBI Bank. It is to be noted that the said property will be treated as unencumbered (except the charge of SBI), clear & marketable. Anybody (Banking/ Financial Institutions/ Individuals) having any kind of interest/ claim/title/objection on the said property detailed here in above may submit the same to the undersigned within 15 days of the publication.

ANKUR JINDAL, (ADVOCATE)
B-215, LOHIA NAGAR
GHAZIABAD- 201001

दिल्ली संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. और डी.बी कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

संक्षेप में

महत्त्वपूर्ण खनिजों पर ऑस्ट्रेलिया से साझेदारी!

भारत की खनन नवाचार और महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग क्वींसलैंड की खनन तकनीक कंपनियों को करीब ला रही है। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्थाओं के बीच संसाधन क्षेत्र में सहयोग के नए चरण का संकेत दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खनिज राज्य क्वींसलैंड है। इस राज्य में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट और महत्त्वपूर्ण खनिज वैनेडियम व ग्रेफाइट हैं। क्वींसलैंड के व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने दो सप्ताह पहले भारत का दौरा किया था। दक्षिण एशिया के व्यापार और निवेश क्वींसीलैंड (टीआईक्यू) के वरिष्ठ व्यापार व निवेश आयुक्त अभिनव भाटिया ने बताया कि इस दल में खनन उपकरण, तकनीक और सेवाओं की नौ कंपनियों ने भारत आई थीं। इनमें से दो कंपनियां हैदराबाद के स्थानीय साझेदारों से समझौता कर चुकी हैं। हालांकि अन्य ने झारखंड के प्रमुख खनक के साथ पायलट परियोना शुरू की। भाटिया ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, 'ये शुरुआती सफलताएं संभावित रूप से भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना सहित जुड़ाव के अगले चरण के लिए मजबूत आधार बनाती हैं।' *बीएस*

इंडसइंड में अमिताभ सिंह सीएचआरओ नियुक्त

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने सोमवार को बताया कि उसने अमिताभ कुमार सिंह को मुख्य मानव संसाधन अधिकारी (सीएचआरओ) नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 10 नवंबर से प्रभावी है। सिंह बैंक के सीनियर मैनेजमेंट कर्मियों का भी हिस्सा होंगे। सिंह ने 21 वर्षों तक आईसीआईसीआई समूह के साथ काम किया है। उन्होंने आईसीआईसीआई समूह में अंतिम दायित्व आईसीआईसीआई होम फाइनैंस के सीएचआरओ का निभाया था। सिंह ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ आठ साल और आईसीआईसीआई बैंक के साथ 11 साल बिताए हैं। सिंह रांची एक्सआईएसएस से मानव संसाधन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। *बीएस*

भारतीय निर्यातक इस सप्ताह रूस जाएंगे

इंजीनियरिंग वस्तुओं के भारतीय निर्यातक इस सप्ताह रूस में आयोजित होने वाली चार दिवसीय प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य घरेलू वस्तुओं पर अमेरिका के लगाए भारी शुल्क के बीच देश के निर्यात को बढ़ावा देना है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय निर्यातकों का शीर्ष निकाय फियो के अध्यक्ष एससी रल्हन करेंगे। रल्हन ने कहा कि माइटेक्स-2025 घरेलू निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों के सामने अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल 14 नवंबर को मॉस्को में क्रेता-विक्रेता बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत के लिए रूस अहम व्यापारिक साझेदार रहा है और इंजीनियरिंग व उपकरण क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं हैं। *भाषा*

अर्थशास्त्रियों से बजट पर बात

भाषा
नई दिल्ली, 10 नवंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारियों को लेकर सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की और आगामी बजट पर उनके विचार जाने। बैठक में साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजारमन मौजूद थे।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, 'केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (सोमवार) नयी दिल्ली में आगामी आम बजट 2026-27 के संबंध में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ परामर्श बैठक की अध्यक्षता की।'

इसमें कहा गया, 'बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा डीईए के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।'

सीतारमण के एक फरवरी को बजट पेश कर सकती हैं। वह वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका के 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बीच बजट पेश करेंगी। अगले वित्त वर्ष के बजट में मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को आठ प्रतिशत से अधिक की निरंतर वृद्धि दर पर लाने के मुद्दों पर ध्यान देना होगा। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ेगी।

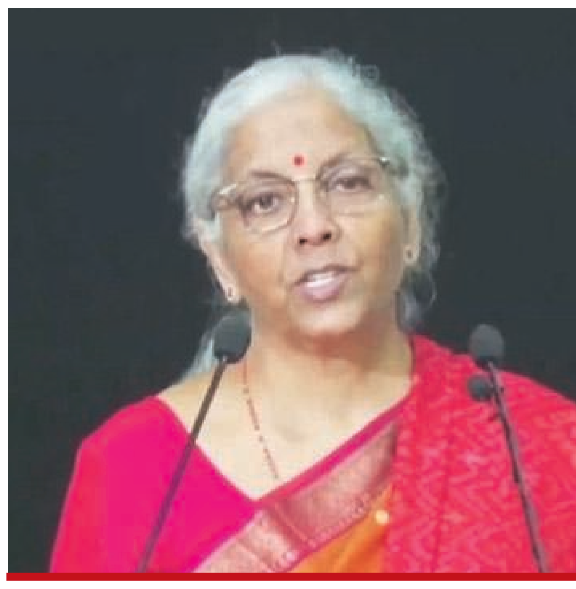

बजट की तैयारी

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साजिद चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, धर्मकीर्ति जोशी, रिधम देसाई, सोनल वर्मा और इंदिरा राजारमन से बातचीत की
- सीतारमण वैश्विक अनिश्चितता और भारत से निर्यात होने वाले सामान पर अमेरिका के 50 प्रतिशत के भारी शुल्क के बीच बजट पेश करेंगी
- कृषि विशेषज्ञों ने अनुसंधान कार्यों के लिए अधिक धनराशि के साथ कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की मांग की
- विशेषज्ञों ने फसल बीमा की नई अवधारणा तैयार करने की भी मांग की, क्योंकि अधिकांश किसान और राज्य इसके परिणामों से असंतुष्ट

कृषि क्षेत्र में आरऐंडडी के लिए अधिक धनराशि पर जोर

कृषि विशेषज्ञों ने सोमवार को जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियों के बीच अनुसंधान कार्यों के लिए अधिक धनराशि के साथ कृषि क्षेत्र के लिए मजबूत नीतिगत समर्थन की मांग की। परामर्श के दौरान उद्योग और अनुसंधान संगठनों के एक दर्जन से अधिक कृषि विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र की वृद्धि को मौजूदा स्तर से और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक में कृषि सचिव देवेश चौधरी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट, कृषि अर्थशास्त्री और उद्योग जगत के अंशधारकों ने भाग लिया। सूत्रों के अनुसार, 'बैठक सकारात्मक रही', जिसमें प्रतिभागियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डाला और सरकार से प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने की मांग की।

भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़ ने कहा कि पिछले दो दशकों में कृषि में अनुसंधान और विकास के लिए धन आवंटन वास्तविक रूप से कम हुआ है, और उन्होंने इस धनराशि को दोगुना करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने फसल बीमा की नई अवधारणा तैयार करने की भी मांग की, क्योंकि अधिकांश किसान और राज्य इसके परिणामों से असंतुष्ट हैं।

बेरोजगारी दर में आई गिरावट

शिवा राजौरा
नई दिल्ली, 10 नवंबर

- किंतु युवाओं की बेरोजगारी दर दूसरी तिमाही में बढ़ी
- वेतनभोगी कर्मचारियों की रोजगार में हिस्सेदारी घटी

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में श्रम बाजार में तेजी के कारण बेरोजगारी दर में कमी आई है, जबकि ज्यादा लोग काम की तलाश में आ रहे हैं। हालांकि युवा बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी और वेतनभोगी कामगारों की हिस्सेदारी में कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा सोमवार को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जारी तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़ों से पता चला है कि चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के संदर्भ में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के 5.4 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष2026 की दूसरी तिमाही में घटकर 5.2 प्रतिशत रह गई। सीडब्ल्यूएस में सर्वे की तारीख के पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर गतिविधियां निर्धारित की जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को संदर्भ अवधि के दौरान 1 घंटे का भी काम नहीं मिला होता है तो उसे बेरोजगार माना जाता है, अगर वह काम की तलाश में हो।

आंकड़ों से यह भी पता चलता है ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत रह गई है। वहीं शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 6.9 प्रतिशत हो गई है। दूसरी तिमाही के दौरान श्रम बल हिस्सेदारी दर (एलएफपीआर) घटकर 55.1 प्रतिशत हो गई है, जिसमें काम कर रहे या काम की मांग करने वाले लोग शामिल होते हैं। यह पहली तिमाही में 55 प्रतिशत थी।

शुल्क मामले में अमेरिकी कोर्ट पर नजर

श्रेया नंदी
नई दिल्ली, 10 नवंबर

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के शुल्कों को चुनौती देने वाले मामले पर भारत के अधिकारियों और विशेषज्ञों की करीबी नजर है। वे आकलन कर रहे हैं क्या इस मामले के फैसले का प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर कोई प्रभाव पड़ेगा। अभी इस समझौते को लेकर भारत और अमेरिका में बातचीत जारी है।

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पिछले सप्ताह हुई सुनवाई के दौरान दुनिया भर के कई देशों पर शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार पर संदेह जताया था। यह सवाल भी उठाया गया कि क्या एक आपातकालीन कानून ट्रंप को आयात में शुल्क निर्धारित करने और बदलने की शक्ति देता है।

भारत के अधिकारी आकलन कर रहे हैं क्या इस मामले के फैसले का प्रस्तावित भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर प्रभाव पड़ेगा

अमेरिका के संविधान के अनुसार शुल्क लगाने की शक्ति अमेरिकी संसद कांग्रेस के पास है। हालांकि पहली बार ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया है कि राष्ट्रपति को आयात को विनियमित करने की अनुमति देने वाले एक आपातकालीन कानून में शुल्क भी शामिल हैं।

अमेरिकी प्रशासन ने इस साल अप्रैल में घोषणा की थी कि वह अमेरिका के बढ़ते व्यापार घाटे को एक नैशनल इमरजेंसी बताते हुए ज्यादातर देशों पर व्यापक शुल्क लगाने की योजना बना रहा है।

सरकारी अधिकारी के अनुसार दोनों पक्षों के वार्ताकार मामले पर विचार कर रहे हैं। कोई भी कार्रवाई अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। अधिकारी ने कहा, 'हम वह देखेंगे। हर दूसरा देश भी ऐसा ही है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके तहत हम प्रक्रियाओं को देखेंगे। यह संभावना है जिस पर दोनों पक्ष विचार कर रहे हैं।' व्यापार और उद्योग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि भले ही सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुनाए लेकिन वह न्यायिक सीमाओं के बावजूद शुल्क के उपायों को आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति व्यापार भागीदारों को लक्षित करने के लिए अन्य कानूनों का उपयोग कर सकते हैं। अधिकारी ने कहा, 'यदि फैसला ट्रंप के पक्ष में नहीं जाता है तो भी राष्ट्रपति द्वारा किसी न किसी रूप में शुल्क लगाने की आशंका है। ट्रंप की नीति का पसंदीदा तरीका शुल्क को इस्तेमाल करना बना हुआ है। मुझे ऐसी स्थिति नहीं दिखती जहां उनका उपयोग देशों (भारत सहित) के खिलाफ नहीं किया जाए।'

व्यापार मामलों के अर्थशास्त्री विश्वजित धर ने कहा, 'असली सवाल यह है कि क्या भारत ट्रंप प्रशासन को कृषि में अपनी मूल रुचि से आगे देखने के लिए मना सकता है। यह शायद विनिर्माण या सेवाओं में मजबूत समझौता करके किया जा सकता है, जो उन्हें चीजों को अलग तरह से देखने के लिए मजबूर करे।'

त्योहारों के दौरान क्रेडिट कार्ड से व्यय 15% बढ़ा

आतिरा वारियर
मुंबई, 10 नवंबर

त्योहारों के मौसम में कुल मिलाकर खर्च बढ़ने और जीएसटी दरों में कटौती के कारण बैंकों के क्रेडिट कार्ड से खर्च बढ़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में क्रेडिट कार्ड से व्यय सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़ गया है।

प्रति कार्ड व्यय के मामले में एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर बना हुआ है, जबकि उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का स्थान है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले प्रमुख बैंकों में एचडीएफसी बैंक के प्रति कार्ड से व्यय सालाना आधार पर 2.8 प्रतिशत बढ़कर 23,959.8 रुपये हो गया है। एसबीआई कार्ड से खर्च सालाना आधार पर रिकॉर्ड 33.5 प्रतिशत बढ़कर 18,892.3 रुपये हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक से प्रति कार्ड व्यय 27.4 प्रतिशत बढ़कर 22,817.6 रुपये हो गया है। वहीं ऐक्सिस बैंक के क्रेडिट कॉर्ड से प्रति कार्ड व्यय सालाना आधार पर 33.4 प्रतिशत बढ़कर 16,884.6 रुपये हो गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के क्रेडिट कॉर्ड से प्रति कार्ड व्यय में पिछले एक साल में तेज वृद्धि हुई है। केयरएज के विश्लेषकों का कहना है कि सरकारी बैंकों के प्रति क्रेडिट कार्ड व्यय में वृद्धि की वजह बड़े पीएसबी द्वारा डिजिटल और रिवॉर्ड पेशकश में वृद्धि है। विश्लेषकों ने रिपोर्ट में कहा है, 'इसके अलावा पीएसबी के क्रेडिट कार्डों से अधिक व्यय की एक वजह इन बैंकों द्वारा ज्यादा आमदनी वाले ग्राहकों को अधिक क्रेडिट लिमिट दिया जाना है। इसके अलावा रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के साथ साझेदारी और डिजिटल सक्रियता की वजह से भी क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है।' विशेषज्ञों के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्रति कार्ड खर्च सितंबर 2025 में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत बढ़कर 19,107.6 रुपये हो गया, जिसकी वजह जीएसटी दर में संशोधन और त्योहारी सीजन के कारण महंगी खरीदारी है।

अक्टूबर में स्वास्थ्य बीमा में रिकॉर्ड तेजी

आतिरा वारियर
मुंबई, 10 नवंबर

गैर जीवन बीमाकर्ताओं की अक्टूबर में वृद्धि दर स्थिर रही है, वहीं एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने सालाना आधार पर प्रीमियम में रिकॉर्ड 38 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि खुदरा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में तेजी की वजह से हुई है, जिसे वस्तु एवं सेवा कर दरों में कटौती के कारण लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ने से रफ्तार मिली। साथ ही 1/एन अकाउंटिंग मानकों के नॉर्मलाइजेशन का भी असर पड़ा है।

जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के प्रीमियम में अक्टूबर में सालाना आधार पर 38.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है और यह 3,738.34 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रमुख बीमाकर्ताओं की स्थिति देखें तो स्टार हेल्थ ऐंड अलायड इंश्योरेंस का प्रीमियम सालाना आधार पर 22.5 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि केयर हेल्थ इंश्योरेंस का 34.22 प्रतिशत, निवा बूपा का अक्टूबर में प्रीमियम 66.55 प्रतिशत बढ़ा है।

नोमुरा के विश्लेषकों ने एक रिपोर्ट में कहा, 'एकल स्वास्थ्य बीमा की वृद्धि वापस लौटी (सालाना आधार पर 38.4 प्रतिशत) है। इसकी एक वजह 1/एन लेखांकन है। संभवतः खुदरा स्वास्थ्य योजनाओं पर वस्तु व सेवा कर न लगने का भी असर पड़ा और दबी मांग लौटी है।'

सितंबर में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमयम पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया था। उद्योग ने कर में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दे दिया, जिससे वहनीयता बढ़ी है। इस कदम से बिक्री में वृद्धि होने और आने वाले महीनों में बीमा की पैठ बढ़ने की संभावना है।

भारतीय जीवन बीमा एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने रिपोर्टिंग का प्रारूप बदला है और दीर्घावधि पॉलिसियों से मिले प्रीमियम की रिपोर्टिंग को बाहर कर दिया। यह 1 अक्टूबर 2024 सा लागू हुआ और 1 अक्टूबर 2025 से इसका असर खत्म होने का अनुमान लगाया गया था।

बहरहाल गैर जीवन बीमा प्रीमियम में 0.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज गई है औरइसका प्रीमियम 29,617.60 करोड़ रुपये रहा है। इसमें जनरल इंश्योरेंस, एकल स्वास्थ्य बीमा और स्पेशलाइज्ड पीएसयू बीमा शामिल होता है। आंकड़ों से पता चलता है कि जनरल इंश्योरेंस का प्रीमियम अक्टूबर में 25,464 करोड़ रुपये रहा है और इसमें सालाना आधार पर 1.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विशेषज्ञों ने कहा कि वाहनों की जीएसटी दरों में संशोधन से मल्टी लाइन सामान्य बीमा कंपनियां प्रभावित हुईं, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों के लिए बीमित राशि और मोटर बीमा प्रीमियम भी कम हो गया।

बीमाकर्ताओं में सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम में वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस के प्रीमियम में सालानाआधार पर 17.65 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वहीं यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस के प्रीमियम में 4.32 प्रतिशत सालाना वृद्धि हुई है। नैशनल इंश्योरेंस का प्रीमियम 14.10 प्रतिशत और ओरिएंटल इंश्योरेंस का प्रीमयम इस दौरान 0.92 प्रतिशत बढ़ा है।

निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में आईसीआईसीआई लोंबार्ड का प्रीमियम 16.30 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं बजाज आलियांज जनरल का प्रीमियम 50.5 प्रतिशत गिरा है। एचडीएफसी एर्गो का प्रीमियम भी सालाना आधार पर 14.97 प्रतिशत कम हुआ है।

जीवन बीमा का न्यू बिजनेस प्रीमियम 12 प्रतिशत बढ़ा

आतिरा वारियर
मुंबई, 10 नवंबर

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक जीवन बीमा कंपनियों के व्यक्तिगत और समूह बीमा का न्यू बिजनेस प्रीमियम अक्टूबर 2025 में सालाना आधार पर 12.06 प्रतिशत बढ़कर 34,006.9 करोड़ रुपये हो गया है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट के कारण इस महीने के दौरान पॉलिसियों की बिक्री में तेजी आई और प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई। अक्टूबर 2024 में कंपनियों का न्यू बिजनेस प्रीमियम 30,347.6 करोड़ रुपये था।

सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का प्रीमियम सालाना आधार पर 12.5 प्रतिशत बढ़कर 19,274.01 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं निजी जीवन बीमा कंपनियों का कुल मिलाकर प्रीमियम 11.5 प्रतिशत बढ़कर 14,732.9 करोड़ रुपये हो गया है।

कुल मिलाकर व्यक्तिगत बीमा खंड में सालाना आधार पर 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 12,932.5 करोड़ रुपये रहा। समूह बीमा खंड का प्रीमियम सालाना आधार पर 8.6 प्रतिशत बढ़कर 21,174.4 करोड़ रुपये रहा। समूह बीमा खंड में बाजार अग्रणी की अग्रणी बीमाकर्ता एलआईसी का प्रीमियम पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस महीने में सालाना आधार पर 7.8 प्रतिशत बढ़कर 14,470.5 करोड़ रुपये रहा। निजी क्षेत्र का प्रीमियम भी लगभग 10.3 प्रतिशत बढ़कर 6,703.92 करोड़ रुपये रहा। व्यक्तिगत बीमा खंड में एलआईसी ने 29.4 प्रतिशत सालाना वृद्धि दर्ज की है और अक्टूबर 2025 में उसका संग्रह 4,803.5 करोड़ रुपये रहा है।

निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 20.3 प्रतिशत बढ़कर 3,185.01 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 1.06 प्रतिशत बढ़कर 2,828.81 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमयम 6.5 प्रतिशत बढ़कर 1,773.2 करोड़ रुपये हो गया है।

बीएस सूडोकू 5433

9								
						7	2	
	7	1						6
					4	8		3
		5			1	2		9
6		9	5		2		3	
	1		7		9			
3	8		1					

परिणाम संख्या 5432

5	3	8	1	4	9	2	6	7
7	9	1	8	6	2	3	4	5
2	4	6	5	7	3	1	9	8
8	6	9	2	1	5	4	7	3
3	1	2	4	8	7	6	5	9
4	7	5	3	9	6	8	2	1
6	2	7	9	3	8	5	1	4
9	8	4	6	5	1	7	3	2
1	5	3	7	2	4	9	8	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

बहुत मुश्किल ★★★★★

क्षेत्रीय मंडियों के भाव | दिल्ली | उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,25,900 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। पिछले बाजार सत्र में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,24,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 2,460 रुपये बढ़कर 1,55,760 रुपये प्रति किलो (सभी करों सहित) हो गई। शुक्रवार को यह 1,53,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना 83.12 डॉलर या 2.08 प्रतिशत बढ़कर 4,082.84 डॉलर प्रति औंस हो गया जबकि हाजिर चांदी 3.30 प्रतिशत बढ़कर 49.93 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2650/2675 गेहूं शरबती 4200 /4300, चावल शरबती सेला 4100/ 4200, स्टीम 5000/5300, लालमती 5900/ 6200, चावल (सोना) 5300 /5400, दाल अरहर सवा नं. 9300/9500, पटका 10200/10700, रिजैक्शन 9000/ 9200, चना दाल 7100/7300 चना देशी छना 6700/6800, चना चापा छना 6800/ 6900, एग्रो प्योर बेसन 2750, मटर देशी 4000/4100, उड़द साबुत (काला) 8600/9900, दाल उड़द (काली) 9500/ 9800, उड़द धोया 9300/11000, मसूर छोटी 9000/10000, मलका 7800/ 8800, किरानाः जीरा 22700/24700, लालमिर्च गुंटूर 15000/23000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 7950/8000, धनिया एमपी 9500/13300, छोटी इलायची (किलो) 2450/3250, बड़ी इलायची 1770/1780, कालीमिर्च (किलो) 740/ 780, सुपारी (किलो) 485/550, सौंफ मोटी 13500/16500,

कानपुर
गेहूं 2650/2660 जौ 2300/2350, चावल मसूरी 3300/3400, चावल मोटा 3000 /3100, देशी चना 6100/6150, चना छना 6900/7100, दाल चना 7100/7300, देशी मटर 4200/4300, पिचकी 3100 /3200, मटर दाल 4500/4700, अरहर लेमन 7100/7125, दाल अरहर 10200 /11100, स्पेशल 9500/9700, उड़द एसक्यू 7900/7925, एफएक्यू 7175/ 7200 राजमा चित्रा 9500/11800, मूंग 6000/7300, मसूर छोटी 8800/9300, छांटी 9800/10500, सरसों 6500/6600, तिल सफेद 10600/10700, सोया (टीन) 2100/2160, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)2350/2500, सरसों खल 2650 /2700, पामोलिन 2200/2275, वनस्पति घी (यूपी एफओआर) 2000 /2125, मधुसूदन देशी घी 10200, वासुदेव 9900, परम प्रीमियम 10200, पदम श्री 10200, लीलाधर 10050, अलसी 7900/8000, धनियाः लोकल 9300 /9400, राजस्थान 9300/9600, बढ़िया 10100/13000, हल्दी 15000/16900, जीरा 22000/25000, अजवायन 13000/ 18000, मेथी 6200/6700, मखाना 700/1200, कालीमिर्च (किलो) 740/ 770, लालमिर्च (किलो) तेजा 180/230, (334) न. 150/170, 270

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो) : लड्डांडू 1600/1670, खुरपा 1480/1540, चाकू 1490/1640, रसकट 1500/1530, शक्कर 1600 /1610, चौरसा &, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली 4110, टिकोला 4100, देवबंद 4120, थाना भवन 4075, सिम्भावली 4120

हापुड़
गेहूं 2690/2695, चावल परमल 3450 /3500, डुप्लीकेट बासमती सेला 6000 /6100, बासमती 1121 स्टीम 8700 /8800, चना 5950/6000, चनादाल 7000/7300, काबली चना 7500/9000, राजमा देशी चित्रा 9300/10300, मटर 3850/3900, मटर दाल 3900/4000, अरहर लेमन 6850/6900, दाल अरहर 9500/10700, मसूर 9500/10200, उड़द देसी 6900/7100, दाल उड़द 9000/9500, धोया 10000/10500, मूंग यूपी 6200/6500, मूंग दाल 8500 /10000,

जयपुर
दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मूंग मोगर 8500/9000, मोटा 9400/9500, उड़द मोगर 9500/9500, मोटा 10000/ 10500, चौला मोगर 7500/7600, मोठ मोगर 7000/7500, मूंग दाल छिलका देशी 9200/10200, मलका 9000/9500, अरहर 9000/10700, मटर दाल 4000 /4100, चना दाल मीडियम 7100/7200, बोल्ड 7200/7300, दलहनः उड़द साबुत देशी 6900/7000,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)180, राइसब्रान (अखाद्य) 178, खल सरसों 2755, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1225, लाल &, कंटीन्यूअस 1230, सरसों (टन) 21500, सूरजमुखी (टन) 16800, गेहूं 2660/2670, आटा (50 किलो)1490, मैदा 1590, चोकर (45 किग्रा) 1200, चोकर (30 किग्रा) 780, मक्की बिहार 2250/2350 **भाषा/एनएनएस**

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 227

न्यायालय के भरोसे न रहें

अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में सुनवाई तेज कर दी है जिसमें अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर एकतरफा शुल्क लगाने के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अधिकार को चुनौती दी गई है। आमतौर पर न्यायालय लंबे समय तक सुनवाई करता है और गर्मियों में अपना निर्णय देता है। परंतु ऐसा लगता है कि इस मामले की सुनवाई जल्दी निपट जाएगी। पिछले सप्ताह न्यायालय में बहस का जो दौर चला उसमें उन वकीलों की स्थिति मजबूत नहीं दिख रही थी जो कार्यपालिका को शुल्क तय करने का अधिकार देने वाले 1977 की एक व्यवस्था का बचाव कर रहे थे। यह कहता है कि आपातकालीन व्यापार उपायों को विधायिका के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। संवैधानिक रूप से, शुल्क और सभी प्रकार के कर लगाने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के पास सुरक्षित है, लेकिन ट्रंप ने इस दशकों पुराने आपातकालीन अधिकार का उपयोग करके अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही व्यापार नीति को प्रभावी रूप से पलट दिया है।

विभिन्न वजहों से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के 9 न्यायाधीशों में से अधिकांश इस कदम को लेकर आशंकित हैं। इनमें से कई तो स्वयं ट्रंप द्वारा नियुक्त किए गए हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रपति, खुद भी थोड़े असहज नजर आ रहे हैं। रविवार को उन्होंने अपने सोशल नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर अपनी शुल्क नीति की आलोचना करने वालों को 'मूर्ख' घोषित किया जो यह नहीं मानते हैं कि अमेरिका अब दुनिया का 'सबसे अमीर, सबसे सम्मानित देश है जहां न के बराबर मुद्रास्फीति है और जिसके शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं।' उन्होंने यह भी कहा, 'केवल शुल्क के कारण ही अमेरिका में खूब कारोबार आ रहे हैं"। उन्होंने प्रश्न किया कि उनके वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय को यह बताया या नहीं।

अमेरिका में चल रहा यह आंतरिक विवाद जाहिर तौर पर शेष विश्व की रुचि का विषय है। खासतौर पर वे देश जहां की अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षा से अधिक शुल्क दर से बेहाल हैं। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि यूरोप समेत उनमें से कुछ इस बात से खुश होंगे कि असमान व्यापारिक रिश्ते और शुल्क थोपने की शक्ति राष्ट्रपति के हाथों से छिनकर वापस कांग्रेस के पास चली जाए जिसके साथ कम से कम लॉबीइंग की जा सकेगी और दबाव बनाया जा सकेगा। बहरहाल भारत इस चर्चा में एक खास मुकाम पर है।

हमारा देश उन देशों में शामिल है जिन पर सबसे अधिक शुल्क दर थोपी गई है। इसके अलावा भारत उन देशों में से एक है जो एक ऐसे व्यापार समझौते को लेकर ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं जो उन शुल्क दरों को घटाने या उनके प्रभाव को कम करने की इजाजत दे सके। ऐसे में यह संभव होगा कि अंतिम समझौते को टाल दिया जाए। इस उम्मीद में कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद शायद ऐसा कोई समझौता करने की जरूरत ही न पड़े। यदि समझौता हो भी जाता है तो यह लालच फिर भी रहेगा कि अगर न्यायालय का फैसला राष्ट्रपति के विरुद्ध गया तो कारोबारी रिश्ते पहले जैसे किए जा सकेंगे।

परंतु ऐसी उम्मीद करना सही नहीं है। तथ्य यह है कि न्यायाधीश कहीं के भी हों, वे राजनीतिक धारा के विरुद्ध जाने में कतराते हैं। खासकर तब जबकि मतदाता सत्ता के साथ हों। अगर वे ऐसा करते हैं, खासकर इस मामले में, तो उनको ऐसी कार्यपालिका से टकराना होगा जो अदालती फैसलों को हाशिए पर डालने में सक्षम है। अगर ट्रंप को आपात उपाय नहीं अपनाने को कहा जाता है तो भी लगता नहीं कि वे उन देशों पर पर व्यापार प्रतिबंध लगाने से पीछे हटेंगे जिनके बारे में वे मानते हैं कि उन्होंने अमेरिकी उदारता का फायदा उठाया है। भारत को वे खासतौर पर ऐसे देशों में शामिल करते हैं। उनके पास कानूनी विकल्प भी मौजूद हैं। शायद यह ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे न्यायाधीश जीत पाएं और भारत को भी उन पर दांव नहीं लगाना चाहिए।

अजय मोहंती

लोकलुभावन कदमों का जाल और उसकी कीमत

भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नीचे उप-राष्ट्रीय यानी राज्यों में राजकोषीय विचलन की गहराती दरार की अब अनदेखी नहीं की जा सकती है। बता रहे हैं अमरेंदु नंदी

बिहार के साथ ही चुनावों का एक अहम चक्र शुरू हो रहा है जो अगले दो साल तक चलेगा। इस दौरान 11 अन्य राज्यों में भी चुनाव होंगे। हमेशा की तरह चुनाव के पहले बंटने वाली 'रेवड़ी' और लोकलुभावन वादे इस दौरान सुर्खियों में रहेंगे। इससे भी ज्यादा अहम एक बात है जिस पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और वह है राज्यों के वित्तीय अनुशासन का क्षरण।

देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के तहत उप राष्ट्रीय राजकोषीय विचलन अब अनदेखी करने लायक नहीं रह गया है। प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद के प्रमाण लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते दो साल में आठ राज्यों के विधान सभा चुनावों से पहले 67,928 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं अब सामान्य हो चली हैं और इनकी मदद से अक्सर सत्ताधारी दल असंतोष से पार पाकर दोबारा चुनाव जीत जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चार कार्यकालों की सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद की और उसके मत प्रतिशत में 7.53 फीसदी का इजाफा हुआ। झारखंड में मैया सम्मान योजना भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के लिए उतनी ही कामयाब साबित हुई। पीआरएस की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि वर्ष 2024-25 में नौ राज्यों ने करीब एक लाख करोड़ रुपये की राशि महिलाओं को बिना शर्त नकदी हस्तांतरण के लिए आवंटित की। यह चुनावों से जुड़ा असाधारण राजकोषीय आवंटन था।

यह दलील दी जा सकती है कि इन वादों ने कल्याण और राजनीतिक संरक्षण के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। इससे राज्यों की वित्तीय व्यवस्था में लोकलुभावनवाद गहराई से शामिल हो गया। विकास अर्थशास्त्र भी बेहतर डिजाइन वाले सशर्त हस्तांतरणों का समर्थन करता है खासतौर पर महिलाओं के लिए। मुद्दा नकद हस्तांतरण नहीं बल्कि उनकी वर्तमान संरचना है जो अधिकतर बिना शर्त, सार्वभौमिक और लगभग स्थायी हो गई है। यह राजकोषीय दावों को स्थायी बनाती है और राज्यों के व्यय को उत्पादक निवेश से हटाकर बारंबार दी जाने वाली रियायतों की तरफ मोड़ देती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तथा राज्यों के बीच लोकलुभावनवाद की होड़ का यह चक्र राजकोषीय अपव्यय का आधार बढ़ाता रहता है।

नीति आयोग के राजस्व सेहत सूचकांक (एफएचआई) 2025 जिसने 18 बड़े राज्यों का राजकोषीय मानकों पर आकलन किया, वह इस मामले में एक अच्छी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संयुक्त ऋण-जीएसडीपी (राज्य का सकल घरेलू उत्पाद) अनुपात एक दशक पहले के 22 फीसदी से बढ़कर करीब 30 फीसदी हो गया है। ब्याज भुगतान का बोझ बढ़कर राजस्व प्राप्तियों के 21 फीसदी तक हो चुका है। पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और राजस्थान में ऋण अनुपात बढ़कर 38 से 46 फीसदी तक जा पहुंचा है। कई राज्यों में राजस्व प्राप्ति का आधा से ज्यादा हिस्सा तो ब्याज भुगतान में चला जाता है जिसकी वजह से निवेश के लिए गुंजाइश कम रह जाती है।

फिर भी ये सुर्खियां पूरी कहानी नहीं बतातीं। बजट के बाहर की उधारी और गारंटी चुपचाप बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र की बजट से इतर गारंटियां ही लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुकी हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे कई राज्य बिजली कंपनियों, सिंचाई निगमों, और परिवहन एजेंसियों के माध्यम से नियमित रूप से उधारी लेते हैं, जिससे ये दायित्व बहीखाते से बाहर रहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन तरह के दस्तूर को लेकर बार-बार चेतावनी दी है, और अनुमान लगाया है कि ऐसा छिपा हुआ कर्ज राज्यों के वास्तविक राजकोषीय घाटे में 0.5 से 1 फीसदी अंक तक की बढ़ोतरी कर सकता है। यह मौन संचय, जो अक्सर चुनावी लोकलुभावनवाद से प्रेरित होता है, राज्यों की राजकोषीय विश्वसनीयता को कमजोर करता है और स्थायी, पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकास की नींव को कमजोर करता है।

वित्तीय बाजार भी दबाव महसूस करने लगे हैं। बैंक राज्यों के बॉन्ड में मुख्य निवेशक हैं, लेकिन उन्होंने सीमित मांग दिखाई है और कई ऑक्शन में कम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। बैंक अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2.82 लाख करोड़ रुपये की उधार लेने की योजना बना रहे हैं। वहीं आपूर्ति पाइपलाइन भारी बनी हुई है जबकि मांग कम है और रुझानों में सतर्कता है। सितंबर के आरंभ में, 10-वर्षीय राज्य विकास ऋण (एसडीएल) और केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के बीच का अंतर बढ़कर 80–100 आधार अंक तक पहुंच गया जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक था। हालांकि कुल यील्ड बढ़ी है, लेकिन बाजार अब भी अच्छे और कमजोर उधारकर्ताओं में फर्क करने में जूझ रहा है। पंजाब और पश्चिम बंगाल, जिनका कर्ज क्रमशः जीएसडीपी के 47 फीसदी और 39 फीसदी से अधिक है, अब भी गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राजकोषीय रूप से मजबूत राज्यों (जहां यह अनुपात लगभग 19 फीसदी है) की तुलना में थोड़े ही अधिक दरों पर धन जुटा रहे हैं। समान नीलामी प्रारूप और रिजर्व बैंक की हस्तक्षेप नीति ने इस अंतर को कृत्रिम रूप से कम कर दिया है, जबकि बैंकों की निवेश सीमा ने वास्तविक मूल्य निर्धारण की गुंजाइश को सीमित कर दिया है। ऐसे माहौल में, राजकोषीय अनुशासन को कोई इनाम नहीं मिलता, और अव्यवस्था को कोई सजा नहीं, जिससे राज्यों के लिए सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है।

राज्यों की राजकोषीय विश्वसनीयता बहाल करना केवल वित्तीय संयम से संभव नहीं होगा। इसके लिए ऐसी संस्थाओं और तंत्रों की आवश्यकता होगी, जो आसान वादों की राजनीति का प्रतिरोध कर सकें। केंद्र सरकार को 'नो बेलआउट' संबंधी नियम के प्रति विश्वसनीय प्रतिबद्धता दिखानी होगी। जो राज्य संशोधित ऋण सीमा का उल्लंघन करें, उनके विवेकाधीन अनुदानों में स्वतः कटौती होना चाहिए। राज्य स्तर पर राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून को नए सिरे से डिजाइन करना होगा। ऐसे ढांचे के आधार पर जो ऋण स्थायित्व विश्लेषण पर केंद्रित हो, और जिसमें सभी संभावित दायित्वों, विकास अनुमानों, और ब्याज की प्रवृत्तियों को शामिल किया जाए न कि यह केवल सरल घाटा सीमाओं पर आधारित हो, जो अक्सर रचनात्मक लेखांकन को बढ़ावा देते हैं।

बाजारों को भी अनुशासनकारी भूमिका निभानी होगी। राज्य विकास ऋण की नीलामी में पारदर्शी जानकारी और वास्तविक मूल्य निर्धारण तंत्र होना चाहिए, ताकि निवेशक जोखिम की पहचान कर सकें न कि उसे सब्सिडी देने वाला बनाएं। पंद्रहवें वित्त आयोग के शर्त आधारित उधारी ढांचे को और मजबूत किया जाना चाहिए, और उन राज्यों के लिए स्पष्ट दंड निर्धारित किए जाने चाहिए जो लगातार राजस्व घाटा बनाए रखते हुए बिना शर्त हस्तांतरण योजनाओं का विस्तार करते हैं।

बहरहाल, अगर राजनीतिक प्रोत्साहनों की मूल संरचना जस की तस बनी रहती तो केवल संस्थागत सुधार पर्याप्त नहीं होंगे। सच तो यह है कि प्रतिस्पर्धात्मक लोकलुभावनवाद तब तक बना रहेगा, जब तक मतदाता लगातार हो रहे राजकोषीय अपव्यय की लागत को अंदरूनी रूप से नहीं समझते। जब चुनावी लोकलुभावनवाद के साथ राजकोषीय पारदर्शिता और मतदाता की विवेकशीलता जुड़ेगी, तभी भारत के राज्य रियायतों की बजाय सुशासन के आधार पर प्रतिस्पर्धा करेंगे।

(लेखक भारतीय प्रबंध संस्थान रांची में अर्थशास्त्र और लोकनीति विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

दूरसंचार क्षेत्र में समान व्यवहार से जुड़ा सवाल

पिछले सप्ताह की शुरुआत में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को वित्त वर्ष 2016-17 तक वोडाफोन आइडिया (वीआई) के एजीआर के मद में समूची बकाया रकम की नए सिरे से मूल्यांकन करने की अनुमति दी थी। यह 27 अक्टूबर को जारी किए गए उस आदेश का संशोधन था जिसमें केवल 9,450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। बाद के 3 नवंबर के आदेश ने संकट से घिरी दूरसंचार कंपनी के लिए राहत के दायरे को कई गुना बढ़ा दिया है। यह हमें इस सवाल की ओर ले जाता है कि केंद्र सरकार, (जिसकी वीआई में 49 फीसदी हिस्सेदारी है) अब क्या करेगी।

क्या सरकार 'जनहित' में इस कंपनी का एजीआर के मद में बकाया 83,400 करोड़ रुपये माफ कर देगी? क्या सरकार वित्तीय देनदारी के बदले में वीआई में अतिरिक्त हिस्सेदारी लेगी और आदित्य बिड़ला समूह और ब्रिटेन स्थित वोडाफोन के संयुक्त उद्यम वाली दूरसंचार कंपनी में बहुलांश अंशधारक बन जाएगी? इसके अलावा, सरकार भारती एयरटेल द्वारा 38,604 करोड़ रुपये के एजीआर बकाया पर राहत मांगने की याचिका से कैसे निपटेगी? अन्य प्रमुख दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो पर कोई एजीआर बकाया नहीं है क्योंकि इसने सितंबर 2016 में अपना संचालन शुरू किया था।

अगर सरकार दूरसंचार उद्योग में एकाधिकार की स्थिति रोकने के लिए कदम उठाती है, जिसमें वीआई को उसकी संचित देनदारियों पर राहत देना शामिल है, तो एक और सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है। क्या सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनियां, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) मिलकर दूरसंचार उद्योग को प्रतिस्पर्धी और दो कंपनियों के एकाधिकार से मुक्त बनाए रखने के लिए आवश्यक बैंडविड्थ उपलब्ध नहीं करा सकतीं?

सामयिक सवाल
निवेदिता मुखर्जी

30 सितंबर, 2025 तक निजी दूरसंचार कंपनियों के पास 92 फीसदी से अधिक बाजार हिस्सेदारी थी जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के पास शेष 8 फीसदी हिस्सेदारी थी।

जहां तक दो कंपनियों के एकाधिकार की बात है तो विमानन जैसे अन्य उपभोक्ता-उन्मुख क्षेत्रों में भी लगभग ऐसी स्थिति देखी जा रही है। मगर यह किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है।

एक दूरसंचार कंपनी के उपभोक्ताओं की संख्या (वीआई के मामले में लगभग 12.77 करोड़ वायरलेस/ब्रॉडबैंड ग्राहक) को अक्सर सरकार द्वारा किसी इकाई को चालू रखने के लिए उठाए गए उपायों के मुख्य कारणों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है लेकिन कुछ वर्षों से मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के लिए नंबर पोर्टेबिलिटी का विकल्प उपलब्ध रहा है। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं को एक बार में समाहित करना मुश्किल होगा।

इस बिंदु पर अगर सरकार जनहित में वीआई को राहत देती है और उसके प्रतिद्वंद्वी एयरटेल को नहीं देती है तो समान कारोबारी अवसर से जुड़े सवाल उठ सकते हैं। यहां तक कि बिना एजीआर बकाए वाली अन्य कंपनियां भी संचालन के किसी अन्य क्षेत्र में समान अवसर की मांग कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में।

सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का मामला लंबे समय से अटका हुआ है क्योंकि स्पेक्ट्रम आवंटन (किसे कितना मिलेगा और कैसे) अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि, हम जानते हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम वैश्विक व्यवहार के अनुरूप नीलामी के माध्यम से नहीं बल्कि प्रशासित आवंटन तंत्र के माध्यम से दिए जाएंगे। इस खंड में संभावित खिलाड़ियों के बीच विभाजन समान अवसर के सवाल पर फिर से उभर सकता है। पुरानी दूरसंचार कंपनियों (जो अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भी प्रवेश कर रही हैं) का तर्क यह रहा है कि उन्होंने 3जी, 4जी और 5जी सेवाओं में शामिल होने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं जबकि नई कंपनियां जैसे स्टारलिंक (ईलॉन मस्क द्वारा प्रचारित) या प्रोजेक्ट कुइपर (जेफ बेजोस द्वारा प्रचारित) के साथ ऐसी बात नहीं है। ये कंपनियां नए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के माध्यम से भारतीय बाजार में प्रवेश कर रही हैं। अगर मस्क और बेजोस की कंपनियां भारत में खुदरा दूरसंचार बाजार में उतरती हैं तो समान अवसर का सवाल निश्चित रूप से उठेगा।

तकनीक के क्षेत्र में ई-कॉमर्स पहले ही समान अवसर के दो पहलू देख चुका है। भारतीय ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए इन्वेंट्री-आधारित व्यवसाय की अनुमति है जबकि विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां केवल मार्केटप्लेस मॉडल का पालन कर सकती हैं। दोनों स्वरूपों में व्यवसाय करने के नियम बहुत अलग हैं और इस अंतर का कोई विशिष्ट कारण या तर्क नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि इन्वेंट्री बनाम मार्केटप्लेस पर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में चर्चा की जा रही है। सरकार द्वारा निर्यात के उद्देश्य से इन्वेंट्री-आधारित ऑनलाइन व्यवसाय में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति देने की संभावना है।

कुल मिलाकर नियमों की एकरूपता को लेकर सभी क्षेत्रों में एक मानक होना चाहिए। अलग-अलग नियम, चाहे वे दूरसंचार कंपनियों, खुदरा संस्थाओं या ऑनलाइन व्यवसायों में हों, हमेशा समान अवसर के सवालों को जन्म देंगे।

एक विशेष दूरसंचार कंपनी को राहत देने के लिए सरकार को अनुमति देने वाले उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश को सभी हितधारकों द्वारा सही भावना से लिया जाना चाहिए। यह सरकार को किसी निजी दूरसंचार कंपनी की वित्तीय देनदारियों को बट्टे खाते में डालने का न्यायालय का निर्देश नहीं है। इसके बजाय यह सरकार के लिए करों और शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक शुरुआती बिंदु हो सकता है ताकि दूरसंचार उद्योग भविष्य में बेहतर स्थिति में रहे।

आपका पक्ष

न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत और ट्रंप से मुकाबला

न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जोहरान ममदानी की जीत अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक बदलाव का संकेत है। ममदानी ने जिस तरह से मुफ्त परिवहन, सस्ती आवास योजनाएं और ट्रांसजेंडर अधिकारों जैसे मुद्दों को अपने अभियान का केंद्र बनाया, उसने शहरी मतदाताओं में नई ऊर्जा पैदा की। लेकिन यह जीत चुनौतीपूर्ण भी साबित हो सकती है, क्योंकि अब उनका सामना सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से है। ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि न्यूयॉर्क को संघीय सहयोग सीमित किया जा सकता है, जिससे शहर की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी। ट्रंप का यह रवैया राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित माना जा रहा है, लेकिन इसका खमियाजा न्यूयॉर्क के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। ममदानी को इस स्थिति में बेहद सावधानी से कदम बढ़ाने होंगे।

ऋषि सुभाष बुड़ावनवाला, रतलाम

न्यूयॉर्क के मेयर पद पर जीत के बाद मंगलवार को जोहरान ममदानी और उनकी पत्नी रमा दुवाजी

प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। औद्योगिक इकाइयों में आधुनिक उत्सर्जन नियंत्रण तकनीकें अपनाई जाएं। नवीकरणीय ऊर्जा से कोयले व पेट्रोल जैसे प्रदूषक ईंधनों का उपयोग घटाएं। इलेक्ट्रिक वाहनों और साइकल जैसे पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा दें। बड़े पैमाने पर पौधरोपण व शहरी हरित क्षेत्रों का विकास करें। जन जागरूकता से लोगों को कचरा जलाने व पटाखों के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करें। सरकार, उद्योग और नागरिकों के सहयोग से स्वच्छ तकनीकों द्वारा वायु प्रदूषण घटाया जा सकता है।

कृति जैन, बड़वानी

वायु प्रदूषण रोकने के उपायों का पालन सुनिश्चित हो

जनसंख्या घनत्व को देखते हुए पेड़ों को लगाना, शहरीकरण की रफ्तार को रोकना, गांवों को और उनके प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करना, कल कारखानों को सरकार के वायु प्रदूषण संबंधी नियमों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित कराने जैसे प्रमुख उपायों से वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को जागरूकता के माध्यम से रोकना आसान होगा। इसलिए स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी के पाठ्यक्रम में वायु प्रदूषण संबंधी पाठ्यक्रम शामिल करना और लोगों को इसके दुष्परिणामों से सचेत करना अत्यंत आवश्यक है।

डॉ अनुपम कुमार, जौनपुर

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग से घटेगा प्रदूषण

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, पौधे लगाना, पेड़ न काटना और कचरा न जलाना जैसे व्यक्तिगत महत्त्वपूर्ण उपाय हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, सौर ऊर्जा को अपनाना, और उद्योगों में फिल्टर लगाना भी आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग, साइकल चलाना या पैदल चलने जैसे विकल्पों का उपयोग करने से भी प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। होटलों में भट्ठियों का उपयोग बंद करके काफी हद तक वायु प्रदूषण पर काबू पा सकते हैं।

आशीष सकलेचा, जावरा

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंगोला की अपनी राजकीय यात्रा के तीसरे दिन वहां की संसद के सदस्यों को संबोधित किया। मुर्मू ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. एंटोनियो अगोस्तिन्हो नेटो के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा लुआंडा स्थित राष्ट्रीय सैन्य इतिहास संग्रहालय का भी दौरा किया। मुर्मू अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित इस देश की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं।

प्रेरणा

उत्साह भले ही परिणाम नहीं दिला पाए, यात्रा को खूबसूरत जरूर बना देता है। - मैट हेग

संपादकीय

सिर्फ गरीबी किसानों की आत्महत्या का कारण नहीं है

एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि 2023 में देश में खेती के व्यवसाय से जुड़े लोगों यानी किसान और खेतिहर मजदूरों में से 10,700 ने आत्महत्या की। इनमें भी 4690 किसान थे, जबकि 6096 खेतिहर मजदूर। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनमें सबसे ज्यादा मरने वालों का प्रतिशत महाराष्ट्र और कर्नाटक (क्रमशः 38.5 और 22.5) का है और सबसे कम एमपी और तमिलनाडु (क्रमशः 7.2 और 5.9) का। सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार- जिसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की मात्र 31% है- में कुल आत्महत्याओं का हिस्सा काफी कम है। इस राज्य में आधारभूत सुविधाओं का अभाव भी महाराष्ट्र या कर्नाटक के मुकाबले बहुत ज्यादा है, सामाजिक वैमनस्य भी जातिवाद के रूप में विद्यमान है और कानून-व्यवस्था भी अपेक्षाकृत खराब है। सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या के मामले संख्यात्मक रूप से भी महाराष्ट्र में दशकों से रहे हैं, जबकि शहरीकरण की दर भी बिहार के मुकाबले बेहद तेज रही है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, प्रशासन की गुणवत्ता भी बेहतर मानी जाती है और साक्षरता और शिक्षा का स्तर भी उत्तर भारत के बिहार और यूपी जैसे राज्यों से काफी अच्छा है। एनसीआरबी का मानना है कि आत्महत्या करने वाला हर तीसरा व्यक्ति पारिवारिक कलह के कारण यह कठोर कदम उठाता है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

दुर्गुणों का सामना करने के लिए हमें गुण-समूह चाहिए

हमारे जीवन पर अलग-अलग रास्तों से दुर्गुणों का आक्रमण होता है, तो हमें तैयारी भी उतनी ही तगड़ी करनी होगी। एक या दो गुणों से हम अनेक दुर्गुणों का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे भीतर गुण-समूह होने चाहिए। शिव जी ने गरुड़ जी से कहा- जाइ सुनहु तहं हरि गुन भूरी, होइहि मोह जनित दुःख दूरी। काकभुशुंडि जी के पास जाकर हरि के गुण-समूहों को सुनो, मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जाएगा। अब पहली बात तो ये कि भगवान भी गुण-समूह में विश्वास रखते हैं। छोटे-छोटे गुणों को धैर्य और निरंतरता से अपने भीतर स्थापित किया जा सकता है। यह समूह में गुण हों, ऐसा समय है। क्योंकि मोह से जब दुःख उत्पन्न होता है तो उसका सामना करने के लिए गुण-समूह चाहिए। और हम लगातार इसका प्रयास करते रहें कि जहां से भी, जो भी गुण हमको लगे कि ये अपनाया जा सकता है, तो अपना लें। अब जो समय आ रहा है, उसमें लगभग हर गतिविधि में एक दुर्गुण तो मिलेगा। तो क्यों ना अपने भीतर गुणों का समूह एकत्रित किया जाए। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • एनडीए के पास कोई और चेहरा नहीं है

भाजपा के लिए नीतीश कुमार आज भी 'जरूरी' क्यों हैं?

सियासत

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

'बिहार की मजबूरी है, नीतीश कुमार जरूरी है'- यह नारा मैंने सबसे पहले 2017 में भाजपा कार्यालय के बाहर सुना था, जब नीतीश ने 'अनगिनतवीं' बार पाला बदलने का फैसला किया था। वे लालू को छोड़ फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा में शामिल होकर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे। यह वापसी किसी पुरानी दोस्ती के अचानक जाग उठने से नहीं, बल्कि राजनीतिक सुविधा से प्रेरित थी। आठ साल बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। 2013 में मोदी की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को चुनौती देने वाले नीतीश से भाजपा को कोई विशेष प्रेम नहीं है। लेकिन एनडीए के चेहरे के रूप में उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं अपनी सियासी पारी के अंतिम पड़ाव पर मौजूद, उम्रदराज और अस्वस्थ नीतीश के पास भी अब कोई विकल्प नहीं, सिवाय इसके कि दिल्ली दरबार में अधीनस्थ की भूमिका स्वीकार लें।

बिहार अभी भी पिछड़ी जाति के वोटबैंक वाली राजनीति की विरासत से मुक्त नहीं हो पाया है। एक जमाने में करिश्माई नेता रहे लालू अब शारीरिक रूप से इतने कमजोर हैं कि चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाते। उन्होंने बेटे तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंप दी है, जो ऊर्जावान तो हैं, लेकिन उनमें पिता जैसे ठेठ गंवई अंदाज की कमी है। जेपी आंदोलन के शायद सबसे परिष्कृत उत्पाद नीतीश भी बीमार हैं और ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो शरीर से ज्यादा दिमाग को कमजोर करती है। भाजपा के पास केंद्र में मोदी जैसे कप्तान हैं, लेकिन राज्य में उसके पास ऐसा कोई नेता नहीं, जो पूरे सूबे में अपना प्रभाव रखता हो। कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर है और रातोंरात मजबूत नहीं हो सकती। फिर प्रशांत किशोर हैं, जो एक व्यवस्था-विरोधी चैलेंजर तो हैं, लेकिन अभी भी बिहार के जटिल जाति-मैट्रिक्स में अपनी जगह तलाश रहे हैं।

ऐसे में हम फिर उसी प्रश्न पर लौटते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार- जो रिकॉर्ड नौ बार शपथ ले चुके हैं- आज भी जरूरी माने जा रहे हैं? पांच साल पहले भाजपा ने चिराग पासवान को आगे कर नीतीश का कद घटाने और जेडीयू वोट बैंक को निशाना बनाने की कोशिश की थी। यह रणनीति कारगर भी रही। जेडीयू को 43 तो भाजपा को 74 सीटें मिलीं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने नीतीश की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने में हिचकिचाहट दिखाई। नीतीश भाजपा के इस पावर गेम को भांप गए। उन्हें अंदेशा था कि महाराष्ट्र में शिवसेना की तरह कमजोर होती उनकी पार्टी को भी भाजपा तोड़ देगी, इसलिए उन्होंने पाला बदला और इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। जब उन्हें लगा कि इंडिया उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को मजबूती नहीं दे पाएगा तो 2024 के आम चुनाव से पहले वे फिर से एनडीए में आ गए।

भाजपा कई अन्य राज्यों में सहयोगियों पर अपनी शर्तें थोपने में सफल रही है, लेकिन नीतीश पर वह ऐसा नहीं कर पाती है। इसका पहला कारण तो यह है कि हिंदी पट्टी के अन्य राज्यों के विपरीत भाजपा बिहार में पिछड़ी जाति का खुद का कोई भरोसेमंद नेतृत्व नहीं गढ़ पाई है। अगड़ी जातियों के प्रभुत्व का अतीत आज भी पार्टी पर मंडरा रहा है। 2015 में मोदी लहर के बावजूद भाजपा बिहार में लालू-नीतीश के साझा जातिगत समीकरण के सामने टिक नहीं पाई थी। दूसरे, आम चुनावों में भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का मतलब है कि पार्टी को अपने हर सहयोगी को समायोजित करना पड़ेगा। ऐसे में भाजपा नीतीश को अपने से अलग करने का जोखिम नहीं उठा सकती।

अंततः, भाजपा को पता है कि नीतीश के पास अब भी दो अंकों का मजबूत वोट-शेयर है। बिहार की प्रतिस्पर्धी गठबंधन-राजनीति में छोटा-सा वोट शेयर भी बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। 2020 के चुनावों में जेडीयू को निर्णायक 15 प्रतिशत वोट मिले थे। 2005 से लगभग हर चुनाव में दो प्रमुख समूह- महिलाएं और अति पिछड़ी जातियां आम तौर पर नीतीश के समर्थन में रही हैं।

भाजपा को पता है नीतीश के पास अब भी दो अंकों का मजबूत वोट-शेयर है। बिहार की प्रतिस्पर्धी गठबंधन राजनीति में छोटा-सा वोट शेयर भी बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। 2020 में जेडीयू को निर्णायक 15% वोट मिले थे।

2005 में पहली बार सत्ता संभालने वाले नीतीश के हाथों जिस स्कूली छात्रा ने साइकिल पाई होगी, वह आज एक वयस्क मतदाता है। आज भी वह सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रमुख लाभार्थी है। यही वह चीज है, जो नीतीश को बिहार की किसी भी सत्ता-व्यवस्था में अनिवार्य बना देती है। हो सकता है निकट भविष्य में भाजपा बिहार में भी एकनाथ शिंदे शैली का तख्तापलट करे, लेकिन अभी तो नीतीश भाजपा के लिए एक 'जरूरी मजबूरी' बने हुए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

दूरदृष्टि • नौजवान पीढ़ी की प्राथमिकताएं अलग हैं

एक नई राजनीति को गढ़ रहे हैं युवा और जेन-जी वोटर्स

युवामन

लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन
कश्मीर कोर के पूर्व कमांडर

न्यूयॉर्क से वर्जीनिया तक के चुनावों में युवा मतदाताओं द्वारा समावेशिता और नीति-आधारित राजनीति को अपनाना सांस्कृतिक विभाजन के दौर को चुनौती दे रहा है। जब जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीता तो इसके मायने एक स्थानीय चुनाव से कहीं अधिक थे। इसमें एक पीढ़ीगत बदलाव था- क्रोध-आधारित राजनीति से समावेशिता, सहानुभूति और सुशासन की ओर। इसने एक नई राजनीतिक ऊर्जा का संकेत दिया है।

अमेरिका में जेन-जी और युवा मिलेनियल्स चुनावी परिणामों को नए सिरे से गढ़ रहे हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि वे पार्टी और विचारधारा से कम, रोजमर्रा के मुद्दों से अधिक प्रभावित होते हैं- जैसे किराया दरें, छात्र ऋण, स्थिर वेतन और कॉस्ट ऑफ लिविंग। ममदानी ने अपने प्रचार-अभियान में इन चिंताओं पर बखूबी ध्यान दिया। इस पीढ़ी की मूल्य प्रणाली अलग है। इसमें दिखावे के बजाय प्रामाणिकता, बयानबाजी के बजाय सामाजिक न्याय और सहानुभूति शामिल है। नेपाल से बांग्लादेश और मेडागास्कर तक दुनिया के लोकतंत्रों में युवाओं में यही अंडर-करंट देखा जा रहा है- जहां वे पारदर्शिता, समावेशिता और निर्णय-निर्माण में भागीदारी मांग रहे हैं।

देखें तो ममदानी की जीत महज जनसांख्यिकीय से मिला फायदा नहीं, बल्कि एक ऐसे नेतृत्व की चाहत को दर्शाती है, जिसमें मूल्यों का समावेश हो। यह दिखाती है कि युवा वोटरों को सहानुभूति और डिलीवरी- दोनों की अपेक्षा रखने वालों के तौर पर देखा जाना चाहिए।

ये सच है कि बीते दशक में दुनिया दक्षिणपंथ की ओर झुकी दिखी है- लोकलुभावन राष्ट्रवाद, मजबूत नेताओं की राजनीति और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण। फिर भी 2025 में अनेक अमेरिकी चुनावों के परिणाम बताते हैं कि संतुलन का कांटा फिर केंद्र की ओर खिसक रहा है। मेयर से गवर्नरों के पद तक डेमोक्रेट्स ने कई प्रांतों और शहरों में जीत दर्ज की है। वर्जीनिया में भारतवंशी गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर चुनी गईं। गवर्नर पद पर भी डेमोक्रेट्स ने कब्जा जमाया। न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया में भी प्रगतिशील उम्मीदवार पकड़ मजबूत रखने में सफल हुए।

इस सब में जो बात उभरकर सामने आती है वह सिर्फ पार्टी प्रदर्शन नहीं, बल्कि उसके पीछे का पैटर्न है- समावेशी संदेश, युवा उम्मीदवार और आक्रोश के बजाय असल मुद्दों पर केंद्रित प्रचार। ये परिणाम संकेत देते हैं कि शहरी और उपनगरीय मतदाता तमाशे के बजाय वास्तविक मूल्यों को तरजीह दे रहे हैं।

इन परिणामों को स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हो-हल्ले, ध्रुवीकरण, पहचान संबंधी प्रतिशोध के नैरेटिव और सांस्कृतिक टकराव वाली राजनीतिक शैली का जवाब भी माना जा सकता है। विविधता वाले युवाओं से भरे न्यूयॉर्क जैसे शहरों के लिए तो यह व्याख्या तर्कपूर्ण लगती है। लेकिन अब भी इसे देशव्यापी जनादेश नहीं माना जा सकता। अमेरिकी राजनीति के संरचनात्मक विभाजनों को महज एक चुनाव नहीं मिटा सकता।

हां, ये परिणाम अपेक्षाओं और लहजे में आ रहे पीढ़ीगत बदलावों की शुरुआत को जरूर बताता है। विभाजनकारी भूख घटती दिख रही है और उद्देश्य और समावेशिता की खोज उसकी जगह ले रही है। लेकिन ये बदलाव सतत रहेगा या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि दोनों पार्टियां कैसे खुद को बदलती हैं और जेन-जी का जुड़ाव कितना टिकाऊ रहता है।

ममदानी की जीत की असली कहानी नेतृत्व में है। उनका प्रचार वैचारिक नाटकीयता नहीं, ठोस नीति पर केंद्रित रहा। इसने दिखाया कि आज की राजनीति में लाभ उनका होता है, जो भरोसे के साथ व्यावहारिक क्रियान्वयन को जोड़ सकते हैं। नस्ल और धर्म की सीमाओं से परे सामने आया उनका जुड़ाव न्यूयॉर्क के वोटरों की विविधता के अलावा उस पीढ़ी की परिपक्वता को भी बताता है, जो खुद को अलग-थलग मानने से इनकार करती है।

युवा वोटरों ने सियासत का नया ककहरा रचा है, जो सहानुभूति, व्यावहारिकता और वैश्विक जागरूकता से परिभाषित है। यह क्रांति से अधिक एक चेतावनी है कि राजनीति पहले शहरों में करवट लेती है, फिर इसकी गूंज बाहर फैलती है।

नेतृत्व की शांत, भागीदारीपूर्ण और नीति-आधारित यह शैली आने वाले वर्षों में शहरी शासन का मॉडल बना सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह मॉडल महानगरों से परे, उपनगरों और ग्रामीण अमेरिका तक भी फैल सकता है, जहां ट्रम्पवाद की अपील अब भी मजबूत है?

भारत के लोगों के लिए भी संकेत स्पष्ट है : युवा पीढ़ी हर जगह ऐसी राजनीति पर जोर दे रही है, जिसमें भागीदारी को दिखावे से ऊपर रखा जाता है। काठमांडू, ढाका, एंटानानारिवो हो या न्यूयॉर्क, युवा ऐसे नेता चाहते हैं- जो वास्तविक मुद्दों पर बात करें, वैचारिक हठधर्मिता पर नहीं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

दैनिक भास्कर — अब आप NYT के सभी आर्टिकल DB एप पर हर मंगलवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

© The New York Times

दैनिक भास्कर से विशेष अनुबंध के तहत

क्राइम

सऊदी अरब में 320 ड्रग तस्करों को इस वर्ष फांसी

इसामील नार

सऊदी अरब में नशीली ड्रग एंफीटेमाइन और हशीश की तस्करी के खिलाफ शाही सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। तस्करों के खिलाफ मौत की सजा के मामलों में उछाल आया है। सरकार ने बताया कि इस साल अब तक 320 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। युवराज मोहम्मद बिन सलमान द्वारा मृत्युदंड के मामलों में कमी का आश्वासन देने के बाद उसमें बढ़ोतरी हुई है। लंदन स्थित मानवाधिकार ग्रुप रिप्रीव के अनुसार इस वर्ष दो तिहाई मृत्युदंड ड्रग तस्करी से संबंधित हैं। सऊदी अधिकारियों की दलील है कि ड्रग तस्करों को कठोर सजा मिलना जरूरी है क्योंकि यह अपराध अनुदारवादी इस्लामी सोसायटी पर हमला है।

सऊदी अरब में मौत की सजा के मामलों पर नजर रखने वाले मानवाधिकार समूहों का कहना है, मिस्र, इथियोपिया, सोमालिया सहित अन्य देशों के गरीब विदेशियों को मौत की सजा ज्यादा दी जा रही है। अदालती दस्तावेजों से भी ये पता लगता है कि जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है, वे छोटे तस्कर हैं। उनका कहना है कि उनसे ड्रग्स की तस्करी जबरन कराई जा रही है। सऊदी अरब से निर्वासित वकील ताहा अल हाजी ने बताया कि ड्रग्स तस्करी के कई आरोपी तो ड्राइवर, मजदूर जैसे गरीब विदेशी नागरिक हैं।

© The New York Times

टेक्नोलॉजी • रिसर्च और अध्ययन बताते हैं, एआई टूल्स का सीधा संबंध कमजोर दिमागी परफार्मेंस से है

एआई चैटबॉट्स, सर्च टूल्स बन रहे हैं खतरा : ज्यादा इस्तेमाल से सोचने-समझने की शक्ति व याददाश्त कमजोर हो रही

ब्रायन एक्स चेन

टेक इंडस्ट्री बताती है कि चैटबॉट्स और नए एआई सर्च टूल्स से सीखने और आगे बढ़ने के तरीके बेहतर होंगे। लेकिन रिसर्च और कई अध्ययनों का कहना है कि एआई से हमारी सोचने-समझने की क्षमता कमजोर होती है। लिखने और रिसर्च जैसे कामों में चैटबॉट्स और एआई सर्च टूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर व्यक्ति उन लोगों से बदतर परफॉर्म करते हैं, जो उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं।

पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन कॉलेज में प्रोफेसर सिरी मेलुमैड की रिसर्च ने एआई से बौद्धिक क्षमता में गिरावट की जानकारी दी है। 250 लोगों को स्वस्थ जीवनशैली पर दोस्त को सलाह देने पर लिखने के लिए कहा गया। कुछ लोगों को परंपरागत गूगल सर्च का उपयोग करने की छूट दी गई। अन्य से गूगल एआई पर निर्भर रहने कहा गया। एआई उपयोग करने वाले लोगों ने सामान्य जानकारी दी- जैसे कि अच्छा खाइए, अधिक पानी पीएं और भरपूर नींद लें। लेकिन गूगल सर्च से जानकारी जुटाने वालों ने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य, वेलनेस से जुड़ी सटीक सलाह दी। डॉ मेलुमैड कहते हैं, मैं उन युवाओं के बारे में चिंतित हूं, जो परंपरागत गूगल सर्च करना नहीं जानते।

यह घटिया क्वालिटी के इंटरनेट कंटेंट से मानसिक स्थिति में गिरावट यानी ब्रेन रॉट (दिमाग की सड़न) का दौर है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन रॉट को 2024 का सबसे चर्चित शब्द घोषित किया है। सीखने और पढ़ने पर एआई के असर से विशेषज्ञों में बेचैनी बढ़ी है। रीडिंग में अमेरिकी बच्चों के पिछड़ने को इसका सबूत माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है, लिखने और सीखने के लिए चैटबॉट्स के इस्तेमाल करने वाले लोग पहले खुद लिखें। बाद में वे एआई टूल्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह मैथ्स के छात्र फार्मूला और समीकरण समझने के लिए पेंसिल, कागज पर लिखें। फिर कैलकुलेटर्स का उपयोग करें। गूगल और ओपनएआई ने रिसर्च के नतीजों पर टिप्पणी से इनकार कर दिया है। व्हार्टन के प्रोफसर डॉ मेलुमैड कहते हैं, एआई सर्च टूल्स आपके दिमाग की प्रक्रिया में बदलाव करते हैं। लिंक्स और क्लिक के जरिये सभी जानकारियां ऑटोमैटिक तरीके से मुहैया कराते हैं।

© The New York Times

एआई से दिमाग की गतिविधियां मंद हो रही

इस साल दिमाग पर एआई के प्रभावों पर सबसे अहम रिसर्च मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुई है। 54 कॉलेज छात्रों से 500-1000 शब्दों के निबंध लिखने के लिए कहा गया। चैटजीपीटी का इस्तेमाल करने वालों में दिमाग की गतिविधि सबसे कम पाई गई। लेख पूरा करने के एक मिनट बाद भी चैटजीपीटी यूजरों को अपने निबंध का एक वाक्य तक याद नहीं रहा। वहीं गूगल सर्च का उपयोग करने वाले छात्रों ने कुछ हिस्सों की जानकारी दी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाले लोगों को निबंध के ज्यादा वाक्य याद रहे।

अमेरिकी बच्चे पढ़ने और भाषाई ज्ञान में हो रहे हैं कमजोर

इस साल अमेरिका में आठवीं कक्षा और हाई स्कूल सहित अन्य बच्चों की पढ़ने की क्षमता बेहद निचले स्तर पर पहुंच गई है। शोधकर्ता चिंतित हैं कि सोच-विचार की कमजोर क्षमता और एआई, सोशल मीडिया के बीच सीधा संबंध है। बालरोग विशेषज्ञों की एक नई स्टडी में पाया गया कि रीडिंग, याददाश्त और भाषा के टेस्ट में बच्चों के कमजोर परफॉर्मेंस का कारण सोशल मीडिया है।

दूसरी ओर कई वकील एआई के झूठ की पोल खोलने में लगे

लॉस एंजिलिस के वकील रॉबट फ्रुएंड और कई अन्य वकील अदालतों में एआई के गलत इस्तेमाल को सामने ला रहे हैं। फ्रुएंड ने एआई की गलतियों का भंडाफोड़ करने के लिए ऑनलाइन डेटाबेस बनाया है। मुकदमों में फर्जी फैसलों का जिक्र होने लगा है। एआई धोखाधड़ी पर नजर रखने के लिए डेटाबेस बनाया गया है। फ्रुएंड सहित कई वकीलों ने एआई दुरुपयोग के 509 मामलों का पता लगाया है।

इस हफ्ते चर्चा में...

अमेरिकी कंपनियों को ट्रम्प ने और टैक्स छूट दी

8.86 लाख करोड़ रुपए
टैक्स छूट दी अमेरिकी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में। ये बिग ब्यूटीफुल बिल की 354 लाख करोड़ रु. की छूट के अलावा है।

44 हजार 345 करोड़ रुपए
का नया फंड बनाया गया है बेलेम ब्राजील में चल रहे विश्व जलवायु सम्मेलन में जंगलों को बचाने के लिए।

1 लाख 50 हजार जॉब
कम किए हैं अमेरिकी कंपनियों ने अक्टूबर माह में। यह पिछले साल के इसी माह से तीन गुना अधिक है।

अभियान

जज ने ट्रम्प विरोधी मुहिम चलाने के लिए पद छोड़ा

मैसाचुसेट्स फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज मार्क वोल्फ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर अपने विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अटलांटिक मैग्जीन में रविवार को प्रकाशित एक लेख में लोकतंत्र के अस्तित्व को खतरा होने की चेतावनी दी है। 78 वर्षीय जज वोल्फ ने लिखा कि ट्रम्प के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वे अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ट्रम्प अपने हितों के लिए कानून का उपयोग कर रहे हैं। वे अपने दोस्तों, दानदाताओं को जांच और संभावित सजा से बचा रहे हैं।

पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वोल्फ को जज नियुक्त किया था। वोल्फ ने बताया कि उन्होंने खुलकर अपने विचार जाहिर करने के लिए इस्तीफा दिया है। मैं अपने संघर्षरत साथी न्यायाधीशों का प्रवक्ता होने की भी उम्मीद करता हूं। पिछले कुछ महीनों में निचली अदालतों के न्यायाधीशों ने ट्रम्प के फैसलों के खिलाफ आदेश जारी किए हैं। ऐसे न्यायाधीशों पर ट्रम्प प्रशासन ने राजनीति करने का आरोप लगाया है। © The New York Times

ओपिनियन • वैश्विक कमाई में अमेरिकी फिल्मों की हिस्सेदारी 26% घट गई है

अमेरिकी फिल्मों, संगीत का प्रभाव अब कम हो रहा है

स्टीफन मार्शे

कभी दुनियाभर के टीनएजर्स के कमरे हॉलीवुड फिल्मों, माइकल जैक्सन और मैडोना के पोस्टरों से सजे रहते थे, पर अब हालात बदल रहे हैं। टीनएजर्स के रूम में अब ब्लैकपिंक, रोसालिया और चीनी पॉप बैंड्स की तस्वीरों को जगह मिलने लगी है। इससे पता चलता है कि अमेरिका की सांस्कृतिक ताकत घट रही है। दक्षिण कोरिया और चीन ने सरकारी नीतियों से अपनी संस्कृति को दुनिया में ब्रांड बना दिया है। के-पॉप, कोरियन ड्रामे, चीनी फिल्में और गेमिंग अब ग्लोबल यूथ की नई पहचान हैं। ट्रम्प सरकार की नीतियों और अमेरिकन कूल की फीकी पड़ती छवि ने अमेरिका के प्रभाव को कमजोर किया है।

टीनएजर्स चीनी और कोरियाई फिल्मों और गेम्स को पसंद कर रहे

शीत युद्ध के दौर में अमेरिका ने अपनी संस्कृति से दुनिया जीती थी। एल्विस प्रेस्ली के गाने, लिवाइस की जीन्स, हॉलीवुड की फिल्में और अमेरिकन ड्रीम ने आजादी और खुलेपन की नई परिभाषा दी थी। उस दौर में अमेरिकी संगीत और सिनेमा राजनीतिक हथियार से कम नहीं थे। लेकिन अब वही अमेरिका अपने ही विरोधाभासों में उलझ गया है। ट्रम्प सरकार की नीतियों और बंद सोच ने उसकी कूल छवि को नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ, दक्षिण कोरिया और चीन ने संस्कृति को नए दौर का निर्यात बना दिया है। सियोल में सरकार ने के-पॉप इंडस्ट्री को औद्योगिक क्षेत्र की तरह बढ़ावा दिया- नतीजा, ब्लैकपिंक और बीटीएस जैसे बैंड्स ने पूरी दुनिया में के-पॉप की दीवानगी फैला दी। कोरियन ड्रामे स्क्विड गेम जैसे शो ने पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स पर रिकॉर्ड तोड़े। वहीं चीन ने फिल्मों, एनीमेशन, गेमिंग और एप्स के जरिए युवाओं को जोड़ा। चीनी प्लेटफॉर्म्स और टेक ब्रांड्स अब मनोरंजन और फैशन के नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। आज हॉलीवुड की वैश्विक हिस्सेदारी 92% से घटकर 66% रह गई है। स्पॉटिफाई पर आधे से ज्यादा हिट कलाकार गैर-अंग्रेजी भाषी हैं। अब संस्कृति की सीमाएं खत्म हो गई हैं। नई पीढ़ी का कमरा अब सिर्फ अमेरिका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की झलक दिखाता है।

© The New York Times

असर • युद्धविराम से फर्क नहीं पड़ा

इजराइली विश्वविद्यालयों, बुद्धिजीवियों का यूरोप में अब भी हो रहा है बहिष्कार

एलिजाबेथ बुमिलर

पिछले माह गाजा में युद्धविराम के बावजूद कई यूरोपीय देशों में इजराइल के खिलाफ विरोध की हलचल चल रही है। यूरोपीय संस्थाओं में इजराइली विश्वविद्यालयों का बहिष्कार जारी है। कुछ दिन पहले यूरोपीय आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने 23 इजराइली विशेषज्ञों को एक वीडियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। शर्त रखी गई कि उन्हें पहचान छिपाना पड़ेगी। विरोध के बाद ये शर्त हटाई गई।

यूरोपीय विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का कहना है कि इजराइल का बहिष्कार जायज है। उसने गाजा में जनसंहार किया है। इजराइली विश्वविद्यालय देश की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ सहयोग करते हैं। बार्सिलोना यूनिवर्सिटी के राउल रामोस कहते हैं, इजराइली विश्वविद्यालयों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिलिस्तीनी लोगों को मारने के लिए होता है।

फिल्म इंडस्ट्री का भी बायकॉट

कुछ हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं और एक्टर्स ने इजराइली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बॉयकॉट कर रखा है। एक टास्क फोर्स ने मई में बताया कि उसने अकादमिक बॉयकॉट के 700 मामले दर्ज किए हैं। बेल्जियम, स्पेन, इटली, नीदरलैंड्स के ज्यादा विश्वविद्यालय बॉयकॉट कर रहे हैं।

© The New York Times